

सी० आइ० ए०

पर्दे के पीछे

दलजीत सेन अदल

प्रकाशक :

विजेन्द्र जैन

महामचिव, अखिल भारतीय विद्यार्थी कांग्रेस,
बी० ए०, रमेश नगर, नई दिल्ली-१५

मूल्य : पाँच रुपये

प्रथम संस्करण : पाँच हजार

मुद्रक :

पापनियर प्रिंटर्स,

२६१, फेज रोड, नई दिल्ली-५

प्रस्तावना

सी० आई० ए० का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। गुप्त रूप से काम करने वाली यह संस्था बहुत बदनाम हो चुकी है। यदि यह कहा जाये कि सी० आई० ए० ने एक प्रजातांत्रिक सरकार का तस्ता उल्टा दिया या एक पिटूरा सरकार को गद्दी पर बिठा दिया तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। चाहे एशिया हो या अफ्रीका या लतीनी अमरीका इस संस्था की घिनौना रूप अन्तर्राष्ट्रीय रंग मंच पर भी दिखाई देगा, कभी जनतन्त्र का खून करने में, कभी प्रगतिशील नीतियों का विरोध करने में या फिर षडयन्त्रकारी गतिविधियों द्वारा आजादी का हनन करने में ताकि लोगों के समाजवाद की ओर बढ़ते हुए साहसिक कदम डगमगां उठें, देश का आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाए, और लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं दबी की दबी रह जाए, इस दिशा में अमरीकी गुप्तचर संस्था सदैव अग्रणी रही है।

सी० आई० ए० उन क्षेत्रों में विद्यमान है जहां उपनिवेशवाद की जड़ें खोखली हो चुकी हैं और जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर राजनैतिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी है। प्रजातन्त्र की आड़ लेकर यह संस्था पैसे और हथियारों का प्रलोभन देकर, जहां २ सम्भव हों सके, सैनिक अड्डे कायम करना

चाहती है ताकि विश्व में युद्ध के बादल मंडराते रहें और छोटे २ राष्ट्रों को विवश कर दिया जाए कि वे सैनिक गुटबन्दी का शिकार बने रहे ।

सी० आई० ए० का मुख्य उद्देश्य है कि एकाधिकार बड़े, पूँजीवादी शक्तियां देश की आर्थिक नीति पर अपना प्रभुत्व जमा सकें और लगड़ा साम्राज्यवाद खड़ा रह सके । सी० आई० ए० एक विशुद्ध राजनैतिक संस्था ही नहीं बल्कि एक व्यापारिक संस्थान भी है । यह संस्था बड़े पैमाने पर पडयन्त्रकारी और विघटन सम्बन्धी कार्यों को बढ़ावा देती है । यह असल बात है कि इस संस्था को हर स्थान पर मुह की खानी पड़ी है ।

अमरीकी सरकार के विदेशी विभाग पर सी० आई० ए० का प्रभाव इतना अधिक बढ़ चुका है कि अमरीकी दूतावासों में सी० आई० ए० के अधिकारी प्रमुख स्थानों पर तैनात हैं । ये अधिकारी भवाछनीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं । ये अधिकारी किसी न किसी प्रकार विद्यार्थियों, युवकों और नागरिकों से सम्बन्ध बढ़ाकर उन्हें विघटनकारी कार्यों के लिए तैयार करके अपने ही देश के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं ।

इण्डोनेशिया में भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सुकर्णो, ईरान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री डाक्टर मुसद्दिक, घाना के भूतपूर्व राष्ट्रपति एनफूमा और कम्बोडिया के नारडोम सिहानुक के विरुद्ध पडयन्त्रों के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । बन्दूकों और टैंकों के बलबूते पर अधिक देर तक साम्राज्यवादी शक्तियां नहीं टिक सकती भले ही सी० आई० ए० कोई रूप धारण करके सामने आए । उसकी मित्रता प्रतिक्रियावादियों से हो या साम्प्रदायिक तत्वों से, उसकी गोद में एकाधिकार पलता हो या तस्करी करने वाला व्यापारी, ये सब आजादी के दुश्मन हैं ।

अतः आजादी के दीवानों को सजग और जागरूक रह कर अपने राष्ट्रीय गौरव, मान बर्मादा और प्रतिष्ठा के लिए सतत कार्यशील रहना चाहिये ताकि विध्वंसकारी और प्लायनवादी प्रवृत्तियां हमेशा के लिए कुचल दी जाएं । सी० आई० ए० का विरोध करने का मतलब है मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन करना ।

जहां लिंकन ने अमरीका की स्वतन्त्रता और एकता को अपने जीवन का लक्ष्य माना वहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए और विश्व के अन्य देशों को गुलामी

की जंजीरों से मुक्त कराने का भी प्रयास किया। भारतीय जनता को लिंकन की आजादी-प्रिय भावना से बहुत प्रेरणा मिली। यह सही है कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सफल होने तक अमरीकी जनता हमारी आजादी की लड़ाई का समर्थन करती रही और भारत के कई प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमरीका में रहकर भारत की हर प्रकार से सहायता करते रहे और उन्हें अमरीकी जनता का सहयोग भी मिलता रहा। स्वामी विवेका नन्द को अमरीका में अध्यात्मवाद की चर्चा करने के साथ-साथ यह भी अवसर प्राप्त हुआ था कि वह अमरीकी लोगों में भारत की आजादी के प्रति रुचि भी पैदा करते रहे थे। कौन नहीं जानता कि भारतीय क्रांतिकारी जापानी जहाज 'कामा-गाटा-मारो' को जब अमेरिका से भारत लाए थे तो उस जहाज में लगभग ४०,००० रायफलें और लाखों रुपये का गोना बारूद मौजूद था। यह था उस समय की जनता और सरकार का आजादी के साथ प्रेम। क्या ही अच्छा होता कि हमारे दोनों देशों के बीच आजादी और मित्रता के आधार पर सम्बन्ध बने रहते और दोनों देश मिलकर साम्राज्यवाद का विरोध करते परन्तु अमरीकी सरकार रास्ते से भटक गई और सी० आई० ए० जैसी संस्थाओं ने अमरीका के पुराने इतिहास को मिट्टी में मिला दिया और कुछ पूंजीपतियों के स्वार्थ की रक्षा के लिए छोटे छोटे राष्ट्रों का गला दबा दिया। आज अवस्था यह है कि अमरीका तथा लतीनी अमरीका में अमीरी और गरीबी का भेद जमीन व आस्मान की तरह बढ़ा है और इसके साथ-साथ काले और गिरे का अमानुषिक भेद भी बढ़ा है। इस भेद भाव को बढ़ाने में तथा इन्सान की इन्सान के खिलाफ नफ़रत को बढ़ावा देने में सी० आई० ए० शर्मनाक पड़यन्त्र रचती रही है।

भारत में सी० आई० ए० एक ओर तो दक्षिण पची फासिस्टों की सहायता करती है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और दूसरी ओर उग्र वाम पंथी फासिस्टों की सहायता करती है जो गांधी जी के चित्रों की एवं देश की संस्कृति की होली जलाते हैं। एक ओर तो एक से बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे कराए जाते हैं तो दूसरी ओर दूसरे से इन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में ताला बन्दी और हड़ताल कराई जाती है। देश की आर्थिक व्यवस्था को क्षीण बनाने के लिए ३०० करोड़ रुपये वार्षिक तस्करी सोने से भारतीय घरती पर आर्थिक हमला किया जाता है। इस प्रकार के 'सुनहरी हमलों' ने एशिया और अफ्रीका के कई छोटे-छोटे राष्ट्रों की आजादी का गला घोंटा है। अब एशिया और अफ्रीका की जनता सजग और जागरूक हो चुकी है इसलिए वह इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। अतः

उनका मुकाबला करने की शक्ति बढ़े, यह किताब इस दिशा में सहायक हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ ।

श्री दलजीत सेन अदल, जो एक अनुभवी कार्यकर्ता हैं, ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत होकर विद्यार्थियों एवं युवकों को चुनौती देते हुए कहा है कि 'सी० आई० ए० एक ऐसा घिनौना हथियार है जो स्वतन्त्रता-प्रिय देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है' जिन लोगों को अपने देश से प्रेम है और जिनकी रगों में स्वाभिमानी रक्त बहता है, और जो चान्दी के चन्द ठीकरो पर अपना ईमान नहीं बेच सकते, उन सब लोगों को एक जुट हो कर सी० आई० ए० का विरोध करने के लिए यह पुस्तक आह्वान देती है ।

नई दिल्ली ।

२४ अक्टूबर, १९७०

शशि भूषण '

ससद सदस्य

दो शब्द

न तो मैं अमरीका का विरोधी हूँ न अमरीकन लोगों का । मैं अब्राहीम लिंकन को आजादी का देवता मानता हूँ । इसलिए जब देखता हूँ कि निकट भविष्य में दुनिया के नक्शे पर अमरीका का नाम आते ही जन-साधारण यह सोचने पर विवश हो जाएगा कि अमरीका आजादी का संरक्षक नहीं अपितु आजादी का शत्रु है तो मुझे आभास होने लगता है कि इस महान देश के माथे पर लगा हुआ कलुषित दाग कभी मिट न सकेगा ।

अमरीका को इस प्रकार बदनाम करने की जिम्मेदारी सी० आई० ए० पर है जिसकी गतिविधियाँ किसी से छिपी हुई नहीं हैं । यह सही है कि अमरीकन सरकार की नीति का सब से तीव्र विरोध अमरीका में ही हुआ है, भले ही इस विरोध के उपलक्ष्य में कई नवयुवकों को अपनी जिन्दगी से हाथ धोने पड़े हों ।

भारतीय जनता स्वभाव से ही किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के हमेशा खिलाफ रही है इसलिए वे लोग जो शायद यह समझते हों कि सी० आई० ए० जैसी संस्थाओं के माध्यम से वे भारतीय जनता के विचारों में

परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल धोखे में हैं। विदेशी टुकड़ों पर मनुष्य तो शायद पल जाए, राष्ट्र नहीं पल सकते। उसकी अपनी मर्यादा होती है और मानवीय मूल्यों में अटल आस्था भी। कोई भी देश इससे वंचित नहीं रखा जा सकता।

मुझे इस बात की खुशी है कि सी० आई० ए० के काले कारनामों का विरोध अमरीका में बहुत तेजी के साथ हो रहा है और आम जनता को इस बात का पता लग गया है कि सी० आई० ए० पड्यन्त्रकारियों का टोला है और यदि इस संस्था का अस्तित्व न मिटाया गया तो उस महान देश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी।

इसलिए आवश्यक है कि सी० आई० ए० का पर्दा फाश किया जाए और यह पुस्तक भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

दलजीत सेन अटल

बी० ८६, रमेश नगर

नई दिल्ली-१५

२४ अक्तूबर, १९७०

अनुक्रमणिका

सी० आर्द० ए०	५
पीस कोर	१४
भारत में पीस कोर	२३
युवक मंच पर	४१
अन्य देशों में	६०
सी० आर्द० ए० और कम्बोडिया	६७
पाकिस्तान को हथियार देने की नीति	७२
फासिस्ट प्रवृत्तियां	८१
आजादी के शत्रु	८७
राजनैतिक दबाव की नीति	१०३
नया रूप पुरानी चालें	११७

अनुक्रमणिका

सी० घाई० ए०	५
पीस कोर	१४
भारत में पीस कोर	२३
युवक मंच पर	४१
अन्य देशों में	६०
सी० घाई० ए० और कम्बोडिया	६७
पाकिस्तान को हथियार देने की नीति	७२
फासिस्ट प्रवृत्तियाँ	८१
भाजादी के शत्रु	८७
राजनैतिक दबाव की नीति	१०३
नया रूप पुरानी चालें	११७

विश्व के अन्य विद्यार्थियों की भांति अमेरिका के विद्यार्थी भी बहुत नटखट निकले।

एक बहुत बड़ा राज जो कई वर्षों से छिपा हुआ था खोलने में कोई कसर न छोड़ी। समूचा अमेरिका स्तब्ध रह गया, लोगो ने दातों तसे उगली दवा ली। नेशनल स्टूडेंट्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने खुले आम इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी संस्था सी० आई० ए० के इशारे पर कई वर्षों से अन्य देशों के विद्यार्थियों और युवकों से तालमेल बढ़ाने का काम करती रही है। मित्रता के पदों के पीछे जासूसी का जाल किस प्रकार तेजी से फैलता रहा है यह घटना दुःखदायी भी है और रोमांचकारी भी।

मजे की बात तो यह है कि 'घर के भेदी ने लंका ढाह दी।' अमेरिकन गुप्तचर संस्था 'सी० आई० ए०' का राज अमेरिका की प्रमुख विद्यार्थी संस्था ने ही खोल दिया। सी० आई० ए० के अधिकारियों को मुंह छुपाना दूभर हो गया, काटो तो खून नहीं, लगे इधर उधर की हांकने और दिल ही दिल में सोचने लगे कि 'खुदा बचाए इन भल्लू जवानों से, सी० आई० ए० की कई वर्षों की कमाई मिट्टी में मिला दी।'।

पुरानी घटनाएँ एक-एक करके सामने आने लगी। हर चित्र धूमिल था, उस पर दाग थे। १९४७ में सी० आई० ए० का जन्म हुआ, उस समय साम्राज्यवाद की जड़ें खोखली हो चुकी थी। लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद की कोख से सी० आई० ए० का जन्म उसी प्रकार था जैसे 'शैतान का साहिब मोलाद' होना वर्षों की मन्नत मानने के बाद। द्वितीय महायुद्ध में हिटलर की पराजय से एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए बहादुर लोगों ने निश्चय कर लिया कि वे हर कुर्बानी देंगे क्योंकि 'आजादी तो बलिदान मांगती है।' आजादी के दीवानों के इस दृढ़ निश्चय को देखकर साम्राज्यवादी सटपटाने लगे और उनके राज्य की दीवारें

गिरने लगीं । एक-एक करके देश आजाद होते गये । विदेशी राज्य के स्थान पर स्वशासन नई आशाओं और आकांक्षाओं का सन्देश लेकर आगे बढ़ने लगा । बड़े-बड़े पूँजीपतियों के दिल दहल गये और उनकी मण्डियाँ प्रायः ठप्प होने लगीं । हिन्दुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य का साया उठ गया, मिस्र ने नई करबट ली, अफ्रीकी एशियाई देशों में चेतना की एक नई लहर उठ खड़ी हुई ।

यस क्या था एक ही चँली के चट्टे-बट्टे मिल गये । कुछ धर्म के नाम पर, कुछ उपराष्ट्रवादिता के नाम पर । उनके नाम भलग-भलग थे परन्तु काम एक था । उन्हीं का रूप बना अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर 'सी० आई० ए०' अर्थात् केन्द्रीय अमरीकी गुप्तचर संस्था ।

अफ्रीका और एशिया की धरती सजग और जागरूक हो जाए तो इसका सीधा परिणाम यह होगा कि शोषण की दीवारें गिर जाएगी, भूखी और नान जनता गुलामी की लोहे की जंजीरों को अपने खून की गर्मी से पिघला देगी । जब साम्राज्य-वादियों ने इस धुनौती को साकार होते देखा तो उनके हाथ-पाव फूलने लगे । उन्हें इस बात का आभास होने लगा कि 'लोग राष्ट्र शक्ति के स्रोत हैं, क्षीणता के स्रोतक नहीं' और वे अपने परिपक्व विचारों से राष्ट्र को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं । परन्तु साम्राज्यवादियों ने जनता की ओर उसी प्रकार हल किया जिस प्रकार 'जब गीदड़ की मौत आ जाये तो वह सरपट शहर की ओर दौड़ने लगता है ।'

सी० आई० ए० ने यही उचित समझा कि वह गोपनीय डंग से उन लोगों का गठन करे जो डालर के बदले अपना ईमान बेचने के आदी हो चुके थे । आजाद देशों में 'जय चन्दो और मीर जाफरो' को इकट्ठा करने का काम सी० आई० ए० के हवाले किया गया । इसनी बड़ी ज़िम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधे पर क्यों ली ? क्या उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वह बचपन से डकैत, प्रपची और खूनी है । लेकिन 'बदनाम न होगे तो क्या नाम न होगा' की होड़ लगाये हुए अमेरिका का गुप्तचर विभाग विध्वंसकारी कार्यों में संलग्न रहा ।

इतिहास के पन्ने उल्ट कर देखिए, किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए बाहर से फौजें नहीं आईं बल्कि चन्द मुट्ठी भर लोग व्यापारी बन कर आये, लश्करी के काम में निपुण थे इसलिए उसी देश के कुछ लोगों को अपना पिटू और दलाल बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे, और अन्तिम क्षणों तक 'जन सेवा' का दम भरते रहे । जब 'गीदड़ चिल्लाना' शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए कि मुगियों की

खैर नहीं।' भला कहां साम्राज्यवाद और कहां जन-कल्याण, कहां तस्करी और कहां देश भक्ति, कहां गंगू तेली और कहां राजा भोज ।

फिर भी प्रयास जारी रहा, आजादी को छीनने का, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का, लोगों की मान मर्यादा पर कुठाराघात करने का, आर्थिक दबाव डालकर, राजनैतिक कुचक्र चलाकर, ताकि एशिया और अफ्रीका की घरसी सिहर न उठे । शुरू-शुरू में सांस्कृतिक संस्थाओं को गांठा गया अहा धर्म और संस्कृति के नाम पर जनता को फुसलाना सरल था वहां प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी संस्थाओं की सहायता की जाने लगी । सी० आई० ए० अपने असली रूप में सामने आ गया उसके अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह में पूंजीवादी, प्रतिक्रियावादी, एकाधिपत्य वाले, शोषण करने, वाले सब मौजूद थे ।

नई-नई संस्थाएँ बनाई गईं राष्ट्रीय स्तर पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी । इन संस्थाओं का बाह्य रूप देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह संस्था देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है । इसका नाम भोला, परन्तु हाथ में भाला । केवल गौर से देखने पर ही पता लगेगा कि संस्था के काम और नाम में कोई सामंजस्य नहीं है । यदि आपने यह जानने का प्रयास किया कि इस संस्था को धन कहाँ से मिलता है ? तो आपको यह जानकर निराशा होगी कि जहाँ भामा शाह ने राणा प्रताप की धन से सहायता उस समय की जब वह पेट पर पत्थर बांध कर शत्रु का मुकाबला कर रहा था, वहाँ आधुनिक 'प्रताप' की सहायता भमरीकी 'भामा शाह' उस समय करता है जब अन्य लोग पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और उनका शोषण करना जरूरी हो ।

कैसी विडम्बना है ? अब्राहीम लिंकन और जेफरसन आजादी की सुरक्षा के लिए लड़े परन्तु उसी की ही सन्तान में कुछ लोग दूसरों की आजादी का दमन करने पर उतारू हैं ।

विद्यार्थी बर्ग स्वभाव से ही क्रियाशील और उतावला रहा है, उनकी इस प्रवृत्ति को बदलना असम्भव है । यही कारण है कि किसी प्रकार का पलोभन उनके स्वाभिमान को छीन नहीं सकता । शुरू-शुरू में उनके जिम्मे जो काम लगाया जाता है उसमें साहस झलकता है । उस नवयुवक की इस साहसिक प्रवृत्ति का दुरुपयोग करने के लिए सी० आई० ए० हर प्रकार के हथकण्डे प्रयोग में लाता है । लेकिन जब विद्यार्थी को इस बात का आभास हो जाता है कि किस प्रकार उसे

मालाकार बनाया जा रहा है तो वह धूल भर भी इसे सहन नहीं कर सकता, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और वह उस मायाबाल को तोड़ने के लिए भयोर हो जाता है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में अमेरिका की नेशनल स्टुडेंट्स एसोसिएशन ने सी० आई० ए० का भाण्डा चौराहे पर फोड़ने का धमक्य उत्साह किया। परिणाम स्वरूप हर कोने से भावाज उठी, अमेरिका के अन्दर भी और बाहर भी 'जो में घाता है तोड़ दूँ शीशा फरेब का'।

गुप्तचरों का टोला :

विदेशों से जो विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाते हैं उन पर सी० आई० ए० की कड़ी नजर रहती है। किसी न किसी बहाने उनसे सम्पर्क बढ़ाकर इस प्रकार साठ-गांठ की जाती है कि इस दोस्ती के बदले में उस विद्यार्थी से मह माशा की जाती है कि वह अपना दिल दिमाग सी० आई० ए० के पास गिरवी रख दे। गूढ़ सम्पर्क होने के तुरन्त बाद उसे गुप्तचरों के टोले में भर्ती कर लिया जाता है। उन विद्यार्थी को इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि जो काम उनके जिम्मे सौंपा गया है वह अहितकर नहीं है।

इस प्रकार भर्ती करने के बाद उसका पुनः 'नामकरण' किया जाता है क्योंकि इस नए नाम पर ही उसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह नए नामकरण के पश्चात् कोई 'ईगल' बन जाता है तो कोई 'पैन्पर' और इन नए कार्य के उपलक्ष में १० डालर से लेकर २० डालर तक जेब खर्च प्रति सप्ताह बांध दिया जाता है। इस जेब खर्च के बदले में उसे एक रसीद पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। रसीद लिखने का मतलब है अपनी मौत के चार्टर पर हस्ताक्षर करना। रसीद का डर दिखाकर उसे बाध्य किया जाता है कि वह सी० आई० ए० की इच्छानुसार कार्य करे। उसके इकार करने पर उसे धमकी दी जाती है कि यदि हस्ताक्षर वाली रसीद उसके देश की सरकार की भेज दी गई तो उसे मारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति से एक हुडी पर भी हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और पिछले दिनों यह आरोप लगाया गया कि इन्ही लोगों से निश्चित रूप में प्रण भी लिए गए हैं कि वे हर राज को गुप्त रखेंगे। इस प्रकार उसके चारों ओर जालूमी का जाल बुन दिया जाता है। परन्तु जब उसे इस बात का आभास होता है कि डालर के बदले उसे अपने ही देश से द्रोह करने के लिए तैयार किया जा रहा है तो उसकी भात्मा उसे विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है।

ठीक ऐसा ही हुआ जब नेशनल स्टुडेंट्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने व्हाईट हाउस की विशेष समिति के अध्यक्ष नीकोलास काजानविच से चर्चा करते हुए कहा कि विदेशों में शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य संस्थाओं को सी० आई० ए० से पर्याप्त धन राशि मिलती रही है इसलिए नहीं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो या धर्म की महत्ता बड़े परन्तु इसलिए कि हर देश में सी० आई० ए० के कुचक्रों का जाल बिछा दिया जाए ।

अमरीकी सेनेट की परराष्ट्र समिति के अध्यक्ष विलियम फुलब्राइट ने कांग्रेस के 'समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सी० आई० ए० पर आरोप लगाया कि यह संस्था अमेरिका की परराष्ट्र नीति पर निरन्तर दबाव डालती रही है । आपने इस बात की भी चर्चा की कि :

“शीत युद्ध से भयभीत होकर हमने सी० आई० ए० को इतनी छूट दे रखी है कि वह हमारी परराष्ट्र नीति का संचालन करती रहे ।”

आगे चलकर आपने चेतावनी दी कि :

“यदि शीघ्र ही कोई कदम न उठाया गया तो निकट भविष्य में इस संस्था के कुचक्रों का प्रभाव हमारे देश की गृह नीति पर भी पड़ेगा और उस समय स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा ।”

इसके साथ ही कांग्रेस को सुझाव देते हुए विलियम फुलब्राइट ने जोरदार शब्दों में कहा कि :

“तुरन्त ही सी० आई० ए० की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए” यहां यह बात उल्लेखनीय है कि फुलब्राइट द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का आज़ तक खण्डन नहीं हुआ, उनकी हर बात अक्षरशः सत्य निकली । इसका ज्वलन्त उदाहरण है भूतपूर्व राष्ट्रपति केनेडी की हत्या सम्बन्धी जाच में सी० आई० ए० का दबाव ताकि असलियत को छुपाया जा सके और केनेडी के हत्यारों को दण्ड न मिल सके । अमेरिकन विदेशी सेवा विभाग के अधिकारी स्मिथ सैमसन ने इस बात की पुष्टि की है कि : इण्डोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सुकर्णो का तख्ता उलटने में सी० आई० ए० का हाथ था और सुकर्णो के विरुद्ध किये जाने वाले प्रदर्शनों की रूप रेखा तैयार करने वाले सी० आई० ए० के प्रमुख अधिकारी थे । वह व्यक्ति जो कई वर्षों तक अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ता रहा और बहुत समय तक

राष्ट्रपति पद पर आसीन रहा उसे पदभ्युत करने के लिए अमेरिका ने धन-धान्य से पूरी सहायता की ।

इसी प्रकार बर्मा में कम्युनिस्ट-विरोधी चीनी गुरिल्लों की मदद सुक्रिया तीर पर सी० आई० ए० ने की । बर्मा सरकार ने जब इस पटव्यंत्र के लिए अमेरिका की भर्त्सना की तो बर्मा स्थित अमरीकी राजदूत ने आश्वासन दिया कि अमरीकी सरकार चीनी गुरिल्लों की सहायता नहीं कर रही है । यह आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा क्योंकि सी० आई० ए० की गतिविधियों में कोई परिवर्तन न आया ।

दक्षिण वियतनाम और दक्षिण कोरिया में भी इस प्रकार की कार्यवाहियाँ जारी हैं । दक्षिण वियतनाम और कोरिया, दक्षिण अमरीकी जासूसों का बड़ा बन चुका है । लेकिन इसके बावजूद वियतनाम और कोरिया की बहुदुर जनता के प्रदम्य उत्साह के आगे अमेरिकन वम्बारों को मुंह की खानी पड़ रही है । सैकड़ों अमरीकी हवाई जहाज गिराये जा चुके हैं । बाँसों में बाहद भरकर जिस मुस्तँदी के साथ वियतनाम की जनता हमलावरों पर टूट पड़ती है उससे यह जाहिर है कि तोपी और बन्दूकों के दहानों पर भी आजादी के सराने गाने वाले सेनानी पूरी शक्ति के साथ अमरीकी सैनिकों को नाकों चने खा सकते हैं ।

समुक्त राष्ट्र संघ में जब नीम-सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न उठा, तो यह विवरण प्राप्त हुआ कि सहायता प्राप्त करने वाली ३६५ संस्थाओं में से ३०० संस्थाओं को अमेरिका में सहायता प्राप्त होती है । यह सहायता भिन्न-भिन्न संस्थानों के माध्यम से दी जाती है और अधिकतर संस्थान तो ऐसे हैं जिनके पास जमा हुई धन राशि का कोई व्यौरा नहीं । न धन के आने का पता और न जाने का । जिस संस्थान के अधिकारी यह भी नहीं जानते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया या तो वे जान-बूझ कर बावसे बने बँटे हैं या वे स्वयं ही सी० आई० ए० की मशीनरी के पुर्जें हैं । अमरीका में जितने भी संस्थान बनाये जाते हैं या तो वे नीजि होते हैं और या फिर उन्हें 'गुप्त हान' देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है । इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गत कुछ वर्षों से कई ऐसे संस्थान बनाये गये हैं जिनका काम सी० आई० ए० के गुप्त कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 'दानियों' का लबादा पहन कर ऐसी संस्थाओं की सहायता करना है जो विध्वंसकारी और विघटनवादी कार्यों से संलग्न हों । जाहिर है कि नए संस्थान पर जागानी से शक नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी नीयत भी आए तो एक के

मदले अनेक संस्थानों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक बार तो प्रत्येक व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अमेरिका की इस 'उदारवादिता' की कोई सीमा भी है जहाँ तक धन के दत्तालों को सीमित रखा जा सकता हो।

सी० आई० ए० की नौव मुख्यतः इसीलिए रखी गई थी कि इस संस्था के माध्यम से 'साम्यवादी गतिविधियों' को अमेरिका में रोका जा सके। लेकिन यह तो केवल उसका बाह्य रूप था। अन्दर ही अन्दर गुप्तचर विभाग अपना जाल फैलाता रहा और इसने अपनी लपेट में अन्य देशों के कई व्यक्तियों को भी ले लिया। जब इसने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया तो सी० आई० ए० के एजेन्ट कई देशों में फैल चुके थे। सब से प्रथम, सी० आई० ए० की गतिविधियों के केन्द्र बने वे देश जिन्होंने थोड़ा समय हुआ आजादी प्राप्त की थी। पूँजीवादियों को हमेशा इस बात का डर रहा है कि आजादी मिलने के बाद शोषण के सब मार्ग बन्द हो सकते हैं। जब विदेशी कारोबार पर रोक लगेगी तो मण्डियों में पूँजीवादी व्यवस्था कायम न रह सकेगी। इसलिए वे शक्तियाँ जो शोषण पर ही पलती हैं आजादी के सूर्य का उदीयमान देखकर शोकानुर क्यों न हो? परिणामस्वरूप इस आजादी पर प्रहार करने के लिए साम्राज्यवादी दलाल दल-बल के साथ आर्थिक दरवाजे से घुसने को प्रयास करते हैं और जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अमुक सरकार शोषण के विरुद्ध है तो उसका तत्ता उल्टने के लिए पड्यन्त्र रचा जाता है। इसमें सहायता देती है स्थानीय पूँजीवादी व्यवस्था और उसकी रक्षा करने वाली संस्थाएं।

प्रजातन्त्र दोषारी तलवार है। इसका सही प्रयोग तो तभी होता है जब इसका विकास करते समय जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए। लेकिन इसका दुरुपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है कि देश-द्रोह करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी अवस्था में वह हर प्रगतिशील नीति का विरोध करता है और यह सब कुछ दूसरे के इशारे पर होता है। ऐसी संस्थाओं का जन्म होते देर नहीं लगती लेकिन इनका पतन भी उसी प्रकार शीघ्र ही होता है। सी० आई० ए० की यह टेक्नीक रही है कि जहाँ किसी संस्था में प्रवेश पाना कठिन हो वहाँ उसके मुकाबले में नई संस्था खड़ी कर दी जाये और इस संस्था के माध्यम से जन-जीवन में घुसपैठ की जाये। इस प्रकार के घुसपैठिये आपको कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक नाम रखने वाली संस्थाओं में भी मिलेंगे। इनका सम्बन्ध न तो साहित्य से होता है न संस्कृति से। लम्बे-लम्बे बाल रखकर साहित्यक बनने का दावा करेंगे, लम्बे-लम्बे

चोगे पहन कर योगी बनने का बहाना करेंगे, रोयेंगे तो संस्कृति के नाम पर, उनका हर आंसू मगरमच्छ का होगा, पर उनके शरीर के हर रोएं-रोएं से गंदारी की भावना टपकेगी, उनका हर वाक्य जहर में डूबा हुआ होगा। उनकी हर आवाज में मस्ती नहीं शरारत होगी, उनका हर काम विध्वंसकारी होगा। धर्म और संस्कृति के टुकेदार बनकर साम्प्रदायिकता को हवा देंगे झूठ बोलेंगे तो गोबल्लू को मात कर देंगे। और अफ़रातफ़री मचाने में हिटलर को भी परास्त कर देंगे।

लेकिन तब तक, जब तक चेतना का प्रहरी सोता है और उसके सजग और जागरूक होते ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। आम चुनावों में सी० आर्इ० ए० की विशेष दिलचस्पी रही है। जब फ़ास में चुनाव के समय प्रगतिशील सत्ताओं के जीतने की पूरी सम्भावना थी, तो सी० आर्इ० ए० ने ऐड़ी से चोटी का जोर लगाकर इस सफलता को पराजय में बदलने का भरसक प्रयास किया। १९४८ में जब ईटली साम्यवादी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था तो सी० आर्इ० ए० ने क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स की पूरी सौर पर सहायता की। चोर-चोर मौसेरे आर्इ० इकट्ठे हो गये। उनका उद्देश्य जनता की दुःख तकलीफ़ को दूर करना नहीं बल्कि चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकार की स्थापना करना था जो साम्राज्यवादी ताकतों का दुमछल्ला बन सके। उन सब प्रगतिशील व्यक्तियों का विरोध किया गया जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे। कैरो के विख्यात समाचार पत्र दैनिक "अल-अहराम" के अनुसार भारत में आम चुनाव के समय १९६२ में और १९६७ में सी० आर्इ० ए० ने भूतपूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को हराने के लिए लाखों रुपये खर्च किए।

जिस स्थान पर चुनाव के माध्यम से सी० आर्इ० ए० की पिछड़ी सरकार कायम नहीं हो सकती उन स्थानों पर ऐसा ढग अपनाया जाता है कि प्रगतिशील सरकार का तख़्ता उल्टा दिया जाये। गोटे माला के भूतपूर्व राष्ट्रपति आरबेन्स के खिलाफ़ ऐसा ही पडयन्त्र रचकर उसे गद्दी से हटाया गया। गायना के भूतपूर्व प्रधान मंत्री खेदी जगन के विरुद्ध भी ऐसा ही पडयन्त्र रचा गया और पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी को हराने का भरसक प्रयास किया गया। बहादुर लुमुम्बा की मौत भी इन्हीं के हाथों हुई। उगते हुए देशों के महान् नेताओं के खिलाफ़ सी० आर्इ० ए० की गतिविधियां न केवल शर्मनाक हैं परन्तु दुःखदायी भी।

१९६० में सी० आर्इ० ए० ने सिंगापुर के मनोनीत और विख्यात राजनीतिज्ञ को ३५ लाख डॉलर देकर खरीदना चाहा, परन्तु उनका यह प्रयास सफल न हो सका।

सी० आई० ए० की गतिविधियों का संचालन करने का केन्द्रीय कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है जिसमें लगभग १०,००० व्यक्ति कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त आशिक समय में कार्य करने वालों की संख्या भी कई हजार है। अन्य देशों में सी० आई० ए० का काम करने वालों की संख्या लगभग दो हजार है। मुख्यतः अमरीकी दूतावास के सूचना केन्द्र हर देश में इन कार्यवाहियों के केन्द्र हैं। हर देश में कार्यभार जिस व्यक्ति के जिम्मे सौंपा जाता है उसे हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त रहती हैं। आश्चर्य तो यह है कि सी० आई० ए० का अधिकारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखता है उसे डिप्लोमेट्स को मिलने वाली सब सुविधाएं प्राप्त हैं। यह व्यक्ति दूतावास का अधिकारी भी होता है और सी० आई० ए० का भी। ऐसी परिस्थिति में सांस्कृतिक आदान-प्रदान तो केवल डोंग है, इसकी आड़ में शिकार खेला जाता है जिससे लोगों के दिल दिमाग पर काबू पाया जा सके। कुछ लोग तो शराब और डालर के नशे में भले ही मस्त हो जाएं परन्तु आम जनता को इस बात का आभास है कि भुगी में रहने वाले इन्सान की भी मर्यादा हुआ करती है, भूखा इन्सान भी स्वाभिमानी हो सकता है, और फटे, पुराने कपड़े पहनने वाला राजाओं की चादर नोचने की जुर्रत कर सकता है। इसीलिए सी० आई० ए० के डालर किसी गरीब व्यक्ति की विद्रोही भावना को शान्त नहीं कर सकते, उसका ईमान नहीं खरीद सकते। इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को दौलत से लड़ाया गया तो उसने दौलत के ढेर को ठुकरा दिया। क्रांति की ज्वाला भड़की और बड़े-बड़े साम्राज्य घुटने टेकने पर मजबूर हो गए।

फिर भी यदि कोई अमरीकी उदारवादिता का ढंढोरा पीटने की सौगंध खाए हुए हो तो उसे भूलना नहीं चाहिये कि भूखे और नगे लोग पेट पर पत्थर बांधकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं।

यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि आम तौर पर प्रत्येक देश की यह कोशिश होती है कि वह अपने दूतावास के माध्यम से इस बात की जानकारी रखे कि अमुक नीति के बारे में उस देश की क्या प्रतिक्रिया है। जिसके फलस्वरूप उसे अपनी नीति निर्धारित करने में सावधानी बरतने की आसानी रहती है। परन्तु यदि यही दूतावास प्रतिक्रिया जानने के अतिरिक्त उस देश पर हावी होने का कुप्रयास करे तो यह राजनीति या कूटनीति नहीं बल्कि उस देश के खिलाफ षडयन्त्र है। कोई भी स्वाभिमानी देश अपने ही देश में ऐसे नागों को दूध नहीं पिला सकता।

इसलिए इन सफेद नागों से बचने की आवश्यकता है और खास तौर पर उस समय जब कि यही नाग छद्मवेश धारण करके स्थान-स्थान पर घूम रहे हों।

पीस कोर

कहा जाता है कि पीस कोर की स्थापना अफ्रीका, एशिया और लतीनी अमेरिका के विकासशील देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य को लेकर हुई थी। १९६० में पीस कोर का उद्घाटन करते हुए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति राबर्ट केनेडी ने कहा था :

“कम विकसित देशों को न केवल अमेरिका से आर्थिक सहायता एवं मशीनों की आवश्यकता है बल्कि इन देशों को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अमेरिका के विचार और उसके तौर-तरीके सही हैं।”

राबर्ट केनेडी ने आगे चलकर कहा :

“आर्थिक विकास के लिए अमरीकी कार्यकर्त्ताओं का इन कम-विकसित देशों में भेजा जाना आवश्यक है।”
(हेरल्ड ट्रिब्यून)

अमेरिका के एक अन्य समाचार पत्र “सेचरडे रिब्यू” में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जार्ज सोकोलस्की ने एक लेख में पीस कोर के वास्तविक उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि “क्या पीस कोर अपना कार्य कर सकती है ?” के शीर्षक के अन्तर्गत सुभाव देते हुए सोकोलस्की ने कहा है :

“निष्काम स्वयं सेवकों की कार्य कुशलता से ही हम उस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं जिससे जन-जीवन प्रफुल्लित हो सके और जन-साधारण अमेरिका की ओर उसी प्रकार देखे जिस प्रकार मुसलमान ‘अक्का’ की ओर इस आशा से देखते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ शान्ति और सन्तोष प्राप्त हो सकता है।”

कहने को तो पीस कोर निष्काम सेवा करने वाले कार्यकर्त्ताओं की टोली है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। पीस कोर की गतिविधियों से तंग आकर ही कई देशों में पीस कोर की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है। कुछ ही दिन हुए प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डार नायके ने पद ग्रहण करने के कुछ दिन बाद पीस कोर के २३ स्वयं सेवकों को श्री लंका से निकल जाने का आदेश दिया। श्री लंका में इन स्वयं सेवकों का यह अन्तिम टोला था जिसे निष्कासित कर दिया गया है। इस टोले के खिलाफ कई संगीन आरोप थे और हर व्यक्ति की ज़बान पर इस बात का चर्चा था कि पीस कोर के स्वयंसेवकों के माध्यम से ही श्री लंका की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बनाई जाती रही है ताकि आर्थिक बन्धनों में फंसा हुआ यह देश साम्राज्यवादी जंगल से निकल न सके।

पीस कोर की यह नीति रही है कि किसी भी देश की नीति उसकी अपनी राजधानी में निर्धारित न होकर वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हो। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तो यूँ समझिये कि उस देश की आजादी हमेशा-हमेशा के लिए गिरवी रखी जा रही है। यही कारण है कि पीस कोर के माध्यम से प्रतिक्रियावादी विचारों का प्रतिपादन किया जाता है।

अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के समय केनेडी ने १९५६ में सान् अन्टोनियो के स्थान पर मतदाताओं को सम्बोधित करते हुए पीसकोर की पहली बार चर्चा करते हुए कहा था कि पीस कोर जैसी संस्था को कायम करना ज़रूरी है। परिणामस्वरूप जब केनेडी ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया तो थोड़े समय बाद उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को अपने एक संदेश द्वारा पीसकोर बनाने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव पर विचार विनिमय के बाद पीस कोर की स्थापना का सुझाव स्वीकार कर लिया गया। सुझाव के पक्ष में सेनेट के ५६ सदस्यों ने वोट दिए और विपक्ष में ३२। हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में २८८ और ६७ के अनुपात से यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया।

बस नया था पीस कोर की नींव रख दी गई और उसके सर्व प्रथम निदेशक बने केनेडी के बहनोई सार्जेंट शिवर। इसके इलावा ३३ सदस्यों पर निर्धारित एक समिति का गठन भी किया गया जिसमें प्रमुख थे लिंडसन जानसन जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश विलियम ब्रगन्स।

कहने को तो पीस कोर एक स्वतन्त्र संगठन है परन्तु इसका संचालन व निर्देशन अमेरिकन गृह विभाग व सी० आई० ए० ही करता है। वाशिंगटन स्थित कार्यालय में पीस कोर के ७५५ अधिकारी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका और लतीनो अमेरिका में कार्य भार विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों के हवाले किया गया है। इस मस्या को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं ताकि पीस कोर का काम सुचारु रूप से चल सके। पीस कोर का काम भी धमरीकी दूतावास के माध्यम से किया जाता है और इसका प्रमुख अधिकारी भी सी० आई० ए० के प्रमुख अधिकारी की तरह दूतावास का भी अधिकारी होता है और उसे वह सब सुविधाएं प्राप्त हैं जो किसी भी अन्य डिप्लोमेट को प्राप्त होती हैं।

वाशिंगटन में पीस कोर कार्यालय एक विद्यालय भवन में स्थित है जहाँ अफ्रीका, एशिया और लतीनो अमेरिका के बड़े-बड़े मानचित्र दीवारों पर लटके रहते हैं। प्रत्येक विभाग अलग है और उसका प्रमुख अधिकारी भी अलग। सब आवश्यक कागजात उसी के पास रहते हैं और वही अपने विभाग का संचालन एवं निर्देशन करता है। पीस कोर में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति वैतनिक हैं। शुरु-शुरु में आंशिक रूप से जिनको भत्ता दिया जाता है उसमें अधिकांश विद्यार्थी होते हैं। थोड़े समय बाद उन्हें पूरे तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। उसका कारण यह है कि पीस कोर सी० आई० ए० का तरुण मोर्चा है। ऐसे कार्यों के लिए विद्यार्थियों और युवकों को विशेष तौर पर तरजीह दी जाती है, कारण यह कि विद्यार्थी और युवक किसी भी साहसिक कार्य करने से नहीं घबराते। शुरु-शुरु में तो इन युवकों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्यों बटोरा जा रहा है लेकिन जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि उन्हें अपने ही देश में उल्ट फेर करने के लिए तैयार किया जा रहा है तो उसमें विद्रोह की भाव तेज हो जाती है, फिर वह पीस कोर का नहीं क्रांतिकारी आन्दोलन का अग्रदूत बन जाता है।

आश्चर्य तो यह है कि पीस कोर के कार्य-क्रम को विस्तृत रूप देने वालों के लिए गोरी चमड़ी वालों को ही भर्ती नहीं किया जाता बल्कि अफ्रीका जैसे देशों में कार्य करने के लिए काले रंग वालों को भी भर्ती किया जाता है ताकि गुप्त कार्य करने में कोई बाधा न पड़ सके। इस प्रकार की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अमेरिका की रंग-भेद नीति पर पर्दा पड़ा रहे। क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिका में जहाँ-जहाँ रंग-भेद का प्रश्न उठा, काले लोगों पर 'खार कुत्ते छोड़े गए' अमेरिका में अब भी कई शिक्षा संस्थाओं में केवल गोरे रंग

के विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते हैं काले रंग वाले बच्चे पास भी नहीं फटक सकते । इन सब तथ्यों की मौजूदगी में पीस कोर एक मजाक बन गया है ।

जहाँ सी० आई० ए० रंग-भेद नीति को कायम रखने के लिए दक्षिणी रोडेसिया और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देता है वहाँ कहीं भी पीस कोर के कार्यकर्त्ताओं ने रंग-भेद नीति के विरोध में अपनी जुवान नहीं खोली ।

पीस कोर के निदेशक ने अफ्रीकी, एशियाई और सतीनी अमेरिका के देशों का दौरा करने के बाद अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा :

“अफ्रीका, एशिया और सतीनी अमेरिका में ऐसे पर्याप्त भवसर प्राप्त हैं कि इन देशों में वही घटना दुहराई जा सकती है जो फिलीपाईन्स में ५ हजार अमरीकी अध्यापकों के माध्यम से १९१० में घटित हुई थी (पर्याप्त इन देशों में गुलामी के बीज पुनः बोये जा सकते हैं ।)”

१९५५ के अमेरिकन बजट में म्यूचुअल सवयूरिटी पैक्ट के अन्तर्गत १५०० लाख डालर की वृहत् योजना स्वीकार की गई । इसके प्रतिरिक्त ६००० लाख डालर की राशि प्रशिक्षण कार्य के लिए निर्धारित की गई । सन् १९९४ तक कुल मिला कर दस हजार पीस कोर स्वयं सेवक विश्व के विभिन्न भागों में काम पर जुटे हुए थे और अनेक भारत में इनकी संख्या १४०० है । अमेरिका ने कुछ देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए समझौता कर रखा है और उसी के अन्तर्गत पीस कोर के स्वयं सेवक उन देशों में तैनात किए जाते हैं । इनमें से कुछ स्वयं सेवक थोड़ा बहुत जनसेवा का कार्य तो अवश्य करते हैं लेकिन उनकी संख्या नहीं के बराबर है । अधिकतर स्वयं सेवक जासूसी का काम करते हैं और जैसे कैसे वे सब जानकारी प्राप्त करते हैं जिनसे उनके मालिक प्रसन्न रहें और जासूसी का काम चलता रहे । भोले भाले लोगों को गोरी चमड़ी वाली नारियों के मोहपाश में उलझाने का भरसक प्रयास किया जाता है और कहीं-कहीं तो पीले वस्त्र धारण किए हुए अमेरिकन साधु लोगों को चक्र में फंसाने का विफल प्रयास भी करते हैं । उनके शरीर पर शिखर दुपहरी में बदन से चिपका हुआ वस्त्र उनके भोलेपन की निशानी तो जरूर है परन्तु उनकी कूटनीति का परिचायक भी । गले में मोटे-मोटे रुद्राक्षों की माला पहनकर अमेरिकन देवियां लोगों को वशीभूत करने के लिए सड़क के चक्कर काटती दिखाई देंगी । ऐसा लगता है कि वशीकरण ही उनका मूल मंत्र हो । उनके लिए न कुछ उचित है न अनुचित । जैसे तैसे काम चलता रहे यही उनका उद्देश्य

होता है। ये लोग साम्राज्यवाद के दलाल बन कर जगह-जगह घूमते हुए दिखाई देंगे। इनका बाह्य रूप कुछ और है और भान्तरिक रूप कुछ और। बगल में खुरी है तो मुँह में राम राम। रंग भले ही सफेद हो लेकिन मन कलुषित। भ्रन्दाज और सलीका घासकाना जरूर है लेकिन काम घिनौना। खुश बचाए इन लोगों से जो बड़े-बड़े शहरों में रोमियो-ड्रिलिंग बन घूमते हैं। यदि आप किसी ऐसे छद्मवेषी व्यक्ति को देख लें तो समझ लीजिए कि पुरानी घाराब नई बोतली में हाज़िर है। साम्राज्यवादियों के इस नए हथकण्डे से जन-साधारण सजग है और यही कारण है कि जहाँ एक बार यह हथकण्डा अपना लिया गया वहाँ आँच पर काठ की हांड़ी दुबारा नहीं चढ़ सकी।

अमेरिका की आजादी का इतिहास साक्षी है कि अमेरिकन लोगों ने वर्तानी साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया। यातनाएं भी सहन कीं परन्तु सब तक चैन से न बैठे जब तक कि ब्रिटिश साम्राज्य का बिस्तर गोल न कर दिया। परन्तु आश्चर्य की बात है कि उसी देश के भाषे पर एक कलुषित दाग इस बात का भी लगा रहे कि बीसवीं शताब्दी में जब जन साधारण आजादी के लिए अघोर हो तो अमेरिकन फौज आजादी की इस भावना को दबाने के लिए बम, गोले और म्यूकें लेकर असह्य जनता पर टूट पड़े। आखिर क्या तक मुसामी के ये कीड़े पलते रहेंगे। कब तक जनता की भावनाओं की अक्हेलना करने का दुसाहस जारी रहेगा। कब तक संगीन बी नोकों से निहुर्ये लोगों के सोने छलनी होते रहेंगे। हीरोशीमा और नागा साकी पर बम बरसाने के बाद अमेरिका अपना सिर गर्व से कैसे ऊंचा कर सकता है? हजारों लोग जो परमाणु बम का कोप भाजन बने उनकी भटकती हुई आत्माएं किस प्रकार अमेरिका निवासियों को चैन से बैठने देंगी। सम्भवतः बदले की भावना पुनः जागृत हो चुकी है और यही कारण है कि अमेरिका के नौजवानों ने अपनी सरकार की जंगबाज नीती का तीव्र विरोध करने के लिए विशाल प्रदर्शनों का सहारा लिया है। कम्बोडिया में सी० आई० ए० के पट्टयन्त्र के विरोध में अमेरिका में जितने प्रदर्शन हुए वे इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक पीढ़ी अमेरिकन सरकार की नीतियों से परेशान है। कोई कालेज या विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ विद्यार्थियों की आवाज़ अमेरिकन सरकार की बबरता के खिलाफ न उठी हो। भले ही इस महान् कार्य में नन्हें मुन्हें अमेरिकन युवकों को बोली का निशाना बनना पड़ा हो। लेकिन नवयुवकों का अदम्य उत्साह प्रशंसनीय था और उसके सामने हजारों लाखों सिर श्रद्धा से झुक गए।

दक्षिण वियतनाम में आजादी के दीवानों की सड़ाई विश्व के इतिहास में अपना अनोखा स्थान बनाए हुए है। यह ठीक है कि अमेरिकन साम्राज्यवाद कभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भ्रम नहीं रहा है और इसका विशेष कारण यह था क्योंकि ब्रिटन नहीं चाहता था कि उनकी साम्राज्यवादी भविष्यों में कोई अन्य साम्राज्यवादी प्रवेश पा सके। दो साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक मन्तव्य रखते हुए भी आपस में ईर्ष्या और द्वेष रखती थीं। लेकिन जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो ब्रिटिश मिशनरी तो सही रास्ते पर आने लगे परन्तु अमेरिकन मिशनरियों ने अपना प्रसंगी रूप दिखाना शुरू किया। ये लोग अमरीकी उदारवादिता के गुण गाने लगे और इन्होंने सतत इस बात का प्रयास किया कि लोग अमरीकी संस्कृति और सभ्यता के पुजारी बन जाए। शायद उन्हें कुछ सफलता भी मिल जाती परन्तु अमेरिका में साम्राज्यवादियों की जड़े इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि इन्होंने दूसरे देशों की आजादी पर पैदाएँ हमले करने शुरू कर दिए। लोगों का सही दंग से अमेरिकन उदारवादिता के दिग्दर्शन होने शुरू हो गए। रही सही कसर सी० आई० ए० और उसकी सहायक एंजिनियों ने पूरी कर दी। अमेरिकन दलालों का यही काम रहा है कि वे भारत को एक भिखारी के रूप में पेश करते रहें और अमेरिका का उदारवादी देश के रूप में। परन्तु वे भूल जाते हैं कि भारतीय जनता अमेरिका सी भीख नहीं बल्कि स्पष्टवादिता की मांग करती है। वह स्वाभिमान के दायरे में चट्टान की तरह मजबूत है।

गत वर्षों में पीस कोर की गतिविधियों के विरोध में पेरू, कोलम्बिया, क्यूबा और अर्जेंटीना में कई विशाल प्रदर्शन हुए हैं जहाँ यह मांग की गई है कि पीस कोर की गतिविधियों पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाया जाए। कई देशों से पीस कोर के स्वयं सेवक निष्कापित किए जा चुके हैं। अन्य स्थानों में भी यही मांग की जा रही है। पिछले दिनों कोलम्बिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने डोमिनिकन गृह-युद्ध में पीस कोर के हस्तक्षेप की तीव्र भर्त्सना की। अफ्रीका के कई देशों में भी प्रचण्ड प्रदर्शन हुए। उन सबका उद्देश्य एक था कि पीस कोर का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए।

पुरानी रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ कर अफ्रीका प्रगति के पथ पर अग्रसर है। परन्तु फिर भी पीस कोर वाले पुरानी लकीर को ही पीटते जा रहे हैं और निरन्तर इस कोशिश में रहते हैं कि प्रगति के पथ पर अफ्रीकी देशों के बढ़ते हुए चरण रुक जाएं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सी० आई० ए० वाले काले रंग वाले लोगों को अपने जामूसी के जाल में फँसाने की कोशिश करते रहते हैं।

वाले मजदूरों की यूनियन को भी फांसने की कोशिश की परन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय बन्दरगाह कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इस तथ्य की जांच की जाए कि सी० आई० ए० द्वारा मजदूर संगठनों को कितनी धनराशि दी गई है।

इसी प्रकार पाकिस्तान के भूतपूर्व वित्त मंत्री मोहम्मद शोभाव पर ब्रिटेन के एक समाचार पत्र में आरोप लगाया गया कि इसी मंत्री महोदय की सेवाएँ सी० आई० ए० ने पाकिस्तान सरकार का तख्ता उलटने के लिए प्राप्त की थी। यह समाचार सितम्बर १९५५ में दैनिक समाचार पत्र 'डेली टेलीग्राफ' में प्रकाशित हुआ था जिसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि शोभाव के माध्यम से अमरीकी सरकार ने अय्यूब सरकार को घमकी दी थी कि यदि भूतपूर्व राष्ट्रपति अय्यूब खां ने सोवियत रुस के प्रति कड़ा रुख न अपनाया तो पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी जाएगी।

५ जून १९६७ को भारतीय ससद में चर्चा करने हुए कुछ ससद सदस्यों ने सी० आई० ए० पर आरोप लगाया कि वह भारतीय समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता दे रही है ताकि इन समाचार पत्रों में छपने वाले लेखों को नए ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। निश्चय ही यदि कुछ समाचार पत्र किसी अमुक नीति का समर्थन करना शुरू कर दें तो वातावरण में काफी परिवर्तन आ सकता है। यही कारण है कि कई बार तो यह भी देखने में आया है कि हिन्दुस्तानी ज़बान में छपने वाले कुछ समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेख मिलते-जुलते थे। हो सकता है कि इन लेखों को लिखने वाला सी० आई० ए० का ही प्रमुख अधिकारी हो। इसके अतिरिक्त सी० आई० ए० की यह भी कोशिश रहती है कि पत्रकारों से भी सीधा सम्पर्क बढ़ा कर उन्हें इस कार्य में भागीदार बनाया जा सके। जिन पत्रकारों की लेखनी में बल है उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि वे यदि एक पुस्तक का अनुवाद कर पायें तो उन्हें प्रति पृष्ठ २० या २५ रुपये मिल सकते हैं। इस प्रकार बड़ी-बड़ी धनराशि देने का प्रलोभन देकर उन्हें फुसलाने का भी प्रयास किया जाता रहा है। अलग बात है कि हमारे देश के पत्रकार स्वाभिमानी हैं और वे खरीदे नहीं जा सकते। कुछ वर्षों हुए ऐसे ही स्वाभिमानी पत्रकारों ने अपनी संस्था से अनुरोध किया था कि अमरीकी दूतावास के सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों से तालमेल बढ़ाने के इस रवैया के खिलाफ आवाज उठाई जाए।

भारतीय संसद में एक पत्रिका 'क्वेस्ट' की खर्चा करते हुए मांग की गई थी कि भारत सरकार इस विषय की पूर्ण जांच पड़ताल करे कि सी० आई० ए० के माध्यम से किन-किन समाचार पत्रों की धन से सहायता की गई है। वास्तव में सी० आई० ए० का काम जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही तेजी से उनका पतन भी हुआ है। कारण यह कि हर चीज की सीमा होती है और यदि कोई उस सीमा को लाघने की कोशिश करे तो परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हो जाती हैं। न घालाकी साथ देती है, न भवकारी। एक-एक करके प्रत्येक राज सामने आ जाता है, चाहे उसको छुपाने का कितना भी प्रयास क्यों न किया गया हो।

आइये ! अब देखें कि युवक आन्दोलन इन गतिविधियों को किस प्रकार देखता है। किस प्रकार विश्व युवक आन्दोलन धन के दलालों का विरोध करता है। कौन सी शक्तियां प्रगतिशील विचारों का समर्थन करती हैं और कौन सी संस्थाएं रुढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट मनोवृत्ति का शिकार हैं। जन-विरोधी भावनाओं का प्रतिपादन करने वाला जनता का हितैषी नहीं, तो किसका हितैषी है ? क्या कारण है कि आज का नवयुवक सजग और जागरूक हो चुका है ? किसने उसकी सोई हुई चेतना शक्ति को जगा दिया है और वह क्यों आधुनिक संसार का इतिहास पुनः लिखने के लिए अधीर है ? उसे प्रश्न नहीं, प्रश्नों का उत्तर चाहिए क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता है। नवयुवक कठिनाईयों से लोहा ले सकता है। यही कारण है कि संसार में युवक आन्दोलन की भूमिका लिखने वालों के सामने भविष्य की रूप रेखा सदैव नाचती रही है। आओ देखें कि इन परिस्थितियों में युवक क्या सोचता है ?

भारत में पीस कोर

भारत में पीस कोर के कार्यकर्ता काश्मीर के प्रश्न पर इतने अधिक

चिंतित हैं कि यदि उनमें से कोई भी आपको इस विषय पर बात

करता मिल जाए तो आप सरलता से इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह अपनी जुवान से किस के मुंह की बात बोल रहा है और कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है।

जब भारत में आम चुनाव के पश्चात् संसद का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ तो उसमें सी० आई० ए० के बारे में चर्चा के दौरान कई राज सांने आए। संसद में यह आरोप लगाया गया कि अमरीकी दूतावास का कौंसिलर मिनिस्टर अपने दूतावास सम्बन्धी कार्य के साथ-साथ सी० आई० ए० का मुख्य अधिकारी भी है। उसका नाम लेनार्ड विस बताया गया और कहा गया कि अमेरिकन दूतावास के सूचना विभाग के कार्यालय का एक कमरा सी० आई० ए० के अधिकारी अन्य लोगों से सम्पर्क बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूतावास को मिली हुई डिप्लोमेटिक सुविधाओं का किस प्रकार हनन किया जाता है, इसका पता लगते ही मनुष्य की आस्था ऐसा कार्य करने वाले लोगों से उठ जाती है। यह दुःख का विषय है कि हमारे देश में ही हमारे आंचल में विषैला सांप पलता रहे और हम निःसहाय उसे बड़े देखते रहें।

सी० आई० ए० में दो प्रकार के दलाल हैं :—

१. संस्थाएं और
२. व्यक्ति विशेष

सी० आई० ए० में भर्ती होने के लिए नवयुवकों और विद्यार्थियों को तरजीह दी जाती है। दूसरा नम्बर पत्रकारों का है। विद्यार्थी और युवक भासानी से मुलावे में आ सकते हैं इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे पत्रकार जो अपनी 'भामदन' बढ़ाना चाहते हैं उन्हें 'आधुनिक समस्याओं से सम्बन्धित' लेख लिखने के लिए अच्छी खासी रकम दी जाती है। सवाल लेख लिखने का नहीं बल्कि इस लेख के माध्यम से इस पत्रकार के हृदय में प्रवेश करके उसे सदा के लिए भमरीनी 'उदारवादिता' का समयक बनाना है। यह लेख यह कह कर लिखाए जाते हैं कि इनका प्रयोग समाचार पत्रों में किया जाएगा परन्तु यह सब लेख वाशिंगटन भेजे जाते हैं जहाँ इन लेखों की भली भाँति छान बीन की जाती है और उन्हीं के आधार पर सी० आई० ए० अपना भगला कदम निर्धारित करती है।

दलाल कैसे भर्ती किए जाते हैं

एक 'नया दलाल' जिसे पुराना दलाल खोज कर लाता है, बहलाकर, कुसला कर, भर्ती तभी किया जाता है जब पुराने दलाल ने इसकी सिफारिश की हो। नये दलाल का परिचय सी० आई० ए० के अधिकारी से न कराकर उस व्यक्ति के साथ कराया जाता है जिसका यह काम होता है कि वह हर सप्ताह रिपोर्ट लेकर अधिकारी को दे। मालिक और 'नीकर' के बीच सीधा सम्बन्ध रखने की आज्ञा नहीं है। कौन जाने किस वक्त यह राज खुल जाए और इसकी भयानक प्रतिक्रिया हो। जासूसों का यह जाल बिल्कुल खुफिया ढंग से काम करता है। जब नया दलाल भर्ती कर लिया जाता है तो उसका पुनः नामकरण किया जाता है यह नाम देशी नहीं विदेशी रखा जाता है। आदमी के नाम पर नहीं बल्कि जानवर के नाम पर। कोई 'ईगल' है तो कोई 'कैमल,' कोई "पेंबर" है तो कोई "रीनो"। यह नामकरण क्यों? इसलिए कि भेद खुल न जाए! इस नकली नाम पर उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है—सप्ताह में कम से कम एक रिपोर्ट। हर रिपोर्ट के दाहिने कोने पर नकली नाम लिखा जाता है उसके साथ जिसका 'इण्टरव्यू' किया गया हो उसका नाम व तिथि। रिपोर्ट विस्तृत नहीं बल्कि खास-खास बातों के बारे में होती है। 'थोड़ा लिखो, लेकिन सम्भ्रमदारी से लिखो', 'थोड़ा मिलो लेकिन जानकारी से मिलो।'।

बस क्या है रिपोर्ट बनते ही पुराना दलाल उछलने लगता है कि आखिर मुर्गी पकड़ ली गई। प्रत्येक दलाल के लिए अपने सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देना अति आवश्यक है :

क—निजी जानकारी

१. क्या आप मदिरा सेवन करते हैं ?

२. क्या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी आजादी की लड़ाई में भाग लिया है ?

३. आपका सम्बन्ध किस राजनैतिक दल से है ?

४. राजनैतिक दलों में आपके घनिष्ठ मित्र कौन से हैं और कहा हैं ? आप उन्हें कब से जानते हैं ।

५. आपका कार्य क्षेत्र कौन सा है—धुवक, श्रमिक या पड़े लिखे लोग ।

६. आपका संक्षिप्त परिचय ।

ख—राजनैतिक जानकारी

१. प्रगतिशील विचारधारा वाले किन व्यक्तियों को जानते हो, उनके नाम व ठहरने का स्थान ?

२. आप उन्हें कैसे जानते हैं ?

३. आप उन्हें कब-कब मिलते हैं ?

४. उनका कार्यक्षेत्र कौन सा है ?

जैसे ही नए व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो उस व्यक्ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसे काम सौंप दिया जाता है । सबसे पहला काम उसके जिम्मे यह लगाया जाता है कि वह अपने सभी राजनैतिक जानकारी के बारे में, विशेषतया साम्यवादियों और उनके सहयोगियों के बारे में, यथा सम्भव जानकारी दे । इस लिस्ट की फिर जाँच पड़ताल की जाती है और फिर इसके आधार पर उस नए व्यक्ति को कहा जाता है कि वह उन जानकार व्यक्तियों से अधिक घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ाए । उसे हर सप्ताह एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है उसमें जिस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जाती है उसका नाम और बातचीत का स्थान एवं तिथि लिखी जाती है । प्रत्येक रिपोर्ट फर्जी नाम पर प्रस्तुत की जाती है । हर दलाल को उसका वेतन मास के अन्त में दिया जाता है । भारत पर चीनी आक्रमण से पहले मासिक वेतन की रसीद कमेटी 'दु कम्बेट कम्यूनिज्म' के नाम पर ली जाती थी परन्तु उसके बाद यह विभाग कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया

क्योंकि साम्राज्यवादियों की नज़र में 'साम्यवादियों की साख कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी'। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख अधिकारी को भारत से वापिस बुला लिया गया और थोड़े समय तक कमेटी का काम धीमा पड़ गया।

यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद उस व्यक्ति के माध्यम से जिसे 'मध्य पुरुष' कहा जाता है, भारतीय प्रमुख अधिकारी को दी जाती है जो इसे सी० आई० ए० के प्रमुख अधिकारी को पेश करता है। 'मध्य पुरुष' के ही माध्यम से सम्पर्क कायम रखा जाता है।

दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों की खोज की गई जिन्हें पत्रकार होने के नाते यह प्रलोभन दिया गया कि यदि वह अमरीकी पुस्तकों का अनुवाद करें तो उन्हें प्रयाप्त धनराशि दी जाएगी—एक पत्रकार को ५००० रु० केवल ५० पृष्ठ की पुस्तक का अनुवाद करने के लिए पेश किए गए लेकिन उस स्वाभिमानी पत्रकार ने चांदी के चन्द ठीकरों पर अपना ईमान बेचने से इन्कार कर दिया।

इसी प्रकार एक साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक से कहा गया कि यदि वह अपने समाचार पत्र में एक विशेष लेख सम्पादकीय के रूप में छापें तो उन्हें अच्छी धनराशि प्रदान की जा सकती है लेकिन इस सर्त पर कि लेख अमेरिकन सूचना विभाग का अधिकारी लिखेगा। यद्यपि सम्पादक के लिए इतनी बड़ी पेशकश को ठुकराना आसान नहीं था परन्तु उस गर्विले पत्रकार ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि 'मैं अपनी कलम नहीं बेच सकता'।

बिचौले को उसकी सेवाओं के उपलक्ष में दी जाने वाली धन राशि रिपोर्ट तैयार करने वाले से थोड़ी कम मात्रा में होती है। मजे की बात यह है कि हर जासूसी करने वाले व्यक्ति को यह आश्वासन दिया जाता है कि जो काम वह कर रहा है वह न तो गैर कानूनी है और न ही सरकार विरोधी अपितु साम्यवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक 'राष्ट्रीय कार्य' है।

बस यह मूल मन्त्र है और वशीकरण मन्त्र भी। इसके इशारे पर नई-नई मस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं। प्रातः उठिए तो पता लगेगा कि।

'मस्जिद तो बना दी पल भर में,
ईमां की हारत वालों ने।'

पलक झपकते ही नई संस्था बन गई, नए पैठ छप गए, और कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि अमरीकी सूचना विभाग के सहयोग से सदस्यों को फिल्म दिखाई जा रही है। आहिस्ता-आहिस्ता सम्बन्ध बढ़ते जाते हैं और यहाँ तक पेशकश की जाती है कि यदि आप चाहें तो अमरीकी 'उदारवादिता' के सहारे अमेरिका जाने का निमन्त्रण भी पा सकते हैं।

एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति भारत आये जिनका जन्म भारत में हुआ था परन्तु उन्होंने अमरीकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इस सज्जन का नाम मोघक था। यह भारत में इसलिए आए कि पता लगा सकें कि कहीं भारत साम्यवादी तो नहीं बन जाएगा। प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिल्ली में कंस्टीट्यूशन क्लब में कुछ दिनों तक निवास किया और इस दौरान वह कई लोगों से मिले। ऐसा लगता है कि उन्हें विश्वास हो गया था कि अधिक देर तक पूँजी के बल पर लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं दबाई नहीं जा सकती। आर्थिक ढाँचे में यथानुसार परिवर्तन आएगा उसे साम्यवाद भी कह दिया जाए तो भारतीय जनता को आपत्ति नहीं होगी। न तो हिन्दू की भूल अलग है न मुसलमान की, न ईसाई की पेट की ज्वाला अलग है, न सिक्ख की। भूखा पेट रोटी मांगता है—भिखारी के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी की तरह। जब तक आर्थिक ढाँचे में आमूल परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, यह सघर्ष जारी रहेगा पूँजीवादी व्यवस्था को न तो पूँजीपति बचा सकते हैं, न पूँजी के दलाल। इसलिए वे लोग जो धन का प्रलोभन देकर गरीब जनता के स्वाभिमानी की छुनौती देते हैं उन्हें कदापि यह भूलना नहीं चाहिए कि गरीबी से सताए हुए लोगों की भी मर्यादा होती है। जब गरीब लोगों के विचारों का ज्वालामुखी फूटेगा तो उसकी घषकती हुई ज्वाला में पूँजीवादी व्यवस्था टिक नहीं सकेगी। परन्तु फिर भी यह कोलाहल क्यों? धन का सालख क्यों दिया जाता है? खुफिया काम करने के लिए। यह खुफिया काम ही नहीं बल्कि पडमन्त्र है, स्वाभिमानी लोगों के खिलाफ, प्रगतिशील राष्ट्रों के खिलाफ, ताकि प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए उनके कदम डगमगा उठें, वे अपनी भूमि से भटक जाए और अमरीकी 'उदारवादिता' की शरण में इस प्रकार सो जाएं जैसे सीतेली मा किसी बच्चे को खोरी देकर नहीं बल्कि विपरीत दूध पिलाकर हमेशा के लिए मौत की गोद में सुला दे।

मोघक के चले जाने के पश्चात भारत में एक अमेरिकन नीग्रो जार्ज कार्टर का आगमन हुआ। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने वल्डें ग्रेसम्बली आफ यूथ की भारतीय कमेटी का 'पुनर्गठन' किया। जार्ज कार्टर दिल्ली स्थित मेडनज होटल में तीन दिन

तक ठहरे और पानी की तरह पैसा बहाते रहे और इस बीच कुछ 'लामदायक व्यक्तियों' से अपना सम्पर्क बढ़ाने में सफल हो गए। यह इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि उस समय वल्ड असेम्बली आफ यूथ के साथ 'सैनिक गुटबन्दी' के प्रश्न पर झगड़ा हो गया था। भारतीय कमेटी ने जापान की सैनानुष्ठान संस्था के साथ मिलकर वल्ड असेम्बली आफ यूथ के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पेश करके सैनिक गुटबन्दी का विरोध किया था। उस समय पश्चिमी देशों पर सैनिक गुटबन्दी का भूत सवार था और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी युवक संस्था इस नीति का विरोध करे। युनाइटेड पारित प्रस्ताव वाशिंगटन की नज़रों में खटकने लगा और वह इस 'हठधर्मी' का बदला लेने के लिए मोके की तलाश करने लगे। वल्ड असेम्बली आफ यूथ के पैरिस स्थित मुख्य कार्यालय और नई कमेटी के बीच किन शर्तों पर समझौता हुआ यह भी एक बहुत बड़ा राज है।

वल्ड असेम्बली आफ यूथ ने कुछ वर्षों के बाद अपना अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जिसकी अध्यक्षता एक नीग्रो ने की। यह अधिवेशन कुछ दिनों तक दिल्ली में चलता रहा परन्तु किसी भी प्रतिनिधि ने सैनिक गुटबन्दी के विरोध में प्रस्ताव पास करना तो एक और रहा, एक शब्द भी न कहा। उसका कारण यह था कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मण्डलों में पाकिस्तान मिलिट्री आपरेशन का युवक विभाग भी शामिल था। वल्ड असेम्बली आफ यूथ के अध्यक्ष से जब इस प्रतिनिधि मण्डल के बारे में प्रश्न किए गए तो अध्यक्ष भड़ोदय आएँ वाएँ शाएँ करने लगे। इस सम्मेलन में युवक कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल भी शामिल था परन्तु इस प्रतिनिधि मण्डल में उन लोगों का बहुमत था जो प्रकट रूप में तो भारतीय थे परन्तु दिल में वे अमरीकी नीति के समर्थक थे और वे नहीं चाहते थे कि वाशिंगटन वाले उनसे नाराज़ हो। शायद इसी बात पर दोनों के बीच गोपनीय समझौता हुआ था। जहाँ कहीं भी भारतीय भावनाओं का प्रश्न उठा, भारतीय कमेटी ने भूल से भी उनका प्रतिपादन नहीं किया। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को यदि अन्तर्राष्ट्रीय दिवालियापन कहा जाए तो उचित होगा। जो लोग अपनी कार्यवाहियों से शांति वातावरण को दूषित करते हैं उनके साथ समझौता करना ग़द्दारी नहीं तो क्या है। वे भूल जाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय एकता का यह अर्थ नहीं कि आप अपने राष्ट्रीय हितों को तिलाञ्जलि दे दें। १९६१ के भारतीय झगड़े में १५ अमरीकी विद्यार्थियों का एक टोला भारत भेजा था ताकि वे भारतीय विद्यार्थियों से अपने सम्बन्ध बढ़ा सकें। वास्तव में उनका उद्देश्य यह जानना था कि अमरीकी नीतियों के प्रति भारतीय विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है?

जब भारत में अमरीकी सरकार की नीतियों के प्रति लोगों ने रोष प्रकट करना शुरू किया तो अमरीकी दूतावास ने यह उचित समझा कि अमरीकी नीतियों के प्रति उचित वातावरण पैदा किया जाए और इस सम्बन्ध में दूतावास की ओर से कई लोगों को जिनका सम्बन्ध युवक या विद्यार्थी संस्थाओं से था को आमन्त्रित किया गया। मूलतया इन बैठकों का उद्देश्य था भारतीय लोगों में अमरीका की खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करना क्योंकि उस समय भारतीय लोग यह जान गए थे कि १९६५ के भारत-पाक झगड़े में भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाने वाले पैंटन टैंक अमरीकी थे, जो गोला बारूद पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया वह भी अमरीकी था। पाकिस्तान ने जो भी अस्त्र-शस्त्र इस्तेमाल किए वे सब अमरीकी थे। जम्मू की सीमा पर यदि मन्दिर की दीवार गोला बारूद से गिरी तो इसके लिए अमरीका जिम्मेदार है और अम्बाला में गिर्जा बर्बाद हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी अमरीका पर है। वे लोग जो मौत की मोद में सदा के लिए सुला दिए गए उनकी आत्मा अमरीका को अवश्य बुरा भला कहेंगी। जिस मां का बेटा इससे छीन लिया गया वह अमेरिका का गुणगान नहीं कर सकती, जिस बहिन का सिद्धूर रोंद दिया गया वह अमरीकी सरकार की नीतियों की निन्दा क्यों नहीं करेगी। जब हर ओर से अमरीकी नीतियों की आलोचना की जाने लगी तो अमरीकी सरकार बोखला उठी। अमरीका के इतिहास में उस समय अमरीकी प्रतिष्ठा को जबर्दस्त धक्का लग चुका था। जब गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो गांधी जी ने हमें सिखाया था कि 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं'। हमने ऐसा किया भी बावजूद इसके कि हमारे देश के सैकड़ों नर नारियों को साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए हम अमरीका या उनके लोगों के विरोधी नहीं हैं बल्कि अमरीकी नीति के विरोधी हैं।

हम अमरीकी सरकार की कोरिया और वियतनाम सम्बन्धी हस्तक्षेप की नीति के विरोधी हैं, हम अमरीकी सरकार के इसलिए भी विरोधी हैं क्योंकि अमरीका ने एक छोटे से राष्ट्र क्यूबा के खिलाफ अतिक्रमण किया है। अमरीका इसलिए भी बदनाम है कि इसने हिरोशीमा और नागा साकी में असह्य और निरीह जनता पर बम बरसा कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसके अतिरिक्त अमरीका सैनिक समझौतों द्वारा छोटे-छोटे राष्ट्रों को धमकाता है और उनकी आजादी का सोदा करता है। हमारा यह पुरु से ही निश्चित मत है कि अमरीका की इस नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। भारतीय लोगों की बात तो अलग रही अमरीकी लोग भी अमरीकी सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इसका ज्वलन्त

उदाहरण है अमरीकी जहाजरानों और सैनिकों का विधतनाम युद्ध में अमरीकी सरकार की ओर से हस्तक्षेप में भाग लेने से इंकार करना, अमरीका में नवयुवकों की ओर से भारी प्रदर्शन, जन अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन और एटमी बमों के प्रयोग के विरोध में विश्वास जन सभाएं। इन विरोध सभाओं और प्रदर्शनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी लोगों के दिल में अपनी सरकार के प्रति कितना रोष है। परन्तु यदाकदा हमें ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिनका काम दिन रात अमरीकी नीतियों का गुणगान करना है। अमरीका उनका स्वाभिमान गीन ले, तो वह इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे, उनकी इज्जत लूट ले तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, और इन सब चीजों के उपनक्ष में कुछ डालर मिल जाएं तो वे इसे दैवी देन समझेंगे। इस प्रकार के पिछलगू हर देश में मिलेंगे, उनकी सस्थाएं भी मिलेंगी, परन्तु इनसे सजग और जागरूक रहना चाहिए। उदाहरणतया 'कांग्रेस फार कलचरल फ्रीडम' और 'फोरम फार फ्री एंटरपराइज' ऐसी सस्थाएं हैं जो दूसरे के स्वर में ही गा सकती हैं। न उनकी अपनी आवाज है न अपना अस्तित्व। पूँजीवाद का समर्थन करेंगी और समाजवाद का विरोध। उनकी नीति है कि 'गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर'। वे यह भी चाहती हैं कि जन साधारण अपनी मांगें मनवाने के लिए सघर्ष नहीं करें बल्कि पूँजीपतियों से दया की भीख मांगे। इन संस्थाओं को कई प्रकार से सहायता भी मिलती है। 'एन्काउंटर' समाचार पत्रिका के सम्पादक स्टीफन स्पेंडर ने अपने पद से इसलिए त्याग पत्र दिया क्योंकि यह सिद्ध हो चुका था कि इस पत्रिका को सी० आई० ए० से धन की सहायता मिलती रही है। अमरीका में छपने वाले एक समाचार पत्र "रैम्पाट" ने उन संस्थाओं की सूची भी प्रकाशित की है जिन्हें परोक्ष रूप में सी० आई० ए० से सहायता दी जाती रही है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार विशुद्ध धरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाता रहा है।

सी० आई० ए०, विरोधी-सस्थाएं बनाने में भी चतुर है और मजे की बात तो यह है कि इन सभी ऐसी सस्थाओं के नाम और काम में 'प्रजातान्त्रिक प्रणाली' का नाम मात्र समावेश भी रहता है। पुरानी सस्थाओं को काबू करने का काम यदि असफल रहे तो नई सस्था को जन्म देना ही उचित समझा जाता है। ये सस्थाएं नाम मात्र होते हुए भी कुछ न कुछ बेवकूफ बनाने में सफल हो जाती हैं। न तो इन्हें धन का अभाव होता है न साधन का। न इनका सम्बन्ध सांस्कृतिक से है न स्वतन्त्रता से। ये स्वयं धोखे में रहती हैं और दूसरों को धोखा देती हैं।

एशिया फाउंडेशन भी एक ऐसा संस्थान है जिसे मान फ्रांसिसको के कुछ नागरिकों ने इसलिए स्थापित किया था कि 'एशिया में स्वतन्त्र समाज का निर्माण हो सके और लोगों को समान मौके प्राप्त हों'। इस संस्थान ने विश्व के कई देशों में अपना जाल बिछा रखा है। इस संस्थान के बोर्ड आफ ट्रस्टीज में प्रमुख हैं एलास-वर्य बकर (भारत में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत), ग्रेस एल० कर्क (कोलम्बिया विश्व-विद्यालय के अध्यक्ष) एडविन ओ० बिसचावर (भूतपूर्व अमरीकी वित्तमन्त्री)। यह संस्थान भारतीय लोगों को शिक्षण प्राप्त करने के लिए धन आदि की सहायता करता रहा है। यह संस्थान साल भर में लगभग ३० लाख डालर खर्च करता है। इस संस्थान का एशिया सोसायटी के साथ भी गहरा सम्पर्क है और इसी के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और प्रबन्धकों के लिए ग्रीष्मकालीन विद्यालय स्थापित किए गए हैं। कई संस्थाओं का नाम इस बारे में लिया जा चुका है। न्यूयार्क टाइम्स ने 'अमेरिकन फ्रेंड्स आफ इण्डिया' को भी सी० आई० ए० का ही भंग बताया है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी ही संस्था 'फाउंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेंट्स अफ़ेयरज' है जो 'इण्टरनेशनल स्टुडेंट्स कांफ़ेस' की धन इत्यादि से सहायता करती रही है। इस काफ़ेस का मुख्य कार्यालय लीडन में है और यह संस्था लग-भग १०,००० डालर प्रतिवर्ष व्यय करती है। थोड़ा समय पहले इस संस्था का अध्यक्ष एक भारतीय नवयुवक था जो इस संस्था में नेशनल काउंसिल आफ यूनि-वर्सिटि स्टुडेंट्स आफ़ इण्डिया का प्रतिनिधित्व करता था। जब इस संस्था के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि इण्टरनेशनल स्टुडेंट्स कांफ़ेस को सी० आई० ए० से सहायता मिलती रही है तो इस संस्था ने मार्च १९६६ में अपने आप को भंग कर दिया। इसके स्थान पर थोड़ा समय हुआ एक नई संस्था स्थापित की गई है जिसका नाम है—इंस्टीट्यूट इण्टरनेशनल द-एस्पूदियां सुरल-एजूकेशन अर्थात् शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जिसका प्रमुख कार्यालय ब्रसलज (बेल्जियम) में कायम किया गया है। यह संस्था नई अवश्य है परन्तु पुरानी संस्था का नया नामकरण है या यूँ कह लीजिए कि 'पुरानी शराब नई बोतलों में' है।

फाउंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफ़ेयरज की ओर से नेशनल काउंसिल आफ यूनिवर्सिटि स्टुडेंट्स आफ़ इण्डिया को धन की सहायता मिलती रही है। आश्चर्य की बात है कि इस संस्था को इस बात की खुली छूट रही है कि यह विद्वविद्यालयों में स्वच्छन्दता से कार्य करती रहे और शिक्षा शास्त्रियों का आशीर्वाद भी प्राप्त रहे। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस संस्था का ६६ प्रतिशत बजट अज्ञात स्रोतों से

पूरा होता रहा है। नेशनल काउंसिल आफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आफ इण्डिया की नींव विचित्र परिस्थितियों में रखी गई। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी संधों की एक गैर-प्रतिनिधि बैठक में, जिसे तत्कालीन अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आशीर्वाद प्राप्त था, १९५८ में इसकी आधारशिला रखी गई। कुछ अज्ञात सूत्रों के दबाव के कारण इस सस्या को थोड़े समय तक सरकार से भी आधिक सहायता मिलती रही है। आधिक सहायता बाद में इसलिए बन्द कर दी गई कि यह सस्या जांच पड़ताल के लिए अपना हिसाब-किताब पेश न कर सकी। शायद उसे इस बात का डर था कि राज खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सज्जन ऐसे भी थे जिनका हिसाब-किताब फर्स्ट सिटी बैंक न्यूयार्क में तब तक चलता रहा जब तक कि उसे बैंक के प्रमुख अधिकारी ने हिसाब-किताब बन्द करने की माग न की।

कहा जाता है कि नेशनल काउंसिल आफ दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आफ इण्डिया विश्वविद्यालयों के छात्र संधों को सम्बद्ध करने वाली संस्था है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्र संध तो बने ही नहीं। ६५ में से केवल १७ विश्वविद्यालयों में छात्र संध हैं जो नामांकित किए जाते हैं। ३५ विश्वविद्यालयों में संध का कोई अस्तित्व नहीं लेकिन फिर भी नेशनल काउंसिल आफ दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आफ इण्डिया अपने आपको सब से अधिक शक्तिशाली और ८० लाख विद्यार्थियों की प्रतिनिधि बताती है। यह सच है कि इस सस्या के अधिकांश पदाधिकारियों को इस सस्या को मिलने वाली धन राशि के सूत्रों का ज्ञान नहीं है परन्तु यह भी सच है कि यह सस्या अपने सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावीजों में लाखों विद्यार्थियों की प्रतिनिधि बन कर पेश होती रही है। 'लाखों विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व' करने वाली इस संस्था का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली की डिफेंस कालोनी में रहा है और ऐसा मुनने में आया है कि इस सस्या का मासिक व्यय किसी भी राजनैतिक दल के मासिक व्यय से कम नहीं होगा? इनकी बैठको और अधिवेशनों में चाहे कुछ ही लोग भाग लें, व्यय की कोई कमी नहीं होगी और यह आश्चर्य की बात नहीं कि १७ प्रतिनिधियों की विचार गोष्ठी में १७००० रुपया खर्च हो जाए। यह विचार गोष्ठी तभी सफल हो सकती है जब या तो काश्मीर की झूलत जलवायु हो या मसूरी का आनन्दमय वातावरण। आखिर इसमें कौनसी बुरी बात है? परनाले की ईंट परनाले पर ही लगेगी। नेशनल काउंसिल आफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आफ इण्डिया के छपे हुए कागजों पर इस बात का दावा किया जाता है कि इस सस्या को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और शिक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है परन्तु पता लगा है कि इसमें कोई सत्यता नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य

व्यक्ति को बिना स्वार्थ के कुछ नहीं देता । जो जिस साज बजाने वाले को पैसा देगा, वैसा ही स्वर उसके साज से निकलेगा ।

सी० आई० ए० के भूतपूर्व प्रमुख एलन डलेस ने १९६७ में सी० आई० ए० के कार्य की सराहना करते हुए कहा था :—

“सी० आई० ए० को जिस चीज की आवश्यकता थी उसे मिल गई अर्थात् गोपनीय सूचना ।’ परन्तु बात यहां तक ही नहीं, इससे भी आगे है । इस समय जो संस्थाएं सी० आई० ए० के इशारे पर काम कर रही है उनमें उल्लेखनीय है :—

- क) इण्टरनेशनल कांफ्रेंस आफ स्टुडेंट्स ।
- ख) इण्डिपेंडेंट रिसर्च सर्विस आफ न्यूयार्क ।
- ग) वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ ।
- घ) कमिटी आफ कारेसपोंडेंस न्यूयार्क ।
- ङ) दि पैन अमेरिकन फाऊंडेशन ।
- च) दि अमेरिकन सोसायटी आफ अफीकन कलचर ।
- छ) दि इण्टरनेशनल मार्किट इन्स्टीट्यूट ।
- ज) दि अमेरिकन फौंडज आफ दि मिडल ईस्ट ।
- झ) इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट फाऊंडेशन आफ न्यूयार्क ।
- ञ) इण्टर नेशनल यूनियन आफ यंग क्रिश्चन डेमोक्रेट्स ।
- ट) नेशनल स्टुडेंट्स एसोसियेशन इन केनेडा ।
- ठ) यूनिवर्सिटी आफ म्यामी ।
- ड) इण्टरनेशनल कन्फेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियनज ।
- ढ) दि कोओपरेटिव लीग आफ अमेरिका ।
- ण) इण्टर नेशनल लेबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ।
- त) कांफ्रेंस आफ दि एटर्नालिक कम्युनिटी ।
- थ) इण्टरनेशनल सेक्रेटरियेट आफ दि पैक्स रोमाना ।
- द) वेस्ट बर्लिन यूनियन फार दि एडवांसमेंट आफ एज़्केशनल ऐंड इन डिवेलपिंग कण्टरीज ।
- ध) इण्टर नेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट ।
- न) न्यूज पेपर गिल्ड आफ अमेरिका ।
- प) इण्टर नेशनल जर्नलिस्ट्स कांफ्रेंस इन जेनेवा ।

- फ) इंटरनेशनल फेडरेशन आफ ज्वरनलिस्ट्स इन बसल्ड ।
- व) रेडियो फ्री यूरोप ।
- म) रेडियो लिब्रेशन ।
- म) रेडियो फ्री एशिया ।

इन संस्थाओं को सी० आई० ए० की सिफारिश पर भिन्न-भिन्न संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिलती है । इन संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं :—

- १) टावर फंड ।
- २) गोथम फाऊंडेशन ।
- ३) बोर्डन ट्रस्ट ।
- ४) बेकन फण्ड ।
- ५) पराडिस फण्ड ।
- ६) हार्डट्स फण्ड ।
- ७) बिलफोर्ड-टेलफोर्ड फण्ड ।
- ८) एडसल फण्ड ।
- ९) सान मिगुएल फण्ड ।
- १०) काण्टफील्ड फण्ड ।
- ११) मुनरो फण्ड ।
- १२) मिशिगान फण्ड ।
- १३) एन्डरू हेमिल्टन फण्ड ।
- १४) अपालिशन फण्ड ।
- १५) विनेबुड फण्ड ।
- १६) चार्ल्स पराडिस विट्टन फण्ड ।
- १७) जेम्स कारलायल ट्रस्ट ।
- १८) एम० डी० एन्डरसन फाऊंडेशन ।
- १९) होग्लीवेल फाऊंडेशन ।
- २०) जे० एम० काप्लन फण्ड इन कारपोरेशन
- २१) वेयरड फाऊंडेशन ।
- २२) जे० फ्रैड्रिक वाउन फाऊंडेशन ।
- २३) रेब चेरिटेबल फाऊंडेशन ।
- २४) मार्शल फाऊंडेशन ।

इसके अतिरिक्त कई संस्थाएँ और संस्थान ऐसे भी हैं जिनके नाम इसमें दर्ज किए जा सकते हैं। जब पहली बार दिल हिला देने वाली गाथा अमेरिकन नेशनल स्टुडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी से सुनी गई तो उसे इस बात की घमकी दी गई कि राज खोलने पर उसे जेल यात्रा करनी पड़ेगी और भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह नवयुवक तो निश्चय कर चुका था “तुम तीर आजमाओ, हम ज़िगर आजमाएँ” और यह भी कि सच बोलने वाला भयंकर परिणामों की चिन्ता नहीं करता। उस नवयुवक ने बताया कि सी० आई० ए० के दलाल व्यक्तियों के बारे में और विद्यार्थी संस्थाओं की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग २० संस्थान ऐसे हैं जिनकी नींव रखते समय उन्हें ‘बेनामी’ बनाया गया था। संस्थान का नाम तो केवल बाहरी दिखावा है, काम तो सब सी० आई० ए० का है। कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सी० आई० ए० से बाकायदा वेतन पाते रहे हैं। इन्हें जासूसों की श्रेणी में भर्ती करने से पहले सौगन्ध खानी पड़ती है कि वे हर बात गोपनीय रखेंगे और उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि उन्होंने कोई भेद खोला तो उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। जिन विद्यार्थियों को जासूसों की श्रेणी में शामिल किया जाता है उन्हें अमरीकी खुफिया विभाग के कोड में ‘विट्टी’ कहा जाता है।

न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार दिल्ली में इन्टरनेशनल यूथ सेंटर, दि नेशनल स्टुडेंट्स प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया और दि फ्रेन्ड्स ऑफ इण्डिया ट्रस्ट को फाऊंडेशन आफ यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज तथा कैंसर बुड फाऊंडेशन से आर्थिक सहायता मिलती रही है। नेशनल काउंसिल आफ दि यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स आफ इण्डिया के भूतपूर्व एग्जिक्यूटिव सेक्रेट्री ने हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक २१ फरवरी १९७० में एक वक्तव्य द्वारा कहा :—

“एक योजना के लिए हमें प्रबन्ध ही थोड़ी सी आर्थिक सहायता फाऊंडेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज, न्यूयार्क से प्राप्त हुई थी। परन्तु हमें रस्तीभर भी सदेह इस संस्थान की गतिविधियों के बारे में न था। हमें इस बात का बिल्कुल ज्ञान न था कि इस संस्थान को सी० आई० ए० से सहायता मिलती है।”

हमें आश्चर्य है कि अज्ञानता का सहारा निजि बचाव के लिए कैसे लिया जा सकता है। जब तक समाचार पत्रों में सी० आई० ए० के बारे में छपा नहीं तब

तक तो यह बात ठीक थी कि वह अज्ञानता के शिकार थे परन्तु जानकारी होने के बाद कोई भी समाचार सी० आई० ए० की गतिविधियों का सण्डन करने के बारे में नहीं आया और या अगर आया भी होगा तो समाचार पत्रों ने अनावश्यक समझकर कहीं फेंक दिया होगा। यदि सूझ बूझ रखने वाली संस्था अज्ञानता का बहाना करे तो यह कोरा झूठ है। इंटरनेशनल स्टुडेंट्स काउंसिल, जो १९६६ में भंग की जा चुकी है, का महामंत्री एक भारतीय युवक था। केनेडा के विद्यार्थी नेता हेविड यंग ने सी० आई० ए० पर आरोप लगाया है कि इस संस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए केनेडा के विद्यार्थियों को नाभांकित किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफ़ेयरस की ओर से विचार गोष्ठियों के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता मिलती रही है।

२३ फरवरी १९६८ को भारत में मनोनीत एशिया फाऊंडेशन के प्रतिनिधि रिचर्ड जी० हेगी ने स्वीकार किया कि यह संस्थान विभिन्न संस्थाओं को वर्ष में ४००,००० डॉलर की सहायता प्रदान करता रहा है, जिसमें अनुसंधान का कार्य भी सम्मिलित है। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ६ मार्च १९६८ को सदन पर बोलते हुए कहा था कि एशिया फाऊंडेशन को सी० आई० ए० से धन मिलता रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में यह सहायता न मिले। एशिया फाऊंडेशन भारत में कई योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता देती रही है। इसी कारण भारत सरकार ने एशिया फाऊंडेशन को अपनी कार्यवाहियां भारत में बन्द कर देने का आदेश दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने संसद में २३ फरवरी १९६८ को बताया कि फाऊंडेशन को सी० आई० से आर्थिक सहायता मिलती रही है इसलिए इसकी कार्यवाहियां आपत्तिजनक हैं।

सी० आई० ए०, सांस्कृतिक गतिविधियों, कलाकारों, खिलाड़ियों, प्रदर्शनियों और यात्रियों से सम्बन्धित संस्थाओं में भी घुस पैठ करती है ताकि उन लोगों के जिन्हें एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधा रहती है, माध्यम से अन्य देश के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाया जा सके। भारतीय संसद में सभी दल के सदस्यों ने सी० आई० ए० की गतिविधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह संस्था विभिन्न ढंगों में राजनैतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रही है और उनकी गतिविधियों का संचालन भी करती है। केन्द्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने ६ दिसम्बर १९६७ को संसद में बताया कि भारत में इन गतिविधियों को रोकने के लिए यथोचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा

कि सी० आई० ए० विद्यार्थी समुदाय का घोषण भी कर सकती है इसलिए सजग रहना आवश्यक है। अमरीकी गुप्तचर विभाग का वार्षिक बजट अमरीका के कुल बजट का छटा भाग है और इस विशाल धन राशि के कारण सी० आई० ए० ने सेना में और नासकीय विभागों तथा निजि संस्थाओं में अपने पाँव जमा रखे हैं। १९ दिसम्बर १९६७ को न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार में यह लिखा गया था कि वार्ट हाऊस पेनल के सदस्यों में इस विषय पर तीव्र मतभेद पाया जाता है कि सी० आई० ए० को खुले रूप से अन्य संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की छूट दी जाए या न। इस पेनल के अध्यक्ष डीन रस्क थे। समाचार में यह भी बताया गया कि ३१ दिसम्बर की निर्धारित सीमा तक इस पेनल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजी जा सकती। इसके अतिरिक्त इस पेनल ने अपना कार्य क्षेत्र भी चार योजनाओं तक ही सीमित रखा है। इसका उद्देश्य यह है कि उन संस्थाओं को जिन्हें सी० आई० ए० से सहायता मिलती रही है चालू वर्ष के लिए सहायता दी जाती रहे और इसके साथ-साथ नीम-अधिकारी संस्था बनाने का काम भी शुरू किया जाए जो कि आहिस्ता-आहिस्ता विदेशों में शिक्षा और साहित्य संबंधी कार्यवाहियों को चला सके। इसी कार्य की पूर्ति के लिए उम समय राष्ट्रपति लिंडसन जानसन ने १९ सदस्यों पर निर्मित डीन रस्क की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण ६ अप्रैल १९६७ को किया था ताकि इस विषय पर विचार किया जा सके कि विदेशों में विद्यार्थी संस्थाओं और अन्य गुटों को खुले रूप से आर्थिक सहायता कैसे प्रदान की जाए। इस समिति के निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नेशनल स्टुडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सी० आई० ए० पर आर्थिक सहायता करने का आरोप लगाया था और कहा था कि गत १५ वर्षों से सी० आई० ए० जासूसी करने का काम करती रही है।

सी० आई० ए० इस बात का निरन्तर प्रयास करती है कि अन्य देशों में लोगों के विचारों को निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों की सहायता ली जाए। लगभग १० लाख डालर १९६१ में अमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड को इसलिए दिए गए ताकि अमरीकी जनता के विचारों को नई दिशा दी जा सके। इस गिल्ड के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क का लाभ उठा कर और यह भी जानते हुए कि यह गिल्ड इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ जर्नलिस्ट्स इन बरसल्स से तथा इण्टर अमेरिकन फेडरेशन आफ जर्नलिस्ट्स इन पनामा से सम्बद्ध है इस बात का प्रयास किया गया कि समाचार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों, समाचार एजेंटियों और रेडियो सम्बन्धी संस्थाओं में नए चेहरे ढूँढ़े जा सकें जहाँ सी० आई० ए० के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों। इस गिल्ड को आर्थिक सहायता के लिए धन राशि हेमिल्टन

फाऊंडेशन इन फिलेडेल्फिया से प्राप्त हुई जो कि सी० आई० ए० की ही संस्था है। इतनी बड़ी धन राशि देने का अभिप्राय: यह था कि गिल्ड के सदस्य डाक्टर की माया से प्रसन्न होकर अन्य देशों के पत्रकारों के साथ सम्बन्ध बढ़ाकर उनके भागे धमरीकी नीतियों का समर्थन करें। एक भारतीय युवक नेता जो सी० आई० ए० की दलाली करता रहा है, ने बताया कि १९६० में उसने सी० आई० ए० के माध्यम से भारत में होने वाली एक आवश्यक राजनैतिक बैठक में धमरीकी प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निर्णय कराया था ताकि उस बैठक में भाग लेने वाले चीन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों को सम्मेलन से अलग किया जा सके। यह प्रमाण है सी० आई० ए० द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवकों व विद्यार्थियों में हस्तक्षेप का। इस नवयुवक को वियाना में हुए विश्व युवक मेले के समय फाँसा गया था और इसके बाद १९६० में हुई आकरा की बैठक में नेशनल स्टुडेंट्स एसोसियेशन आफ़ अमेरिका ने इस नवयुवक को सी० आई० ए० के जाल में भर्ती करने पर राजी कर लिया था। आकरा में हुई बैठक के तीन महीने बाद, इस नवयुवक को सी० आई० ए० से सूचना प्राप्त हुई कि एक भारतीय नवयुवक नेता जो आकरा बैठक में मौजूद था, सी० आई० ए० का भी दलाल था। क्योंकि कुछ भारतीयों ने चीन और रूस से प्रतिनिधि बुलवाए हुए थे इसलिए वह चाहता था कि इस सम्मेलन में अमेरिकन भी भाग लें ताकि तटस्थता की नीति न अपनाई जा सके। इस नवयुवक को इसलिए पूरा खर्चा देकर भेजा गया कि वह यह काम कर सकता था। परिणाम स्वरूप नई दिल्ली से आकरा का हवाई जहाज़ का टिकट दे दिया गया।

अमरीकी सरकार परोक्ष रूप से अमेरिकन सेंट्रल ट्रेंड यूनियन आर्गनाइजेशन की इसलिए सहायता करती रही है ताकि इस संस्था द्वारा विश्व के अन्य नवोदित राष्ट्रों में क्रांति-विरोधी भावना पैदा की जा सके। इससे पूर्व इस संस्था का सारा खर्चा सी० आई० ए० एक फर्जी फाऊंडेशन द्वारा अदा करती रही है। सी० आई० ए० का पैसा देने का काम यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट के हवाले कर दिया गया है इस नई संस्था से जिन अमरीकी संस्थाओं को सहायता दी जा रही है उनमें अमेरिकन सेंट्रल ट्रेंड यूनियन आर्गनाइजेशन भी शामिल है। इस के माध्यम से अमेरिकन रिटेल कलर्जस इण्टरनेशनल और इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ़ पेट्रोलियम एण्ड केमिकल वर्कर्स को आर्थिक सहायता दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट को क्षेत्रीय सेबर संस्था बनाने के लिए भी सहायता दी जाती रही है। अमेरिकन सेंट्रल ट्रेंड यूनियन आर्गनाइजेशन

(एफलशिम्पो) के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए किसी भी देश में उनकी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर सी० आई० ए० को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा है उन स्थानों पर सी० आई० ए० का काम चलाने के लिए नई संस्थाओं को जन्म दिया जा चुका है ताकि यह जाहिर हो सके कि नई संस्था कलुषित नहीं है।

सी० आई० ए० के लिए कोई भी ढंग अपनाना बुरा नहीं। जैसे जैसे काम बनना चाहिये चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही कारण था कि एक रूसी वैज्ञानिक को फांसने के लिए प्रेम-जाल फैलाया गया और एक सुन्दरी की सेवाएं प्राप्त करके उस वैज्ञानिक को थोड़े समय के लिए अमेरिका में धारण लेने के लिए तैयार किया गया। यह आरोप रूसी समाचार पत्र 'इज़वेस्तिया' के ६ फरवरी १९६८ के पन्ने में छपा। घटना इस प्रकार है : सी० आई० ए० ने एक अमरीकी वैज्ञानिक की धर्मपत्नी को डालरों का लालच देकर कहा कि वह रूसी वैज्ञानिक को, जो अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हुआ था, प्रेम जाल में फंसाए। इस तरह वशीभूत करने के पश्चात् रूसी वैज्ञानिक को वियाना स्थित होटल के कमरे से इस तरह निकाला गया कि कानों कान इसकी खबर भी न हो। इस प्रमिका ने बड़ी चतुराई के साथ रूसी वैज्ञानिक को पश्चिमी जर्मनी में सी० आई० ए० के दलालों के हवाले कर दिया जिन्होंने इस वैज्ञानिक पर दबाव डाला कि वह रूसी विज्ञान सम्बन्धी भेद बताए। जब उसे मजबूर किया गया तो उसके सिर से प्रेम का भूत उतर गया। उसने सोचा कि प्रेम-पाश में फंसा कर उसे अपने ही देश के खिलाफ जासूसी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रेम का तिलसिम टूटते ही वह रूसी वैज्ञानिक वहाँ से भाग निकला और वापिस अपने देश आ पहुँचा। वियाना से पश्चिमी जर्मनी लाते समय रूसी वैज्ञानिक को जो पासपोर्ट सी० आई० ए० ने दिया वह जाली था और उसमें उस वैज्ञानिक को एक सैनिक अधिकारी दिखाया गया था और उसे चुपके चुपके पश्चिम जर्मनी में फ्रैंकफर्ट लिबाया गया था।

यह एक अनोखा ढंग है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रेम-जाल में फास कर जासूसी करने पर विवश कर दिया जाता है। मनुष्य की कमजोरी का लाभ उठाकर जब उसे प्रेम के फदे में जकड़ लिया जाता है तो फिर नशीली आंखों से ओभ्ला होना कठिन हो जाता है। उसकी अपनी कमजोरी उसके लिए कठिनाईयाँ पैदा कर देती हैं। वह भागना चाहता है तो प्रेमिका उसे अपनी बांहों में जकड़

लेगी है। यह जानता है कि इस स्त्री का प्रेम केवल दिगाया है लेकिन उसके हाव-भाव में कुछ दाएँ के लिए प्रभावित हो जाता है। बग, यह सोचे से दाएँ ऐसे है जिनमें यह स्त्री भेद जानने का प्रयास करती है क्योंकि यह भी जानती है कि वह उस मनुष्य के साथ प्रेम दिन में नहीं बल्कि अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करने के लिए कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रायः इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। उन स्थानों पर ही यह सम्भव है जहाँ मेनजोल की आज्ञादी हो। यह सम्बन्ध दाएँ जाने सम्मेलनों में भी कायम रहे जाते हैं और तब तक यह काम जारी रहता है जब तक कि पूरा भेद हासिल न कर लिया जाए।

सी० आई० ए० वाले साम, दाम, दण्ड, भेद, चारो अंग अपनाते हैं। परन्तु यह बात ध्यान है कि अधिकार लोग इन अंग से बच निकले हैं और उन्होंने सी० आई० ए० की सुक्रिया गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। उनको आवाज एक चेतावनी है उन लोगों को जो सम्भवतः इस अंग में उलझे हुए हैं।

युवक मंच पर

सी० आई० ए० के दो तरफ़ मोर्चे हैं—युवकों के लिए वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ (वेय) और विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कांफ़ेंस (यह संस्था अब तोड़ दी गई है क्योंकि इस संस्था पर आरोप लगाया गया था कि इसका पूरा मंचालन सी० आई० ए० करता था)।

दोनों संस्थाएँ पश्चिमी रंग में ढली हुई हैं। एक नहला है तो दूसरा दहला। ये हमेशा इस ताक में रहती हैं कि किसी न किसी प्रकार कोई शिकार फँस जाए। इन संस्थाओं के तीर तरीके अन्य संस्थाओं से भिन्न हैं। स्वाल गंदम जवाब घना। न इनको विद्यार्थियों के हित से कोई लगाव है न युवकों की समस्याओं से। दोनों संस्थाएँ सी० आई० ए० की हिज मास्टर वायस् हैं। इनका अपना कुछ नहीं सब धिगाना है। पूरी की पूरी संस्था गिरबी रखी हुई है। इसके उपलक्ष में इन संस्थाओं के जिम्मे केवल यही काम है कि ऐसे युवकों का गुट तैयार किया जाए जो युवक आन्दोलन में बराबर झीत गुड़ जारी रख सकें ताकि युवा शक्ति बंट जाए और युवकों की क्रांतिकारी परम्पराओं को ठेस लगती रहे। युवक राग रंग में मस्त होकर आन्दोलन करना भूल जाएं। युवक देश भक्ति का नहीं प्रेम का राग अनापें और परिस्थितियों के गुलाम बन जाए।

विश्व युवक संस्था (वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ) तटस्थ रहने की नीति और विश्व शान्ति का विरोध करती है। स्वतन्त्रता के लिए जूझ रहे लोगों का समर्थन करना तो बहुत बड़ा प्रश्न रहा, इस संस्था ने भूल से भी कभी स्वतन्त्रता प्रिय लोगों का साथ नहीं दिया। पश्चिमी गुट बन्दी के दायरे में संस्था की नीतियों को सीमित रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और इसी भावना को लेकर नवोदित राष्ट्रों में

युद्धक आन्दोलन की जड़े खोलनी की जाती रही हैं। यह बलगत बात है कि भारी कोशिशों के बावजूद इस संस्था को हर स्थान पर मुंह की खानी पड़ी है। इसी संस्था की सब कार्यवाहियां गुप्त रूप से अमेरिका द्वारा संचालित की जाती हैं क्योंकि अमेरिका के कम्युनिस्ट-विरोधी कट्टर पंथियों को विश्वास है कि प्रगतिशील युद्धक आन्दोलन ही साम्राज्यवादी शक्तियों से टक्कर ले सकता है इसलिए वे लोग इस संस्था के माध्यम से प्रगतिशील नीतियों का विरोध करना ही उचित समझते हैं।

यही कारण है कि इस संस्था की कार्य-प्रणाली व सोचने का ढंग प्रजातांत्रिक प्रणाली से मेल नहीं खाता। सम्भवतः यही कारण है कि राष्ट्रीय समितियों का गठन चुपके-चुपके कर दिया जाता है और उन्हीं लोगों को संस्था का पदाधिकारी बनाया जाता है जो अपना दिल-व-दिमाग दूसरे के पास गिरवी रखने को तैयार हो। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की संस्थाएं तोड़ने-फोड़ने व विघटनकारी कार्यवाहियों का केन्द्र बन जाती हैं।

दुःख का विषय है कि ऊपर लिखित विश्व की दोनों संस्थाओं से सम्बद्ध संस्थाएं भारत में भी मौजूद हैं। उनका जन्म क्यों और कैसे हुआ यह जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने उलटने पड़ेगे।

दो विश्व युद्धों के बीच ऐसा दिखाई देता था कि सारा संसार सुकड़ सा गया हो। वैज्ञानिक प्रगति के बढ़ते हुए चरणों ने समय पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय की स्थिति से यह आभास होने लगा कि यदि विश्व के किसी एक कोने में कोई घटना घटित हुई तो उसकी प्रतिक्रिया विश्व के दूसरे कोने में देखी जा सकेगी।

युद्ध की भीषण प्रतिक्रिया ने शान्तिप्रिय लोगों के हृदय में नई चेतना पैदा की। अन्तर्राष्ट्रीय एकाता की भावना सर्वप्रथम मजदूर वर्ग में दिखाई देने लगी और यह बात सिद्ध हो गई कि आम जनता के हितों को तिलांजलि देकर कोई राष्ट्र उन्नत होने का दम नहीं भर सकता। यद्यपि विश्व के कोने-कोने में रहने वाले लोग धर्म, भाषा, जाति, रंग व खान-पान के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं परन्तु आशाओं और आकांक्षाओं की किमी भी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। वे सब नव-निर्माण के स्रोतक हैं और विश्व शान्ति के प्रहरी।

यही कारण है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का गठन शुरू हुआ जिनका उद्देश्य मित्रता और शान्ति के लिए निरन्तर प्रयास करना था ताकि

माने वाला संसार युद्ध के भीषण परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय संस्थाओं से भी यह आशा की जाने लगी कि वे भी राष्ट्रीय शक्ति एवं जन-मानस के कल्याण की भावनाओं का परिचायक बनेंगी। विश्व तानाशाही के पजे से मुक्त होगा, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक शोषण की दीवारें गिरा दी जाएंगी।

परन्तु युद्ध के विपरीत कीटाणु अन्दर ही अन्दर रेंगते रहे और समय पाकर शान्त वातावरण को दूषित करते हुए दिखाई देने लगे। वल्ड असेम्बली आफ यूथ इन्हीं विपरीत कीटाणुओं का मूल रूप है जिसका काम घिनीना है, जिसकी हर कार्य-वाही में बन्धुत्व-विरोधी भावनाओं का समावेश है और केवल उन्ही नीतियों का समर्थन करना है जो सड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद को सहारा दे सकें।

१९४५ में लन्दन में पहला अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन हुआ जिसमें वल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ की स्थापना की गई। तीन वर्ष पश्चात् १९४८ में लन्दन में एक अन्य सम्मेलन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, केनेडा, बेल्जियम, डेन्मार्क और नीदरलैंड के इशारे पर बुलाया गया और इस सम्मेलन में एक नई संस्था 'वल्ड असेम्बली आफ यूथ' की रूप रेखा तैयार की गई और एक वर्ष बाद एक नई संस्था का जन्म हुआ।

युवकों के लिए यह जानना स्वाभाविक था कि आखिर दो संस्थाओं को स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी ?

वल्ड असेम्बली आफ यूथ द्वारा प्रसारित प्रचार सामग्री में लिखा है कि जब इस संस्था का जन्म हुआ उस समय 'अन्तर्राष्ट्रीय समाज सेवा संस्थाओं का विचार अपनी चरम सीमा पर था'। युद्ध की भीषण प्रतिक्रिया के पश्चात् विश्व के शान्त वातावरण में भाग लगाने का काम ब्रिटेन की राष्ट्रीय युवक संस्थाओं की तदर्थ समिति के जिम्मे लगा और उसी ने ही यूरोप की अन्य युवक संस्थाओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने का काम प्रारम्भ किया, इसी लन्दन सम्मेलन में युवकों ने शीत युद्ध प्रारम्भ करने की पृष्ठ भूमि तैयार की गई जो कुछ समय बाद सिद्धहस्त साबित हुई। इसका ज्वलंत उदाहरण है वल्ड असेम्बली आफ यूथ का गत २५ वर्षों का इतिहास जिसके हर पन्ने पर अमिट दाग लगे हुए हैं। वे दाग इसलिए अमिट हैं क्योंकि वल्ड असेम्बली आफ यूथ ने अपनी घिनीनी गतिविधियों से युवक आन्दोलन को साम्राज्यवाद का पिछलग्गू बनाने का दुसाहस किया है। इस संस्था का सदैव यही मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार साम्यवाद का विरोध किया जाए ताकि अमेरिकन ढंग की

प्रजातान्त्रिक प्रणाली जिसे अमेरिका में 'जन-पूँजीवाद' की संज्ञा दी जाती है विश्व के अन्य देशों में भी पनप सके। इस संस्था का जनहित, प्रगति और स्वाधीनता के उतना ही प्रेम है जितना अमेरिका को सैनिक गुट बन्दो, मार्शल प्लान और आर्थिक सिद्धान्त से। क्योंकि इन सब कार्यवाहियों के पीछे एक ही भावना काम करती है कि किस प्रकार नवोदित राष्ट्रों को आर्थिक गुलामी की खंजीरों में पुनः जकड़ा जा सके।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की प्रत्येक नीति से भेदभाव की बूझलकती है यह संस्था काले और भोरे के प्रश्न पर रंग-भेद नीति का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखती। यही कारण है कि जब दक्षिण अफ्रीका में गोरी चमड़ी वाले युवकों ने एक ही समिति में काली चमड़ी वाले युवकों के साथ बैठने से इंकार कर दिया तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने एक ही देश में दो राष्ट्रीय समितियों को मान्यता देकर प्रमाणित कर दिया कि यह संस्था प्लान सरकार की रंग-भेद नीति के आगे केवल घुटने ही नहीं टेक सकती बरन् अपनी नीतियों को भी कुर्बान कर सकती है। वह उभरते हुए जवाकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और नवयुवक शांत रहें यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

एक ओर तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ रंग-भेद नीति के प्रश्न पर अपना ईमान गिरवी रख चुकी है और दूसरी ओर लोगों की आखों में धूल भोक्ने के लिए एक नींदो को अपनी संस्था के प्रधान पद पर सुबोभित भी कर सकती है। हाथी के दात खाने के और, दिलाने के और। जब दक्षिण अफ्रीका के युवकों का प्रश्न इस संस्था के सम्मुख रखा गया तो इसी संस्था ने अपनी एक विज्ञप्ति में कहा :

“ऐसा लगता है कि यदि दक्षिण अफ्रीका में दो राष्ट्रीय समितियाँ (यूरोपियन और गैर यूरोपियन) काम करती रहे तो यह निश्चित ही हमारी सफलता का प्रमाण होगा यदि इस प्रकार दो अलग २ समितियाँ बना दी जाएं तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक समिति को अपने प्रतिनिधि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ में भेजने का अधिकार होगा। यदि दक्षिण अफ्रीका के युवक इसे स्वीकार करें तो यह अवश्य ही एक महान कार्य होगा।

(विज्ञप्ति क्रम ६६। ब. अ. १२)

जब यह विज्ञप्ति यूरोपियन यूथ कौंसिल के सम्मुख रखी गई तो उन्होंने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया और मानव अधिकारों के चाटेर पर हस्ताक्षर करने में दृढ़ रह कर दिया। परन्तु इस अवहेलना के बावजूद यूरोपियन यूथ कौंसिल को

वर्ल्ड असोसिएशन का फ्रांज़ यूथ से निष्कासित न किया गया । बल्कि वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ ने आगे चल कर कहा :

“हम केवल इतना कर सकते हैं कि सावधान रहें ताकि हमारे ‘मित्र’ जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं हतोत्साहित न हों”---हम भविष्य से समझौता करने के प्रयास में इन ‘मित्रों’ से सम्बन्ध विच्छेद न करें भविष्य इस बात की निरन्तर कोशिश करते रहें कि भविष्य में कोई और महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके ।”

‘अपने मित्रों को हतोत्साहित न करें’ परन्तु किस लिए ? यह प्रश्न पूछना सर्वदा अनुचित समझा जाएगा क्यों कि इसका सीधा अर्थ यह होगा कि भविष्य के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया जा रहा है । भले ही वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ वर्तमान से समझौता करले और भविष्य को हमेशा के लिए गिरवी रख ले ।

परन्तु वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ का कोई भी तर्क गैरयूरोपियन यूथ काउंसिल को बाध्य न कर सका कि वह सही मार्ग अपनाए और रंग-भेद नीति को तिलांजली दे दे । जहाँ तक वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ का सम्बन्ध है इसकी इतनी भी हिम्मत न हुई कि रंग-भेद की नीति का समर्थन करने वाली गैर-यूरोपियन यूथ काउंसिल को सदस्यता से निष्कासित कर दे ।

वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ न तो साम्राज्यवाद का विरोध करती है और न ही उपनिवेशवाद का । यही कारण है कि इस संस्था ने कभी भी युवकों को साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए आह्वान नहीं दिया । हंगरी और चेकोस्लावोव्स्की के प्रश्न पर वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ टीका टिप्पणी कर सकती है लेकिन जब साम्राज्यवादियों ने १९५६ में स्वेज नहर के प्रश्न की घाड़ में मिरा पर आक्रमण किया तो वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ इस कुकर्म को भा का दूध समझ कर पी गई । एक शब्द भी उन्हो ने साम्राज्यवादियों के विरोध में न कहा । जब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली सत्ताशाही बर्बरता पूर्ण अत्याचार कर रही थी तो वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ के कान बहरे हो गये थे, अरब देशों पर इस्रायली आक्रमण के दौरान इसने अपनी आँख पर पट्टी बांध ली और विषयनाम पर अमरीकी आक्रमण के समय तटस्थ हो गई । यह है वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ का असली रूप । आज तक वर्ल्ड असोसिएशन फ्रांज़ यूथ की किसी भी बैठक में आक्रान्ताओं

के विरुद्ध आयाज नहीं उठाई गई। इससे बढ़कर साम्राज्यवाद की और अधिक सहायता क्या हो सकती है कि जब लेबनान और आर्जेंटिना में अमरीकी नौ सैनिक और ब्रिटिश फौजें उतारी गईं तो वल्टे असम्बली आफ यूथ का कोई भी पदाधिकारी इस तृप्त और बर्बरता पूर्ण कदम के आगे धंगुली भी न उठा सका।

यह केवल किस्सा या कहानी होती, तो भाखें भूंदी जा सकती थीं लेकिन यह तो एक हकीकत है जिसका परिचय वल्टे असम्बली आफ यूथ के सब प्रचार सम्बन्धी प्रसारिकाओं में मिलेगा।

इस आशय से कि विश्व में स्वतन्त्रता प्रिय लोगों को बल न मिले वल्टे असम्बली आफ यूथ एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था—वल्टे फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ—का उद कर विरोध करती है।

जून १९५१ में बर्लिन शहर में युवकों का एक बृहत् विश्व मेला हुआ जिसके बारे में वल्टे फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ ने प्रचार हेतु एक बुलेटिन निकाला। जिसका विरोध करते हुए वल्टे असम्बली आफ यूथ ने शिकायत की कि इण्टरनेशनल यूनियन आफ स्टुडेन्ट्स के प्रधान ने युवकों को क्यों आह्वान किया है कि 'विश्व शान्ति की स्थापना के लिए शस्त्रीकरण का विरोध करें' और 'जर्मनी के एकीकरण के लिए इसलिए प्रयास करें ताकि जर्मन समस्या का समुचित हल ढूँढा जा सके'। वल्टे असम्बली आफ यूथ ने यह भी कहा कि 'वल्टे फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ ने पश्चिमी अर्थ व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए युवकों को हड़ताल करने का आह्वान क्यों दिया है' और 'वल्टे फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ निशस्त्रीकरण का समर्थन क्यों करती है'। उन्होंने इस बात का भी गिला किया कि इण्टर नेशनल यूनियन आफ स्टुडेन्ट्स के अध्यक्ष ने अमरीका की युद्ध सम्बन्धी नीति का विरोध किया है और क्यों इस बात की मांग की है कि जर्मनी और जापान का निशस्त्रीकरण कर दिया जाए और जर्मनी और जापान के विद्यालयों एवं विश्व-विद्यालयों में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षण न दिया जाए।

वल्टे असम्बली आफ यूथ ने इस बात की भी शिकायत की कि वल्टे फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ के उद्देश्यों में क्यों इस बात पर बल दिया गया है कि 'विश्व-शान्ति के लिए आन्दोलन में तेजी लाई जाए', 'कोरियाई लोगों की आजादी की लड़ाई का समर्थन किया जाए' और 'बियतनाम के बहादुर लोगों की जो अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं सहायता की जाए'।

वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ के चार्टर का उल्लेख करते हुए वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह सर्वथा अनुचित है कि :—

‘बड़े-बड़े पूंजीपतियों, जिनका नेतृत्व अमरीकी साम्राज्यवाद करता है, की युद्ध सम्बन्धी नीति का विरोध किया जाए।’

“मारशल प्लान और एटलांटिक पैक्ट की आलोचना की जाए।”

“साम्राज्यवादियों के दमन चक्र का डट कर मुकाबला किया जाए ताकि परतन्त्रता की वेदियों में जकड़े हुए राष्ट्र स्वतन्त्र हो सकें।”

“सब देशों के युवकों को आह्वान किया जाए कि वे वियतनाम, कोरिया, अंगोला, मुजाबिक इत्यादि देशों में छिड़े हुए स्वतन्त्रता संग्राम की सहायता करें ताकि विश्व में शान्ति का वातावरण स्थापित हो सके।”

‘विश्व के सब युवकों को अन्तर्राष्ट्रीय एकता के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि उनकी शक्ति क्षीण न हो’—यह कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जिनको लेकर वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ सदैव वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ का विरोध करती रही है। अतः हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ विश्व शान्ति की मनु है। यह युवकों में अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री का विरोध करती है, और यह नहीं चाहती कि उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध करने वाले राष्ट्रों की सहायता की जा सके। इसकी दृष्टि में साम्राज्यवाद का विरोध करने का अर्थ है ‘पश्चिमी अर्थ व्यवस्था का विरोध’। वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का कोई भी तर्क किसी भी कत्तीटी पर खरा नहीं उतर सकता क्योंकि इस संस्था ने सदैव सैनिक गुट बन्दी का समर्थन किया है और साम्राज्यवादियों के तलवे चाटे हैं।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का चार्टर देखकर कोई भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह चार्टर अमरीका की विदेश नीति की ही प्रतिलिपी है। वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ की नीति का विरोध सोवियत संघ की नीति का विरोध नहीं वरन् विश्व के सब राष्ट्रों का विरोध है जो शान्ति प्रिय हैं। भारत भी उसी शान्ति की नीति का प्रबल समर्थक है, अन्य देश भी इसी दिशा में निरन्तर प्रयास करते हैं ताकि युद्ध के बादल सदा के लिए ओझल हो जाएं।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ यह भी आरोप लगाती है कि वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ स्पेन सरकार की तानाशाही का विरोध करती है ! करे भी क्यों न ? स्पेन के तानाशाहों ने जन-मानस की भावनाओं को कुचल कर रख दिया है । वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ को तो स्पेन के तानाशाहों का विरोध करने पर आपत्ति है परन्तु हम तो इन तानाशाही देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, पुर्तगाल, टर्की, पाकिस्तान, दक्षिणी रोडेशिया और दक्षिणी अफ्रीका को भी शामिल करते हैं । ये सब देश हमारी दृष्टि में विरोध के पात्र हैं क्योंकि इन देशों में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें जेल की काल कोठड़ी में कैद किया जाता है, बिना मुकदमा चलाए देश भक्तों को फांसी दी जाती है । भला, हम भारतीय भी इस दुराचारी तानाशाही को देख कर चुप कैसे रह सकते हैं ।

परन्तु जब हम तानाशाही का विरोध करते हैं, तो वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ की दृष्टि में हम 'पथ भ्रष्ट' हैं । प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह कैसे भी विचार रखे, परन्तु यदि कोई संस्था इस प्रकार के विचार रखे जिससे विश्व शान्ति और विश्व बन्धुत्व को खतरा हो तो उस संस्था की नीतियों का विरोध करना मानव-धर्म बन जाता है ।

१९५२ से लेकर आज तक वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ ने कई बार प्रयास किया है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ सहयोग की भावना अपनाए और विश्व के युवकों में मैत्री के लिए काम करे । परन्तु दो समस्याओं के बीच हुई निष्ठा-पड़ी की देख कर ऐसा लगता है कि जहाँ वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ 'युवकों में अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री पर बल देती रही है' वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का काम केवल झूठे आरोप लगाने के और कुछ नहीं रहा है । इसने बार-बार इस बात की मांग की है कि वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ अपनी नीति का स्पष्टीकरण करे । दूसरे शब्दों में इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ अमरीका की युद्ध सम्बन्धी नीति की समर्थक है । वह विमतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप की विरोधी नहीं और न ही इस्राईल की आक्रांता मानती है । भला, इसका समर्थन कैसे सम्भव हो सकता है । सत्य कटु हो सकता है, परन्तु सत्य तो सत्य है चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो ।

वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ ने कई बार सुझाव दिया कि दोनों संस्थाओं के बीच प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान हो चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो

या खेल का मैदान, विचार गोष्ठी हो या बृहत् सम्मेलन। परन्तु वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने इस सुभाव को भी ठुकरा दिया। आखिर किस लिए ?

क्या यह सत्य नहीं कि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने गलत रुख अपनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि वह लोह पर्व के पीछे है। नहीं तो क्या आवश्यकता है कि यह संस्था युवकों और उनकी संस्थाओं के साथ भी अनगव की नीति अपनाए। इसके अतिरिक्त कई ऐसे दृष्टान्त हैं जिनसे यह विदित होगा कि कुएं के मेंढक की भांति वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के द्वार केवल उन्ही लोगों के लिए खुले हैं जो साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की सदस्यता के द्वार साम्यवादी देश के युवकों के लिए बन्द हैं। कोई भी प्रगतिशील युवक संस्था इसमें प्रवेश नहीं पा सकती। केवल वही लोग इस संस्था के साथ सम्पर्क बढ़ा सकते हैं जो काठ के उल्लू हैं। इस संस्था से सम्बन्धित संस्थाएं केवल वही हैं जिनका दृष्टिकोण पश्चिमी ढांचे में ढला हुआ है। कोई भी तटस्थ संस्था इसके निकट नहीं आ सकती।

यदि हम वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के सम्मेलनों में भाग लेने वाले राष्ट्रों की सूची पर दृष्टि पात करें तो ज्ञात होगा कि ऐसे राष्ट्रों की संख्या अधिक रही है जो सदस्य तक भी नहीं हैं। आन्तरिक रिपोर्ट के अनुसार १९४६-५० में इस संस्था के २६ सदस्य थे, १९५०-५१ में इनकी संख्या ३३ हो गई और १९५२ में यही संख्या घटकर ३२ हो गई। इसी प्रकार क्रमशः प्रेक्षकों की संख्या १५, २० और २१ थी।

विश्व के कई छोटे से छोटे देश भी इसी गिनती में शामिल हैं। इस प्रकार वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ विश्व व्यापी संस्था न बनकर केवल साम्राज्यवादी विचार धारा की पिछलग्गू बन गई है।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के नियम '४' उपनियम 'ब' के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्रीय समिति को अपना चन्दा अदा न करने पर सदस्यता में प्रत्यक्ष निलय किया जा सकता है। परन्तु वास्तव में यह उपनियम विधान की शोभा बढ़ाने के लिए रखा गया है वास्तविकता कुछ और है। १ अप्रैल १९५१ तक राष्ट्रीय समितियों से वसूल की जाने वाली चन्दे की रकम कुल मिलाकर ५१८,८६१ फ्रांक (बेल्जियम सिक्का) थी जिसमें एक वर्ष बाद १४१,८८० फ्रांक की वृद्धि हुई। अगस्त १९६२ में डाकार (सेनीगाल) के स्थान पर आयोजित वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्रीय समिति को चन्दा न देने के उपलक्ष में संस्था के किसी भी पद पर खड़ा होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता था।

परन्तु स्वयं कोषाध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि १९५२ तक ३२ राष्ट्रीय समितियों पर्याप्त ६०% ने अपना चन्दा भ्रदा ही नहीं किया । जहाँ तक हमें विदित है चन्दा न देने पर किसी भी राष्ट्रीय समिति को आज तक बल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ की प्राथमिक व सक्रिय सदस्यता से भलग नहीं किया गया और न ही किसी राष्ट्रीय समिति को चन्दा न देने पर चुनाव में सट्टा होने या वोट डालने के अधिकार से वंछित किया गया । इसलिये यह जानना आवश्यक है कि यदि ६०% राष्ट्रीय समितियाँ चन्दा भ्रदा नहीं करतीं तो बल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ को मिलने वाली पर्याप्त धनराशि कहाँ से आती है ?

कोषाध्यक्ष ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में लिखा है कि 'धन तो हमारी संस्था का जीवन और प्राण है' । यदि यह बात सत्य है तो 'जीवन और प्राण' प्रदान करने की जिम्मेदारी किस पर है ?

बल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ से प्राप्त आकड़ों से पता लगता है कि १९४६-५० में इस संस्था को प्राप्त होने वाली धनराशि का ८३ प्रतिशत ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम से तथा १९५०-५१ में ८७ प्रतिशत ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और फ्रांस से प्राप्त हुआ । इसमें एक देश ने तो ४६ प्रतिशत धन राशि प्रदान की । यह सिद्धहस्त बात है कि संस्था को मिलने वाली कुल धनराशि का ५६ प्रतिशत ऊपर लिखे हुए देशों से प्राप्त हुआ । इसके विपरीत हर वर्ष संस्था को चन्दा में प्राप्त होने वाली धन राशि की मात्रा कम होती गई है ।

मझे की बात तो यह है कि कुल धन राशि का ३५ प्रतिशत तो केवल एक राष्ट्र देता रहा है । भला, वह राष्ट्र कौन हो सकता है जिसकी 'दान वीरता और उदारता पर बल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ की नींव सड़ी है ।'

१९५१ में इन्ही देशों (अर्थात् अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम) ने निर्धारित धन राशि का ८२ प्रतिशत और वास्तविक प्राप्त होने वाली धनराशि का ६१ प्रतिशत भ्रदा किया । १९४६ और १९५१ के बीच 'इन्हीं चार देशों ने निर्धारित धन राशि का ८७ प्रतिशत भ्रदा किया जिसमें अकेले अमेरिका की ओर से ३५ प्रतिशत धन प्राप्त हुआ' । इसके अतिरिक्त उसी वर्ष फ्रांस की राष्ट्रीय समिति ने वेय से वसूल करने वाली धनराशि जो इसे सफर-खर्च के लिए मिलनी थी, कुल मिलाकर १७,१३३ फ्रांक तक छोड़ दी ।

१९५२ में वेय को ५७६२०६ फ्रांक का घाटा रहा क्योंकि उस वर्ष का व्यय कुल मिलाकर १०,३४,४३५ फ्रांक था। अक्टूबर १९५१ में २००,००० फ्रांक का घाटा दिखाया गया। (बुलेटिन नं० ६)

१९५२ के बजट में व्यय होने वाली राशि १,६७४,००० फ्रांक थी जबकि आय केवल ७५६,००० फ्रांक थी। (सकुलर नं० १७/ब अ/१५)

यदि एक ही वर्ष की आय और व्यय के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते तो चकित होने की कोई बात नहीं। यह आंकड़े हमने वेय के विभिन्न सकूलरों और बुलेटिनों से प्राप्त किए हैं जिनको तैयार करने की जिम्मेदारी कई विशेषज्ञों पर है जिन्हें आंकड़े तैयार करने के लिए ही ७००० फ्रांक प्रति व्यक्ति प्रति मास दिए जाते हैं ताकि आंकड़ों में वास्तविकता की झलक आ सके। इसके अतिरिक्त आंकड़े एकत्र करने और उन्हें वास्तविक रूप देने का काम भी तो सरल नहीं, और हो सकता है कि आय-व्यय का व्योरा देते समय इन्हीं विशेषज्ञों को एक दूसरे के आंकड़े देखने का अवसर न मिला हो! आखिर राष्ट्रीय आय के बारे में भी तो अर्थशास्त्रियों की राय एक दूसरे से भिन्न होती ही है।

परन्तु हमें यह देखना है कि घाटा किस प्रकार पूरा किया गया :

फाऊंडेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज ने १० प्रतिशत धन राशि यात्रा कोष में ग्रांट के रूप में प्रदान की। इस फाऊंडेशन की आय के स्रोत के बारे में कुछ भी कहना असम्भव है।

अज्ञात स्रोतों से प्राप्त दान द्वारा। वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की डाकर में हुई बैठक में (डाकर प्रस्ताव क्रमांक ३) एक प्रस्ताव द्वारा (वेय प्रसारिका क्रमांक १४) अज्ञात स्रोत से प्राप्त होने वाले दान की स्वीकृति इसलिए दी गई ताकि कार्यालय का काम चलाने में पड़ी हुई बाधाएं दूर हो सकें। परिणाम स्वरूप कुमारी हेलन डेल को वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया।

इस संस्था को दान देने वाला व्यक्ति किन कारणों से अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है? इसलिए कि सम्भवतः कोई ऐसी समिति जो अमरीकी न हो उसे साम्यवाद-विरोधी गतिविधियों के पक्ष में दण्डित न करे।

गारंटी कोष से प्राप्त धनराशि द्वारा जो अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ईटली और नीदरलैंड से प्राप्त होती है और जो १९५२ में कुल मिलाकर २३७,६८६ फ्रांक थी।

सरकार द्वारा प्राप्त सहायता, चाहे वह परोक्ष हो या अपरोक्ष। कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट ने सारा भेद ही खोल कर रख दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि "अधिक मात्रा में धन देने वाले देश चिंतित हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में सुरक्षित व्यवस्था दिखाई नहीं देती। धन की बड़ी मात्रा तो सरकारी कोष से निकाली जाती है इस कारण उन्हें डर है कि कहीं सरकारी नीति में परिवर्तन आने पर इस धन राशि में कमी न कर दी जाए।"

(सरकूलर क्र० ११७/ब प्र/१५)

यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की न्यूयार्क स्थित बैठक में यह निश्चय किया गया था कि सरकार को किसी भी युवक आन्दोलन में परोक्ष रूप से नियन्त्रण या हस्तक्षेप न करने दिया जाए। और जब युवक संस्थाएँ स्वावलम्बी न बन सकें तो इन संस्थाओं को चलाने के लिए लोगों से धन इकठ्ठा किया जाए या उन स्रोतों से सहायता ली जाए जिन्हें इन संस्थाओं को सहायता देने की आवश्यकता का पूर्ण आभास हो।

लेकिन वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ अपनी मर्यादा को भूलकर कुछ संस्थानों के पास अपने आपको गिरवी रखती रही।

करोड़पति डेविड डेविस की सहायता से।

यूरोपियन यूथ काँसिल द्वारा प्राप्त धनराशि से।

इस प्रकार यात्रा कोष में घाटे की राशि पूरी की गई। १९५१-५२ में यात्रा के लिए १,८४४,००० फ्रांक धनराशि में से ४१५,००० फ्रांक धनराशि एशिया में वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के काम के प्रसार हेतु निर्धारित की गई। इस धनराशि से एशिया में अमरीकी दलालों का जाल बिछाने का काम किया गया।

कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट में दर्ज है कि 'कोई भी राष्ट्रीय समिति जिसे अपने सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो और जिसे जन-साधारण का सहयोग मिलता हो उसे अपनी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन का कभी भी अभाव नहीं रह सकता।'

इससे तो यही परिणाम निकाला जा सकता है कि वह राष्ट्रीय समिति जो अपना वार्षिक हिस्सा भ्रदा नहीं कर सकती वह एक जीती-जागती संस्था नहीं है ।

कोयाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट (सरकूलर क्र० ११७/व अ/ १५) में इस बात पर भी जोर दिया है कि यदि संस्था की प्रचार सामग्री न पढ़ी जाए तो ऐसी सामग्री कितनी भी उपयुक्त क्यों न हो, उपयोगी नहीं समझी जा सकती । यह कहना सत्य है कि न तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की कार्यकारिणी के सदस्य और न ही इसकी राष्ट्रीय समितियों ने कभी कोई चन्दा दिया है । एक बार जब कार्यकारिणी ने यह निश्चय किया कि संस्था की प्रसारिका 'वेय फोरम' केवल उन्हीं लोगों को भेजी जाए जो इसका चन्दा भ्रदा करते हों तो जिन्हें 'वेय फोरम' भेजना बन्द कर दिया गया उन्होंने कभी इस बात की शिकायत न की । इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ द्वारा प्रकाशित सामग्री में कोई भी सदस्य दिलचस्पी नहीं रखता । लेकिन मज्जे की बात यह है कि एक बार 'वेय फोरम' के बारे में जब बैठक में चर्चा की गई तो लगभग ३/४ सदस्यों ने इस पत्रिका को कभी पढा तक भी न था ।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ प्रजातन्त्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्वी यूरोप से जो युवक अपना देश छोड़ कर अन्य भागों में आकर बसते हैं उन लोगों के साथ और उनकी संस्थाओं के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित करती है । क्योंकि ये लोग न घर के होते हैं न घाट के, अतः इन लोगों को आसानी से पिछड़ बनाकर उन्हें अपनी मातृ भूमि के विरुद्ध पडयन्त्र रचने के लिए उकसाया जा सकता है । यूरोप में इन लोगों की कई संस्थाएं हैं । अमेरिका में भी इन संस्थाओं के काम को बढ़ावा देने का काम पूरे जोर से जारी है । इन लोगों के जिम्मे यह काम लगाया जाता है कि वे अपनी मातृ भूमि पर तथ्याकथित 'भ्रातृक का अध्ययन करें, मनन करें और साम्यवाद का विरोध करने के लिए तैयार रहें ।' इन सब संस्थाओं की कार्य प्रणाली एक जैसी है और वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का इन संस्थाओं के साथ धनिष्ट सम्बन्ध है ।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का यह मत है कि पूर्व और पश्चिम के बीच पाए जाने वाले अन्तर को कम नहीं किया जा सकता । परन्तु आश्चर्य तो यह है कि यह संस्था एक नागरिक में और अपने देश से भागने वाले एक भगोड़े में कोई अन्तर नहीं देखती । इस संस्था की विकास परिपद का सब से अधिक बजट इन 'भगोड़ी संस्थाओं' को आर्थिक सहायता देने पर व्यय होता है । १९५१ में इसी कार्यवाही को

बढ़ावा देने व इसके औचित्य के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया था जिसमें लिखा था :—

“.....कि राष्ट्रीय समितियाँ इस दिशा में निरन्तर प्रयास करें कि उन लोगों को जिन्हें अपनी मातृ भूमि छोड़ कर अन्य देशों में पनाह लेनी पड़ती है, अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए।”

राजनैतिक दमन का विरोध करने के नाम पर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ प्रस्ताव तो पास कर सकती है परन्तु उसके पास इस विषय पर कोई उत्तर नहीं कि क्यों इस संस्था ने भेदभावपूर्ण और रंग भेद का विरोध नहीं किया ? यह सस्था उपनिवेशवाद की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए उन देश भक्तों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं रखती जो साम्राज्यवाद के बलबूते पर पलने वाले देशों में हर प्रकार की कुर्बानी दे रहे हैं। जब पैटरिक लुमुम्बा की निर्मम हत्या की गई तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ इस दुर्घटना पर दो आंसू भी न बहा सकी। जब फ्रांस में प्रगति-शील युवकों के आन्दोलन को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारम्भ हुआ तो यह सस्था सो गई। जब स्पेन में बहादुर देश भक्तों के विरुद्ध दमन की कार्यवाहियाँ जारी थीं तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के पदाधिकारी कुम्भकर्ण की नींद सोए हुए थे। पुर्तगाल की घरती पर कितने लोग असह्यम अवस्था में छटपटा रहे हैं उनको देखने की हिम्मत इस संस्था में नहीं है क्योंकि यदि यह सस्था दमन का विरोध करेगी तो इसका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसको मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द हो जाएगी, वे भवन गिर जाएंगे जिसकी नींव पर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ खड़ी है। यही कारण है कि दमन पुर्तगाल में हो या स्पेन में, या किसी अन्य देश में, वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ गूँगे और बहरे की तरह न कान से सुन सकती है और न जबान से बोल सकती है। बोले भी क्यों कर, इसकी दुकान दूसरे के पास गिरवी है।

इस संस्था की इन्हीं नीतियों और गतिविधियों के कारण थोड़े ही काल में कई सतियाँ हुई हैं, उन पर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि यह सस्था दिन प्रति-दिन अपना अस्तित्व खोती जा रही है।

गैर-यूरोपियन यूथ काउंसिल आफ साऊथ अफ्रीका ने दिसम्बर १९५२ में इस संस्था को तिलांजलि दी। मारच १९५२ में इससे अलग हो गया। इससे पूर्व मार० ट्रेविसो बेन्जियम यूथ काउंसिल के नेता और दक्षिणी रोडेशिया के सहायक

महा मन्त्री ये ने १९५१ में इस संस्था से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि बल्ड ग्रसेम्बली आफ यूथ ने इन देशों में काम करने वाली राष्ट्रीय समितियों को बिना कारण ही बंग कर दिया था। आस्ट्रिया ने जून १९५३ में इस संस्था से सम्बन्ध विच्छेद कर लिए और उसी वर्ष उत्तरी रोडेशिया और सूरीनाम भी इस संस्था से अलग हो गए।

एक-एक करके यह कड़ी टूटती गई और इसकी सांख कम होती गई क्योंकि लोग इसका असली रूप पहचानने लग गए थे।

बल्ड ग्रसेम्बली आफ यूथ और इसकी भारतीय शाखा :

१९५५ में अमरीकी नवयुवक जार्ज कार्टर जो निग्रो थे और बल्ड ग्रसेम्बली आफ यूथ की ओर से एशिया के लिए सचिव नियुक्त थे, भारत आए। ठीक उसी समय श्रीमती रुजवेल्ट भी भारत यात्रा पर आई हुई थी। यह महिला भूतपूर्व राष्ट्रपति की धर्मपत्नी थीं। कारणवश इन्होंने अपने प्रति भारतीय सौहार्द को देख कर यही उचित समझा कि अमरीकी युवकों और भारतीय युवकों के बीच ताल-मेल बढ़ाया जाए। इससे सुन्दर अवसर कब मिल सकता था कि जार्ज कार्टर भी भारत में मौजूद थे। दिल्ली के मेडन होटल में बिराजमान यही अमरीकी युवक एक विशिष्ट व्यक्ति बने हुए थे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री से मिलकर इस बात का आश्वासन लिया कि भारतीय शाखा अमरीकी प्रभुत्व के नीचे काम करने वाली बल्ड ग्रसेम्बली आफ यूथ के साथ अपना नाता जोड़ लेगी। यह बात स्वाभाविक थी क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस में ऐसे तत्व मौजूद थे जो अमरीका को अपना 'मसीहा' समझते थे और समाजवाद के कट्टर शत्रु थे। इनके धरीर पर देशी अस्त्र तो जरूर थे परन्तु उनकी आत्मा मर चुकी थी। यह वही लोग थे जो अब कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं और उनकी नीतियों पर प्रत्येक व्यक्ति आक्षेप कर रहा है। श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में ये लोग भीरो बिस्ली की भांति काम करते थे। अन्दर ही अन्दर यह लोग घडयंत्र की भूमिका अदा करने के लिए अपने विश्वस्त सहयोगियों द्वारा युवकों में पदार्पण कर चुके थे। बस क्या था जार्ज कार्टर को अपना ध्येय पूरा करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ा। बम्बई के वातानुकूल बंगले में रंठ रामकृष्ण बजाज बिराजमान तो थे ही उन्हीं को इस संस्था की भारतीय शाखा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। यह घोषणा क्यों हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है ?

जार्ज कार्टर के भारत आगमन से पहले जो राष्ट्रीय समिति भारत में काम कर रही थी उस समिति के सदस्यों ने अपने राष्ट्रीय गौरव को मिरवी रखने से इंकार कर दिया था। उन्होंने अमरीका की इसलिए घोर निन्दा की थी क्योंकि अमरीका पाकिस्तान के साथ सैनिक गुट बन्दी में शामिल हो चुका था। अमरीका ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाने के लिए हथियार दिए थे। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस कार्यवाही की निन्दा नहीं करेगा? जिस व्यक्ति में राष्ट्रीय गौरव जागता है वह अमरीका की हथियार देने वाली नीति का कभी समर्थन नहीं कर सकता। भारतीय राष्ट्रीय समिति ने ऐसा ही किया और खुले ढंग से बल्ड असेम्बली आफ यूथ (भारतीय कमेटी) की ओर से डटकर विरोध किया। अमरीका नाराज हो गया। उसे यह कैसे गवारा था कि इस राष्ट्रीय समिति को कायम रहने दिया जाए। परिसमय स्वरूप जार्ज कार्टर अमरीका वापिस जाते समय भारतीय युवकों को एक भेंट दे गए—वह थी नई राष्ट्रीय समिति जिसका कार्यालय 'महात्मा गांधी मार्ग, बम्बई' पर खोल दिया गया।

दो वर्ष पश्चात् इसी समिति ने जी० रविन्द्र वर्मा को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया। जी० रविन्द्र वर्मा पुराने राजनैतिक खिलाडी हैं। विद्यार्थी आन्दोलन से सम्बन्धित होने के बावजूद इनकी कार्य शैली भारतीय लोगों की देश भक्ति की भावना को छू भी नहीं पाई। यह व्यक्ति आजकल सिन्डी केट के साथ हैं और उसकी नीति का समर्थन करते हैं। थोड़े समय पश्चात् रविन्द्र वर्मा बल्ड असेम्बली आफ यूथ के अध्यक्ष चुने गए। कितना बड़ा सम्मान मिला, व्यक्ति को नहीं बल्कि भारत को, परन्तु इस संस्था ने इस सम्मान को एक ओर रख कर केवल उन्ही नीतियों का समर्थन किया जो प्रतिक्रियावादी थी।

आज तक जितने भी भारतीय युवक इस संस्था के अध्यक्ष बने हैं वे सब के सब सिन्डीकेट में चले गए हैं। और यदि कोई एक आघ बच गया हो तो ऐसा व्यक्ति निःसन्देह निर्भीक होगा! वह स्वयं इस संस्था को छोड़ देगा। जब पहली राष्ट्रीय समिति बिना किसी कारण मंग कर दी गई तो उसका एक कारण यह भी बताया गया था कि पिछली समिति बल्ड असेम्बली आफ यूथ के नाम पर बल्ड असेम्बली आफ यूथ और अमेरिका के आपसी सम्बन्धों को खराब करना चाहती थी। उस समय यह बात विचित्र लगती थी परन्तु आज तो अमरीका में भी बल्ड असेम्बली आफ यूथ का चित्र धूमिल है। जार्ज कार्टर ने भारत आकर राष्ट्रीय समिति के रूप में परिवर्तन लाने के लिए तीन महीने तक निरन्तर प्रयास किया। और इस प्रयास में तत्कालीन

युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सहयोग दिया ! युवक कांग्रेस के तत्कालीन युवक नेता भी सिण्डिकेट में चले गए हैं । दिल्ली में भारतीय युवक कांग्रेस की परामर्शदाता समिति की बैठक ४-५ दिसम्बर १९५४ को हुई जिसमें यह निर्णय किया गया था :

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की गतिविधियों में रुचि ले और यदि इसे आमन्त्रित किया जाए तो यह भारतीय राष्ट्रीय समिति में शामिल हो जाए, परन्तु इस शर्त पर कि सारी समिति पुनः गठित की जाए ।”

(सरकूलर क्र० १ नं० वाई डी/पी.आर./१२४७५ दिनांक ६-१-१९५५)

थोड़े समय बाद कांग्रेस के कार्यालय से एक सरकूलर क्रम ५ सहाय वाई० डी०/पी० आर०/ ७ मार्च १९५५ को जारी किया गया जिस पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे और दोनों व्यक्ति युवक कांग्रेस और सेवा दल के प्रमुख नेता थे । इस सरकूलर में कांग्रेस कमेटीयों को आदेश दिया गया था कि वे वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के काम में रुचि लें । यह स्पष्ट है कि उस समय कांग्रेस जैसी महान संस्था में ऐसे लोग भी हूँद थे जो समाजवाद के समर्थक नहीं थे परन्तु ये लोग संस्था पर पूर्ण अधिकार जमाए हुए थे और निरन्तर इस कोशिश में रहते थे कि अवसर मिलने पर प्रगतिशील आन्दोलन का गला घोट दिया जाए । और ऐसा हुआ भी । इन लोगों ने कांग्रेस में सत्कारुढ होने का पूरा लाभ उठाया और डट कर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की सहायता की । यहाँ तक कि दिल्ली में इसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलवाया गया और दिल्ली में इस संस्था ने एक विशालकाय भवन का निर्माण किया जिसको देखकर आश्चर्य होता है कि वह संस्था जिसका अस्तित्व केवल कागजी पर है किस प्रकार १२ लाख रुपये की धन राशि से एक भवन तैयार कर सकती है ? यह पैसा कहां से आया और क्यों आया, यह पूछना ‘देश द्रोह’ होया क्योंकि इस धन में काला धन भी शामिल है और सरकारी धन भी, इसमें क्षोषण करने वालों की आत्मा वास करती है, साम्राज्यवाद की इससे बू आती है । इस भवन की कहानी बहुत अधिकार है क्योंकि इस भवन का निर्माण करने वाले देशी भी थे और विदेशी भी थे— अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच बनाया गया, कूटनीतिज्ञों की बस्ती में । कौन कहता है कि चाणक्य मर गया ? उसकी नीति खिन्दा है उसके नाम पर दिल्ली में एक बस्ती कायम है जहां विश्व के कूटनीतिज्ञ रहते हैं और इस बस्ती में विदेशी संस्थान की सहायता से युवक केन्द्र भी कायम है जिसे वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की मान्यता ही नहीं आशीर्वाद भी प्राप्त है ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि जब कांग्रेस ने सरकूलर भेज कर अपनी साखाओं को आदेश दिया कि वे वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ से सम्पर्क बढ़ाएं तो इसकी भूमिका कुछ दिन पहले ही तैयार कर ली गई थी और इस संस्था का प्रचार शुरू कर दिया गया था। उस समय से ही युवक कांग्रेस और सेवा दल का सम्बन्ध इस संस्था में रहा है। यह अलग बात है कि कांग्रेस के अन्दर भी शुरू से लेकर आज तक वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ का विरोध होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रगतिशील लोगो की आवाज न सुनी गई और सिण्टीकेट के इम्पारे पर वही काम होता रहा जिसकी खर्चा करते ही प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने वर्षों तक निस्तब्धता क्यों छाई रही ?

वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ द्वारा पहली एशियाई विचार गोष्ठी १९५६ में दिल्ली में बुलाई गई। इस विचार गोष्ठी में ३० भारतीय प्रतिनिधि और १५ एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इन लोगों ने एशिया के विभिन्न राजनैतिक और गैर-राजनैतिक युवक आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व किया। 'सागर को आगर में भर दिया,' कितना बड़ा कमाल दिल्ली में हुआ इसकी खर्चा क्यों न की जाए ? १५ प्रतिनिधियों ने ३० भारतीय प्रतिनिधियों के साथ मिल कर एशिया के युवक आन्दोलन का नक्शा बदलने की कसम खाई परन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी क्योंकि भारत के ४५ करोड़ लोग मजदूर और जायसुक थे और वे खूब समझते थे कि एशिया की धरती पर वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ क्यों पदार्पण कर रही है ? यह संस्था किसके हितों की रक्षा करेगी यह बताने की आवश्यकता नहीं थी।

मजे की बात यह है कि जब से भारतीय राष्ट्रीय समिति ने अपना सम्बन्ध वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ से जोड़ा है उसने आज तक कभी अपना खन्दा अदा नहीं किया। यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक है कि जो भी संस्था वर्ल्ड प्रसेम्बली आफ यूथ से सम्बन्ध रखती है उसकी गतिविधियों पर शक करना स्वाभाविक है। भारतीय लोगों ने अमरीकी सरकार की उन नीतियों का तीव्र विरोध किया है जिसका

अन्य देशों में

श्री लका मे अमरीकी गुप्तचर संस्था ने थोड़ा समय हुआ एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की और इस सम्बन्ध में एक नीग्रो रिसर्च स्कालर की सेवाएं प्राप्त की क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य उन लोगों से सम्पर्क बढ़ाना था जिनका रंग गोरा नहीं था। इस केन्द्र की गतिविधियों के बारे में सारे श्री लका में भारी प्रतिक्रिया हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना के पीछे कौन सा भेद छिपा हुआ है। जन-साधारण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि अमरीका के दक्षिणी प्रान्तों में रंग-भेद नीति के आधार पर काली चमड़ी वाले व्यक्तियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह सरकार जो अपने देश में रंग-भेद नीति को समाप्त नहीं कर सकी किस प्रकार निग्रो को श्री लका भेज कर अपनी रंग-भेद नीति पर पर्दा डालना चाहती है ?

लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर शान्ति के अग्रदूत डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की अमरीका में दिन दहाड़े हत्या क्यों की गई ? वे यह भी जानना चाहते थे कि गोरी चमड़ी वालों के लिए बने हुए विद्यालयों में काली चमड़ी वाले विद्यार्थी के प्रवेश पाते ही उन पर शिकारी कुत्तों से वार क्यों कराया जाता रहा है ? परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर अमरीकी गुप्तचर संस्था के किसी भी अधिकारी से नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ऐसा पूछना तो 'प्रजातन्त्र के प्रतिकूल' होगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने का अर्थ समझा जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हथकण्डों का भाण्डा फोड़ने के लिए 'साम्यवादी ढंग' अपना रहे हैं !

अमरीकी गुप्तचर संस्था, काले रंग के युवकों को अपने दाव में फंसाने के लिए काले रंग की आठ भी ले सकती है ताकि खुफिया काम करने में आसानी हो।

अमरीकी सूचना विभाग का एक नौजवान अधिकारी गुप्तचर संस्था में उस समय भर्ती किया गया था जब वह विद्यार्थी था। इसी अधिकारी को कई बार विद्यार्थी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए देखा गया। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अमरीकी सूचना विभाग का यह अधिकारी एक डिप्लोमेट है। इस गुप्तचर विभाग ने विशेष तौर पर दांतों का इलाज करने वाले डाक्टरों को भी भर्ती कर रखा है जिनका काम उपयुक्त व उपयोगी सूचना प्राप्त करना है ताकि अमरीकी गुप्तचर संस्था उसका उपयोग कर सके। कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को गुप्तचर विभाग के माध्यम से अमरीका भी भेजा जा चुका है ताकि वे 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में निपुणता प्राप्त कर सकें। 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' का यह कार्यक्रम केवल ढोंग है और यह वास्तव में एक सरल तरीका है युवकों को फुसलाने का। यह भलग बात है कि श्री लंका की घरती पर विघटनकारियों के पांव जम नहीं सके क्योंकि इस देश की शानदार परम्पराएँ हमेशा साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास की कड़ियों में निहित हैं।

कुछ मास हुए सियरा ल्योन में बुलाए गए सम्मेलन को असफल बनाने के लिए अमरीकी गुप्तचर संस्था ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्हें डर था कि आजादी का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि अमरीकन साम्राज्यवाद का विरोध अवश्य करेंगे जिससे अमरीका की साख कम होगी। परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन के महा सचिव के जाली हस्ताक्षरों से अमरीकी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूचना भेजी कि 'सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है', यहां तक ही नहीं इसी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन के लिए भेजा गया सब सामान जैसा कि कान के साथ लगा कर मुनने वाले यंत्र किसी हवाई कम्पनी के साथ मिल कर रास्ते में ही उतरवा लिए और उसे सियरा ल्योन न जाने दिया। गुप्तचर संस्था की यह कोशिश थी कि किसी प्रकार सम्मेलन असफल हो जाए। गुप्तचर संस्था अपने कार्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। परिणाम यह निकला कि जाम्बिया और केनिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

जुलाई १९६६ में हुए इस सम्मेलन में गुप्तचर विभाग ने बाघा ढालने का प्रयास केवल इसलिए किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में मंगोला, मोल्डोविया, गिनीबिसाओ में तब रहे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी भाग ले रहे थे।

अन्य देशों में

श्री लंका में अमरीकी गुप्तचर संस्था ने थोड़ा समय हुआ एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की और इस सम्बन्ध में एक नीग्रो रिसर्च स्कालर की सेवाएं प्राप्त की क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य उन लोगों में सम्पर्क बढ़ाना था जिनका रंग गोरा नहीं था। इस केन्द्र की गतिविधियों के बारे में सारे श्री लंका में भारी प्रतिक्रिया हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना के पीछे कौन सा भेद छिपा हुआ है। जन-साधारण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि अमरीका के दक्षिणी प्रान्तों में रंग-भेद नीति के आधार पर काली चमड़ी वाले व्यक्तियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह सरकार जो अपने देश में रंग-भेद नीति को समाप्त नहीं कर सकी किस प्रकार निग्रो को श्री लंका भेज कर अपनी रंग-भेद नीति पर पदां डालना चाहती है ?

लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आसिर दान्ति के अपद्रुत डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की अमरीका में दिन दहाड़े हत्या क्यों की गई ? वे यह भी जानना चाहते थे कि गोरी चमड़ी वालों के लिए बने हुए विद्यालयों में काली चमड़ी वाले विद्यार्थी के प्रवेश पाते ही उन पर शिकारी कुत्ते से बार क्यों कटाया जाता रहा है ? परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर अमरीकी गुप्तचर संस्था के किसी भी अधिकारी ने नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ऐसा पूछना तो 'प्रजातन्त्र के प्रतिकूल' होगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने का धर्म सम्भवा जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हर्षकण्ठों का भाण्डा फोड़ने के लिए 'नाम्नवादी ढग' अपना रहे हैं।

अमरीकी गुप्तचर संस्था, काले रंग के युवकों को अपने दाव में फँसाने के लिए काले रंग की भाव भी ले सकती है ताकि सुफिया काम करने में आसानी हो।

भमरीकी सूचना विभाग का एक नौजवान अधिकारी गुप्तचर संस्था में उस समय भर्ती किया गया था जब वह विद्यार्थी था। इसी अधिकारी को कई बार विद्यार्थी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए देखा गया। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि भमरीकी सूचना विभाग का यह अधिकारी एक डिप्लोमेट है। इस गुप्तचर विभाग ने विशेष तौर पर दांतों का इलाज करने वाले डाक्टरों को भी भर्ती कर रखा है जिनका काम उपयुक्त व उपयोगी सूचना प्राप्त करना है ताकि भमरीकी गुप्तचर संस्था उसका उपयोग कर सके। कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को गुप्तचर विभाग के माध्यम से भमरीका भी भेजा जा चुका है ताकि वे 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में निपुणता प्राप्त कर सकें। 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' का यह कार्यक्रम केवल ढोंग है और यह वास्तव में एक सरल तरीका है युवकों को फुसलाने का। यह घटपट बात है कि श्री लंका की घरती पर विघटनकारियों के पांव जम नहीं सके क्योंकि इस देश की ध्यानदार परम्पराएं हमेशा साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास की कठियों में निहित हैं।

कुछ मास हुए सियरा ल्योन में बुलाए गए सम्मेलन को असफल बनाने के लिए भमरीकी गुप्तचर संस्था ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्हें डर था कि भावादी भा समर्थन करने वाले प्रतिनिधि भमरीकन साम्राज्यवाद का विरोध अनिवार्य करेंगे जिससे भमरीका की हालत कम होगी। परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन के महा सचिव के जाती हस्ताक्षरों से भमरीकी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूचना भेजी कि 'सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है', यहां तक ही नहीं इसी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन के लिए भेजा गया सब सामान जैसा कि फान के साथ लगा कर सुनने वाले यंत्र किसी हवाई कम्पनी के साथ मिल कर रास्ते में ही डूबकर लिए और उसे सियरा ल्योन न जाने दिया। गुप्तचर संस्था की यह कोशिश की कि किसी प्रकार सम्मेलन असफल हो जाए। गुप्तचर संस्था अपने कार्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। परिणाम यह निकला कि जाम्बिया और केनिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में जाने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

जुलाई १९६६ में हुए इस सम्मेलन में गुप्तचर विभाग ने बाधा डालने का प्रयास केवल इसलिए किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में भंगोला, मोरम्बिर, प्लोदिमाओ में चल रहे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी भाग ले रहे थे।

अन्य देशों में

श्री लंका में अमरीकी गुप्तचर संस्था ने थोड़ा समय हुआ एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की और इस सम्बन्ध में एक नीग्रो रिसर्च स्कालर की सेवाएँ प्राप्त की क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य उन लोगों से सम्पर्क बढ़ाना था जिनका रंग गोरा नहीं था। इस केन्द्र की गतिविधियों के बारे में सारे श्री लंका में भारी प्रतिक्रिया हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना के पीछे कौन सा भेद छिपा हुआ है। जन-साधारण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि अमरीका के दक्षिणी प्रान्तों में रंग-भेद नीति के आधार पर काली चमड़ी वाले व्यक्तियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह सरकार जो अपने देश में रंग-भेद नीति को समाप्त नहीं कर सकी किस प्रकार निग्रो को श्री लंका भेज कर अपनी रंग-भेद नीति पर पदाँ डालना चाहती है ?

लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर शान्ति के प्रमदूत डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की अमरीका में दिन दहाड़े हत्या क्यों की गई ? वे यह भी जानना चाहते थे कि गोरी चमड़ी वालों के लिए बने हुए विद्यालयों में काली चमड़ी वाले विद्यार्थी के प्रवेश पाते ही उन पर शिकारी कुत्ते से बार क्यों कराया जाता रहा है ? परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर अमरीकी गुप्तचर संस्था के किसी भी अधिकारी से नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ऐसा पूछना तो 'प्रजातन्त्र के प्रतिकूल' होगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने का अर्थ समझा जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हत्यकण्डों का भाण्डा फोड़ने के लिए 'साम्यवादी ढग' अपना रहे हैं !

अमरीकी गुप्तचर संस्था, काले रंग के युवकों को अपने दाव में फँसाने के लिए काले रंग की झाड़ू भी ले सकती है ताकि गुप्तचर काम करने में आसानी हो।

अमरीकी सूचना विभाग का एक नौजवान अधिकारी गुप्तचर संस्था में उस समय भर्ती किया गया था जब वह विद्यार्थी था। इसी अधिकारी को कई बार विद्यार्थी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए देखा गया। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अमरीकी सूचना विभाग का यह अधिकारी एक डिप्लोमेट है। इस गुप्तचर विभाग ने विशेष तौर पर दांतों का इलाज करने वाले डाक्टरों को भी भर्ती कर रखा है जिनका काम उपयुक्त व उपयोगी सूचना प्राप्त करना है ताकि अमरीकी गुप्तचर संस्था उसका उपयोग कर सके। कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को गुप्तचर विभाग के माध्यम से अमरीका भी भेजा जा चुका है ताकि वे 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में निपुणता प्राप्त कर सकें। 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' का यह कार्यक्रम केवल ढोंग है और यह वास्तव में एक सरल तरीका है युवकों को फुसलाने का। यह अलग बात है कि श्री लंका की घरती पर विघटनकारियों के पांव जम नहीं सकें क्योंकि इस देश की सानदार परम्पराएं हमेशा साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास की कड़ियों में निहित हैं।

कुछ मास हुए सियरा ल्योन में बुलाए गए सम्मेलन को असफल बनाने के लिए अमरीकी गुप्तचर संस्था ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्हें डर था कि आजादी का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि अमरीकन साम्राज्यवाद का विरोध अवश्य करेंगे जिससे अमरीका की साख कम होगी। परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन के महा सचिव के जाली हस्ताक्षरों से अमरीकी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूचना भेजी कि 'सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है', यहां तक ही नहीं इसी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन के लिए भेजा गया सब सामान जैसा कि कान के साथ लगा कर सुनने वाले यंत्र किसी हवाई कम्पनी के साथ मिल कर रास्ते में ही उतरवा लिए और उसे सियरा ल्योन न जाने दिया। गुप्तचर संस्था की यह कोशिश थी कि किसी प्रकार सम्मेलन असफल हो जाए। गुप्तचर संस्था अपने कार्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। परिणाम यह निकला कि जाम्बिया और केनिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

जुलाई १९६६ में हुए इस सम्मेलन में गुप्तचर विभाग ने बाधा डालने का प्रयास केवल इसलिए किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में अंगोला; मोज़म्बिक, गिनीबिसाओ में तब रहे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी भाग ले रहे थे।

यह कैसे सम्भव हो सकता था कि साम्राज्यवादी और उनके पिछलग्गू इस सम्मेलन की सफलता को एक भ्रांति से देख सकते !

साइबेरिया भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है परन्तु इस देश पर वास्तविक रूप में फ्रायर स्टोन कम्पनी राज्य कर रही है। डालर शाही ने समूचे देश की आर्थिक व्यवस्था पर खड़ की पैदावार के माध्यम से अपना प्रभुत्व जमा रखा है। यह आश्चर्य की बात है कि इस देश में न तो घनाज की उपज होने दी जाती है और न ही इस देश में प्याज उगाया जा सकता है। देश के सर्वोच्च व्यक्ति की कोठी भी फ्रायर स्टोन कम्पनी ने बनवाई है ताकि उस देश की आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक सत्ता पर डालर का प्रभुत्व बना रहे। इस देश में हीरे जवाहरात की कमी नहीं है और यही कारण है कि इस देश का शोषण करने के लिए साम्राज्यवादी हर प्रकार के हथकण्डे अपना चुके हैं।

दक्षिणी अफ्रीका की रंग-भेद नीति का लाभ उठा कर अमरीकी गुप्तचर संस्था अनाधिकृत व्यापार चलाने के लिए कई नई-नई कर्मों की नींव डाल चुकी है जिनके नाम और काम में कोई सामंजस्य नहीं है। इसी देश में एक व्यक्ति जिसे 'हीरों का बादशाह' कहा जाता है को इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य चलाने के लिए निपुण माना गया है। यह व्यक्ति हीरों की तस्करी का काम करता है और इस ढंग से जिन-जिन देशों में इसने तस्करी के भट्ठे कायम कर रखे हैं वहां ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे बिध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। इस काम में बैंक आफ इंग्लैंड इनकी पूरी-पूरी सहायता भी करता है। कुछ चीनी दलाल भी कई देशों में इन्हीं कार्यों में सलग्न हैं। अमरीकी गुप्तचर संस्था साम्यवाद के विरोध के नाम पर वास्तव में सोवियत रूस का विरोध करती है अमरीकी गुप्तचर संस्था के लिए अवांछनीय नहीं है कि वे चीनियों से तालमेल बढ़ाएं क्योंकि अमरीकी गुप्तचर संस्था और लाल चीन दोनों ही सोवियत रूस के शत्रु हैं। और इसी कारण दोनों में कोई मतभेद नहीं है और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं।

ईसाईल एक ऐसा देश है जहां हीरों की कोई भी कान नहीं हैं परन्तु आश्चर्य की बात है कि ईसाईल मारो दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी है जो हीरे को निर्यात करता है। ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है कि ईसाईल मध्य एशिया में साम्राज्यवादी शक्तियों का दलाल है। अरब देशों पर ईसाईल आक्रमण से मध्य एशिया की शान्ति खतरे में पड़ चुकी है जिससे विश्व शान्ति को भी खतरा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ईसाईली आक्रमण की कई बार आलोचना की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद ईसाईल शरारत करने पर तुला हुआ है क्योंकि उसे साम्राज्यवादी देशों का सहयोग प्राप्त है। दिन प्रतिदिन आक्रांताओं की स्थिति दृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ समय हुआ ईसाईली सेना ने बड़ी बर्बरता पूर्ण ढंग से कैरो के एक विद्यालय पर बम बरसाए। अलअक्सा मस्जिद को आग लगाने का काम अकेले रोहण का ही नहीं बल्कि अमरीकी गुप्तचर संस्था की सोची समझी साजिश का नतीजा था ताकि अरब देश के लोगों को भयभीत किया जा सके। ईसाईल को साम्राज्यवादी देशों से पर्याप्त सहायता मिलती है। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि अलअक्सा मस्जिद में आग लगाने के काम के पीछे एक ऐसी भावना निहित थी जिसका उद्देश्य अरब भावना को ठेस पहुँचाना था। रोहण की बात तो अलग रही, ईसाईल सरकार स्वयं कई मस्जिदों को गिरा चुकी है। कई धार्मिक स्थानों पर अब यहूदियों के लिए नाच गाने के केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। दूसरे लोगों के धर्म के प्रति इस प्रकार की अवहेलना करके ईसाईल ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह हिटलरी तानाशाही से कम नहीं है। ईसायल से अरब वासियों को जबर्दस्ती निष्कासित करने और उनकी जायदाद को हड़पने का निरन्तर प्रयास जारी है। सबसे धर्मनाक बात यह है कि वे लोग जो उस देश के वासी हैं उन्हें अपने ही देश में भिखारी बना दिया गया है और उन्हें खुले आकाश के नीचे सड़कों पर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। दरयासीन में कत्लेआम की दुःखद घटना भुलाई नहीं जा सकती और न ही उन घटनाओं पर पर्दा डाला जा सकता है जो साम्राज्यवादियों और उनके दसालों ने पलस्तोन की पवित्र धरती पर अमानुषिक व्यवहार से घटित की हैं। इन सब कार्यवाहियों के पीछे अमरीकी गुप्तचर संस्था का हाथ है।

ईसाईल की सरकार लगातार युद्ध का वातावरण बनाए रखने के लिए यदा-कदा ऐसे काम करती रही है जिससे मध्य एशिया की शान्ति खतरे में पड़ी रहे और अनेकों रोहण अरब वासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए तैयार किए जा सकें। संसार के लोग जानते हैं कि पागलपन का बहाना लेकर न्यायाधीश ने रोहण को अपराधी मानने के बावजूद कानून के अन्तर्गत मिलने वाले भारी दंड को एक ओर रख कर न्याय की खिल्ली उड़ाई है। रोहण का यह पागलपन असली नहीं बल्कि ईसाईल सरकार की अरब-विरोधी नीति की देन है। साम्राज्यवादी शक्तियाँ नहीं चाहती कि अरब राष्ट्रीयता पनप सके क्योंकि अरब राष्ट्रीयता साम्प्रदायिक नहीं बल्कि समाजवाद की प्रतीक है।

अमरीकी गुप्तचर संस्था के कई विनीत रूप हैं। कभी-कभी तो यह बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हितों के रक्षक के रूप में, कभी-कभी तेल के बड़े व्यापारी बन कर यह संस्था अरब राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करने के लिए हथियारों की सहायता लेकर हमारे सम्मुख आती है। कभी-कभी तो घिसे-पिटे राजाओं की मदद भी करती है ताकि राजवाड़ा शाही की मुदां लाश को पुनः जिन्दा किया जा सके। जहाँ सनिज पदार्थ किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुनियमित बना सकते हैं वहाँ अरब देशों के आर्थिक स्रोत 'तेल' का शोषण करने के लिए तेल ही उसके शत्रुओं का सबसे बड़ा सीखा हथियार है। जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय मिस्र पर तीन देशों ने आक्रमण किया। यह आक्रमण मिस्र के विरोध के लिए नहीं बल्कि अरब राष्ट्रीयता का विरोध करने के लिए किया गया था। इसी कारण ईलायल और अमरीका की सरकारों में ताल-मेल है।

पिछले कुछ महीनों से अमरीकी गुप्तचर संस्था की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ समय पहले फ्रांस में इसी गुप्तचर संस्था ने मजदूरों के एक सर्वप्रिय नेता को अगवा कर लिया था। यह नया ढंग अपनाया गया था कार्यकर्ताओं को भयभीत करने का।

घाना में क्वामेइन्क्रूमा का तख्ता उलटने में भी अमरीकी गुप्तचर संस्था का ही हाथ था। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि जब क्वामेइन्क्रूमा ने अपने इलाका में रबड़ की उपज द्वारा घाना के आर्थिक ढाँचे को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास शुरू किया उस दिन से ही अमरीका इस ताक में था कि किस प्रकार स्वतन्त्रता सेनानी इन्क्रूमा को मार्ग से हटाया जा सके। परिणाम स्वरूप फायर स्टोन कम्पनी और अमरीकी गुप्तचर संस्था ने घाना में पडयन्त्र द्वारा इन्क्रूमा का तख्ता उल्टा दिया।

एशिया हो या अफ्रीका, अमरीकी गुप्तचर विभाग की काली करतूतें देखने को मिलेंगी। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन काली करतूतों का पर्दा फाश किया जाए।

अमरीकी गुप्तचर संस्था इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि इसका सीधा सम्पर्क युवक नेताओं से बना रहे और विशेषतया उन लोगों से जो भविष्य में सरकारी काम काज में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले हों। यही एक सरल ढंग है सरकारी मशीनरी को प्रयोग में लाने का। उन युवक नेताओं को ओर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनका सम्बन्ध किसी प्रगतिशील संस्था से रहा हो जिससे उनकी प्रगतिशील भावना को डालर की सहायता से कुण्ठित किया जा सके।

सरकारी कर्मचारियों को विचार गोष्ठियों में भी आमन्त्रित किया जाता है और कभी-कभी तो प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें बुलाया जाता है। इस प्रकार के निमंत्रण किसी सांस्कृतिक संस्था के नाम पर भेजे जाते हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने पर कोई आपत्ति न हो।

अफ्रीका में नाईजीरिया की स्वतन्त्रता ने एक नये युग का प्रादुर्भाव किया। सदियों से रोई हुई चेतना शक्ति सजग और जागरूक हो उठी। भला यह कैसे सम्भव था कि साम्राज्यवादी इस नई चेतना से समझौता कर लेते। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की सदैव यह नीति रही है कि 'बांटो और राज्य करो' परन्तु इसी नीति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया और 'बांटो और राज्य करो' के स्थान पर 'बांटो और चले जाओ' की नीति अपनाई गई। भारत के बंटवारे के समय अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। इससे पूर्व अंग्रेजी सरकार ने हिंदु और मुसलमानों में मन-मुटाव पैदा करने के लिए कोई कसर न छोड़ी। नाईजीरिया में साम्राज्यवादी शक्तियों ने ऐसा ही किया परन्तु उन्हें मुंह की खानी पड़ी और इनकी सब कोशिशें विफल रही और नाईजीरिया का बंटवारा न हो सका। बाईफरा को नाईजीरिया से अलग करवाने के लिए अलगाव सम्बन्धी शक्तियां साम्राज्यवादियों के इशारे पर काम करती रहीं। यह सिद्धहस्त बात है कि इस अलगाव सम्बन्धी आन्दोलन के पीछे साम्राज्यवादियों और चीनियों का हाथ था जिन्होंने धन से तथा अन्य प्रकार से अलगाव पसंदों की पूरी सहायता की। यह अलग बात है कि नाईजीरिया की राष्ट्रवादी सरकार ने अलगाव पसन्दों की दाल न गलने दी। अफ्रीकी महाद्वीप सी० आई० ए० की गतिविधियों का केन्द्र बन चुका है और कई अफ्रीकी देशों में सी० आई० ए० का घिनीना रूप देखने को मिला है। अफ्रीकी राष्ट्र गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद प्रगति के पथ पर बढ रहे हैं। उनकी इस प्रगति को देख कर साम्राज्यवादी बौखला उठे हैं। वे शासक जिन्हें अफ्रीका के लोगों की बुद्धि और योग्यता पर शक था वही अफ्रीकी लोगों की कार्य कुशलता पर परेशान हैं। साम्राज्यवाद की हार को विजय में परिणत करने के लिए सी० आई० ए०, एम० आर० ए० और पीस कोर इत्यादि संस्थाएं घुम पैठ की नीति को अपना कर अपनी घृणास्पद कार्यवाहियों को जारी रखने का प्रयास कर रही हैं। पश्चिमी देश अब भी अफ्रीका के लोगों को 'जानवर' समझते हैं और उन्हें 'असभ्य' कहते हैं, परन्तु तथा कपित सभ्यता के ठेकेदार भूल जाते हैं कि अफ्रीका प्रगतिशील और जागरूक विचारों की जन्मभूमि है। हमें वे दिन याद हैं जब अफ्रीका में रहने वाले लोगो को भेड़ बकरी की तरह जहाजों में लाद कर दूसरे स्थानों पर 'गुलामों' के रूप में भेजा जाता था। भेड़-बकरियों की

माति नीग्रो बिकते थे । इस अवस्था पर किसको खोभ नहीं होगा ? एक नई चेतना की लहर उठी जिसने अफ्रीका के लोगों की सोई हुई आत्मा को जगा दिया । आज अफ्रीका के लोग अपने देश का निर्माण कर रहे हैं और वे उन संस्थाओं को राष्ट्रीय गौरव और मान-मर्यादा के प्रति चुनौती समझते हैं, जिनका काम तथा कथित 'दान वीर' बनकर अफ्रीका को पुनः गुलामी के फंदे में बांधना है । आजादी के पहरेदार को सदैव सजग रहना चाहिये और इसके साथ ही उन संस्थाओं से भी सावधान रहना चाहिए जो आजादी की शत्रु हैं ।

सी० आई० ए० और कम्बोडिया

सी० आई० ए० इसलिए भी बदनाम है क्योंकि इसका काम राज्य सरकारों का तख्ता उलटना और अपने पिछलग्गुओं का गद्दी पर आसीन करना है। जहाँ सैनिक शक्ति द्वारा राज्य सरकार का तख्ता उलटना असम्भव हो वहाँ सी० आई० ए० पैमे का लालच देकर विधायकों को खरीदने का काम भी करती है। इन विधायकों को अपने दल छोड़ने पर विवश कर दिया जाता है। इस प्रकार सरकारों में परिवर्तन लाया जाता है। जब कोई विधायक बिक जाए तो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा।

सी० आई० ए० ने हेती में सरकार का तख्ता उलटने का षडयन्त्र १९६४, १९६५, १९६८ और १९६९ में किया। माफिया ने हेती के तानाशाह फाकोमस दुवालियर के विरुद्ध षडयन्त्र को विफल बना दिया। हेती के बारे में लगातार संघर्ष माफिया और सी० आई० ए० के बीच काफ़ी समय तक चलता रहा। १९६८ के आक्रमण के समय २४० से अधिक अमरीका से शिक्षण प्राप्त हेती सैनिक इस षडयन्त्र में शामिल थे। हेती के राष्ट्रपति भवन पर जो बम गिराए गए उस बी-२५ हवाई जहाज का संचालन अमरीकी वायु सेना का जय हम्फ्री कर रहा था जो कि अब लेवोन फ्लोरिदा में बतौर तकड़ी के ठेकेदार के काम कर रहा है। क्योंकि सी० आई० ए० धन इत्यादि से षडयन्त्रकारियों की सहायता करती रही है इसलिए राष्ट्रपति दुवालियर को सी० आई० ए० के इशारे पर केब हेती में छाता से उतारने वाली फौज के विरुद्ध लड़ने के लिए दूसरे देशों से हथियार प्राप्त करने पड़े। १९६५ तक हेती ने अमेरिका से कई जंगी जहाज भी अपनी इच्छा के प्रतिकूल खरीदे। १९६३ में राष्ट्रपति दुवालियर और वाशिंगटन के बीच मन-भुटाव शुरू हुआ और तभी से सी० आई० ए० का प्रकोप हेती पर प्रारम्भ हो गया।

कम्बोडिया में प्रिंस सिहानुक का तख्ता उलटने की क्रिया बहुत दिलचस्प है। सिहानुक अपने देश से बाहर गये हुए थे और इससे पूर्व कि अपनी मातृभूमि लौटने के लिए रवाना होते, सैनिक टुकड़ी के एक जनरल लोन नोल ने सिहानुक सरकार का तख्ता उलट दिया। यह पडयन्त्र अकेले लोन नोल के मस्तिष्क की उपज नहीं था बल्कि इस योजना के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। पश्चिमी गुट वाले लोन नोल को अपना 'पुराना और घनिष्ट मित्र' एवं 'सेना में शक्तिशाली' व्यक्ति मानते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि लोन नोल में न तो सैनिक सूझ-बूझ है और न ही शासन करने की योग्यता। यहां तक कि जिस सेना के वह प्रमुख थे उसने कभी भी लोन नोल को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझा। कम्बोडिया से फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त होने के बाद अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर दल-बल सहित कम्बोडिया में प्रवेश किया ताकि कम्बोडिया की धरती को फौजी ग्रहों में बदल कर समूचे हिन्द चीन को अपने अधिकार में कर लिया जाए। लोन नोल ही एक ऐसा सैनिक कर्मचारी निकला जो अमेरिका के इशारे पर चल सकता था। जब सिहानुक ने १९६३ में अमेरिका से मिलने वाली सैनिक सहायता बन्द कर दी थी तो लोन नोल ने इस का विरोध किया था।

लोन नोल को इस बात का ज्ञान था कि सिहानुक आम जनता में सर्वप्रिय हैं इसलिए उसने यही उचित समझा कि सिहानुक की अनुपस्थिति में उनका तख्ता उलट दिया जाए। इस समाचार ने विश्व भर में हलचल मचा दी क्योंकि कम्बोडिया की तटस्थ नीति के सभी प्रशंसक थे।

सिहानुक ने अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि उसका तख्ता उलटने के लिए सी० आई० ए० ने पडयन्त्र रचा। उन्होंने इस बात को बिल्कुल निराधार बताया कि कम्बोडिया में राजनैतिक स्थिति ढाँवाडोल थी जैसा कि कम्बोडिया की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है। सिहानुक ने यह भी आरोप लगाया कि 'राजनैतिक ढाँवा डोल स्थिति' तो केवल एक बहाना है जिसके द्वारा सी० आई० ए० का उद्देश्य पूरा हो सकता है। यदि कम्बोडिया की इस घटना के पीछे अमरीकी पडयन्त्रकारियों का हाथ नहीं था तो अमरीका को जल्दी क्या पड़ी थी कि वह तुरन्त ही कम्बोडिया में लोन नोल सरकार को मान्यता प्रदान कर दे। ऐसा दिखाई देता है कि एक ओर तो सी० आई० ए० ने अपना विध्वंसकारी कार्य पूर्ण किया और उधर वाशिंगटन में तुरन्त इस काम पर सरकारी मुहर लगा दी गई। मशीनगनों की नोकों पर और सगौन के साए सले राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई और इसी अनाधिकृत बैठक

ने सिहानुक की समग्र ताकत अपने हाथ में ले ली। वस क्या था चाड़ू ने खेत को खाने का ठेका अपने जिम्मे ले लिया। पहले तो अमरीका अप्रत्यक्ष रूप से कम्बोडिया में घुस पैठ करता था अब उसे सोन नोल सरकार से घुसपैठ ही नहीं बल्कि सब अधिकारों को हथियाने का लाइसेंस भी मिल गया।

कम्बोडिया में सैनिक विद्रोह इतनी जल्दी क्यों हुआ और किस लिए हुआ इसकी जानकारी आवश्यक है ताकि फिर कभी एशिया की धरती पर साम्राज्यवादियों के पांव टिक न सकें। सर्व प्रथम तो यह कि अमरीकी जंगबाज अमरीका को वियतनाम और लाओस की जग में होने वाली सैनिक क्षति और राजनैतिक हार की पूर्ति करना चाहते थे क्योंकि उन्हें विदित था कि हिन्द चीन में वियतनाम की बहादुर जनता अपनी आजादी के लिए लड़ रही है और लाओस के लड़ाकू लोग जीवन की बाजी लगाकर भी अपने देश को साम्राज्यवादी चंगुल से निकालने का प्रण किए हुए हैं। रह गया प्रश्न कम्बोडिया का यदि सिहानुक का प्रभुत्व रहा तो कम्बोडिया में साम्राज्यवादी हथकण्डे न चल सकेंगे। इसी कारण अमरीका ने हिन्द चीन में अपनी राजनैतिक हार का बदला लेने के लिए सोन नोल सरकार को गद्दी भरी दी। यह ठीक है कि कम्बोडिया पर सोन नोल सरकार का कब्जा है लेकिन आम जनता न तो सोन नोल के साथ है और न अमरीकी नीति के साथ। जिस देश की आजादी को गिरवी रखा जा रहा हो उस स्वाभिमानी राष्ट्र के लोग कुछ समय के लिए भले ही शांत हो जाएं, लेकिन एक न एक दिन तूफान बन कर भवष्य उठेगा और वह दिन दूर नहीं जब समूचा हिन्द चीन साम्राज्यवादी हथकण्डों से मुक्त हो जाएगा।

अमरीका के राष्ट्रपति निकसन ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि "अमरीका शान्ति पर विजय पाना चाहता है" परन्तु वास्तव में यह विजय शान्ति स्थापित करने के लिए नहीं बल्कि एशिया के देशों को चारों ओर से घेरने के लिए अमरीका की नई चाल—“सैनिक विजय प्राप्त करना” है ताकि जिन देशों में इतनी शक्ति है कि वे अमरीकी साम्राज्यवाद का विरोध करने की हिम्मत रखते हों, उन्हें क्षीण बनाया जा सके। जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद कभी पीछे नहीं रहा। यह न केवल दमन चक्र में सहयोगी रहा है बल्कि दमन के लिए हथियार भी देता रहा है। सी०आई०ए०, राज्य सरकारों का तत्त्वा उल्टने के बाद अमरीकी दुम छत्तों की घन इत्यादि से सहायता भी करती है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की आजादी को छीनने के निरन्तर कई प्रयास किए जा चुके हैं परन्तु



हर बार पड़यन्त्रकारियों को मुंह की खानी पड़ी है। भले ही चन्द मुट्ठी भर लोग डालर के मोह-पाश में राष्ट्रीय चेतना को तिलांजली दे दें परन्तु जन साधारण की रगो में बहने वाला रक्त राष्ट्रीय चेतना के अविरल वेग का परिचायक है। लोग अपना बलिदान देकर भी अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं इसलिए यदि इस चिंगारी को थोड़ी देर के लिए दबा दिया जाए तो यह चिंगारी अन्दर ही अन्दर सुलगती रहेगी और समय पाकर अपनी लपेट में उन शक्तियों को लेगी जो राष्ट्र हित के विरुद्ध काम करते हैं।

जान फोस्टर डलेस का सिद्धान्त कि 'एशिया के लोग एशिया वालों से लड़ें' एक सोची समझी साजिश का प्रति रूप था जिसका मूल उद्देश्य यह था कि एशिया के लोगों को उकसा कर, फुसला कर, बहला कर अपने मबोदित राष्ट्रों में विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके। जागरूक एशिया तो चट्टान से भी अधिक शक्तिशाली होगा, एशिया के लोगों में जागरूकता आने का सीधा अर्थ यह होगा कि नव शक्ति का उदयमान होना और जुल्म व अन्याय से टकरा जाना। भला साम्राज्यवादियों को यह स्थिति रुचिकर कैसे लग सकती है? यह ठीक है कि शक्तिशाली एशिया ही साम्राज्यवाद को चुनौती दे सकता है और इसे परास्त कर सकता है।

कम्बोडिया बहुत पहले ही साम्राज्यवादी जगल में फस गया होता यदि राज कुमार सिहानुक अपनी बुद्धिमत्ता और कार्य कौशल से इसे रोक न सकते। कम्बोडिया की राजनीति का अध्ययन करने वाले लोगों को निश्चित ही यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि "इधर तस्ता उल्टा और उधर अमरीका ने 'नई' सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी"। एक ओर तो राष्ट्रपति निक्सन बार बार आश्वासन दिला रहे हैं कि हिन्द चीन से अमरीकी फौजें हटा ली जाएंगी और दूसरी ओर युद्ध की स्थिति बराबर कायम रखी जा रही है। अमरीकी गृह विभाग पर सी०आई०ए० का इतना जबरदस्त नियन्त्रण है कि यह जानना सम्भव नहीं कि भविष्य में किस देश की आजादी पर हमला किया जाएगा और किस सरकार का तस्ता उल्टा जाएगा जो अमरीकी नीति के समर्थक नहीं हैं। सी०आई०ए० की एक निश्चित योजना है कि किस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया में गृह युद्ध छेड़ा जा सके। इस गृह युद्ध के लिए सी० आई० ए० हर प्रकार की सहायता देती है और इन योजनाओं को पूरा करने के लिए तन, मन, धन, से सहायता भी प्रदान करती है।

१९६३ में जान फोस्टर डलेस ने कहा था :—

“वियतनाम की लड़ाई को अलग से नहीं देखा जा सकता, इसका सम्बन्ध हिन्द चीन के भविष्य से जुड़ा हुआ है।”

हिन्द चीन का भविष्य, अमरीकी सैनिक अधिकारियों के अनुसार, तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि पूरा हिन्द चीन टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाए और प्रजातांत्रिक सरकारों का तत्त्वा उत्पन्न कर अपने दुमछत्तों को गद्दी आसीन कर दिया जाए।

१९५३ में राजकुमार सिहानुक ने डलेस को समझाने का विफल प्रयास किया था। सिहानुक ने खुले शब्दों में डलेस को बताया कि स्वतन्त्र और तटस्थ कम्बोडिया वियतनाम और लाओस में शांति स्थापना के लिए प्रयास कर सकता है। इस पर डलेस ने कहा था :—

“जब तक हमारे धनु, वियतकांग, परारत नहीं हो जाते और आपको सम्भवतः इस बात का ज्ञान भी होगा कि किस प्रकार इन्हीं वियतकांग गुरीलों ने तुम्हारे खंभर वन और धानदार परम्पराओं को, तुम्हारी सहूलों एवं पुरानी सभ्यता और तुम्हारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली का सहस्र नहस करके रख दिया है और जब तक यह भयानक खतरा टल नहीं जाता हम फ्रांसिसियों को जिन्होंने हिन्द चीन में हमारी आजादी की रक्षा के लिए भारी क्षति उठाई है, हतोत्साहित नहीं कर सकते। हम इस समय युद्ध के भयंकर भोड़ पर खड़े हैं। हमें अवश्य विजय प्राप्त करनी है।”

डलेस सिद्धान्त ही अमरीकी विदेश नीति का मूलधार रहा है। १९६७ में सी० आई० ए० ने खमेर परिवार के कुछ लोगों की सहायता से एक पडयन्त्रकारी योजना बनाई थी कि यह लोग राजसत्ता अपने हाथ में ले लें। इस पडयन्त्र में थाई लैंड के कई मुख्य अधिकारी भी शामिल थे और उन्होंने थाई लैंड की सीमा के पास अपना भूदा भी जमा रखा था। इस पडयन्त्र का पता एक साल बाद लगा। राज कुमार की सर्वप्रियता से घबरा कर ही लोन नोल सरकार ने सिहानुक के वापिस कम्बोडिया लौटने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

पाकिस्तान को हथियार देने की नीति

अमरीका की सदैव यह नीति रही है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता मिलती रहे ताकि पाकिस्तान के शासक प्रसन्न होकर अमरीकी उदारवादिता के प्रति आभार प्रकट करते हुए पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डे स्थापित करने की अनुमति दे दें। अमरीका जानता है कि पाकिस्तान को हथियार देकर इसने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए—पाकिस्तानी शासक भी खुश हो गए और अमरीकी श्रंगबाज भी। आखिर हथियार तो बेचने ही थे—बजाए नई दुकान खोलने के पाकिस्तान सरकार ने अपनी दुकानदारी अमरीका के पास पट्टे में लिख दी। अमरीकी सरकार सैनिक अड्डे बनाना चाहती थी उसे अड्डे मिल गए और पाकिस्तान के सैनिक शासकों को कुछ और वर्षों तक सत्तारूढ़ रहने का लाइसेंस भी मिल गया।

पाकिस्तान सीटो पैक्ट का सदस्य है और इस नाते अमरीकी गुट में शामिल भी है और चूंकि अमरीका ने आक्राताओं की सहायता देने का प्रण ले रखा है इसलिए पाकिस्तानी आक्राताओं को हथियार देना भी इसी का काम है। जब अमरीकी सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, उस समय भारतीय नेताओं ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को हथियार देने का मतलब है एशिया की शान्ति को भग करवा न्योकि पाकिस्तान इन हथियारों का प्रयोग अवश्य भारत के खिलाफ करेगा परन्तु अमरीकी सरकार ने उस समय आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान ये हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन हथियारों को खेने के बाद जो घिमांजी हरकत की वह इतिहास के पन्नों पर एक कलुपित दाग है। पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ समझ कर भारत पर

आक्रमण किया। यह बात अलग है कि भारतीय जवानों ने हर मोर्चे पर पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए।

कई वर्षों से अमरीका निरन्तर पाकिस्तान को हथियार देता रहा है, कभी स्वयं और कभी अन्य देश के द्वारा। यह जानते हुए भी कि शीत युद्ध की भूमिका रखने के बाद पाकिस्तान इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, चीन के खिलाफ नहीं क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत विरोधी होने के नाते आपस में मिल चुके हैं, फिर भी अमरीका हथियार देने से बाज नहीं आता। यदि अमरीका ने अपनी इस नीति में शीघ्र परिवर्तन न किया तो अमरीका का नाम आते-ही जन साधारण यह सोचने पर विवश हो जाएगा कि आज का अमरीका आक्राताओं का सहयोगी है, युद्ध का समर्थक है और आजादी का शत्रु। जब अमरीका ने पाकिस्तान की हथियारों के लिए प्रार्थना पर विचार करना शुरू किया तो भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को कह दिया था कि उनका यह कदम शान्ति के लिए अहितकर होगा, परन्तु हथियारों की सप्लाई जारी रही।

यह अलग बात है कि अमरीका के हथियार, गोला बारूद और पैटन टैंकों ने जब भारतीय सीमाओं की ओर हल किया तो अमरीकी पैटन टैंकों के सीने भारतीय गोलियों से छननी कर दिए गए। पाकिस्तान का रवैया अपने पड़ोसियों के प्रति हमेशा भिन्न रहा है और सर्वेभ भारत विरोधी। सीटो, सेंटो की सहायता से पाकिस्तान अपने लोगों की हथियारों से 'सेवा' करता रहा है। पाकिस्तान के लोगों को इन्हीं हथियारों के बलबूते पर 'मौलिक प्रजातन्त्र' और 'सैनिक तानाशाही' के बीच गेंद की भाँति उछाला जाता रहा है। जन आन्दोलनों को बुरी तरह से दबाया जाता है और राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगता है। पाकिस्तान में न तो प्रजातन्त्र का बीज प्रकुरित होने दिया जाता है और न ही प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाली संस्थाओं को काम करने का मौका दिया जाता है।

प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता का बोल बाला है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पर बराबर कटाक्ष किए जाते हैं। धर्म के नाम पर पाकिस्तान के शासकों ने पाकिस्तान की जनता को बेबकूफ बनाने की कोशिश तो की ही है चीन जैसे धर्म-विरोधी देश को भी उल्लू बनाया है। कारण यह है कि दोनों देश—चीन और पाकिस्तान—भारत को एक आँख से नहीं देख सकते। भारत का विकास उनकी नजरों में अक्षरता है। स्वतन्त्र भारत की प्रगति उनके लिए शूल है। भारत की

उन्नति को देखकर पाकिस्तान के हृदय में डाह पड़ जाता है। परन्तु सन्तोष जनक बात यह है कि जहाँ पाकिस्तान सरकार का रुख भारत-विरोधी और जनता विरोधी है वहाँ पाकिस्तानी जनता सजग और जागरूक हो रही है और इन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि रोटी की लड़ाई को धार्मिक नारों से छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के समाचार पत्रों में इस बात की बराबर चर्चा होती है कि किस प्रकार सी० आई० ए०, शासन में घुस पड़ कर रहा है।

पाकिस्तान जमाते इस्लामी के महा सचिव अब्दुल खालिक ने यह आरोप लगाया है कि सी० आई० ए० पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक झूठे में परिणत करना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सी० आई० ए० की गतिविधियों पर रोक न लगाई गई तो किसी न किसी दिन पाकिस्तान 'बियतनाम' बन सकता है। उन्होंने अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी पर एतराज वाली कार्यवाहिया करने का आरोप भी लगाया। परन्तु इन गतिविधियों पर रोक तो तब लग सकती है जब सरकार ऐसा करने को तैयार हो। जब सरकार ने स्वयं सी० आई० ए० की गतिविधि के रूप में घर बुलाया हो तो कौन कहे मेहमान से कि : "बाज आए ऐसी मुहब्बत से, उठा लो पाग-दान अपना"

यद्यपि पाकिस्तानी नेताओं ने जागृति देर से आई है परन्तु हम बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में सी० आई० ए० का जाल तेजी से फैलता जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान को अमरीका से हथियार इत्यादि मिलते रहे हैं और इसी प्रलोभन में शामक लोग जनता की भावनाओं की अवहेलना करते रहे हैं। कुछ समय पूर्व अमरीका ने पाकिस्तान को टर्की के माध्यम से १०० अमरीकी टैंक देने का निर्णय किया था। भारतीय संसद में इस विषय पर ध्यान आकर्षित प्रस्ताव द्वारा अमरीकी सरकार को चेतावनी देते हुए संसद सदस्यों ने कहा था कि अमरीका की हथियार देने की नीति शोभ पूर्ण है। जब तक अमरीका की विदेश नीति दूसरे देश के लिए अहितकर रहेगी, उस देश के लोगों को निश्चय ही इस नीति का विरोध करना पड़ेगा चाहे इस दिशा में उन्हें कितना अधिक प्रयास क्यों न करना पड़े। जन-माधारण द्वारा किया गया इस प्रकार का विरोध ही उस देश की इतिहास के पन्नों में जीवित रख सकता है।

इस दिशा में हम देश के लोगों को उनसे भी चौकस रहना पड़ता है जिसका नाम धोरी छिपे उस देश में घुस पड़ कर रहा है। पाकिस्तान में अमरीका की गति-

शाली लाबी है। और इसमें बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ जो दक्षिण पंथी हैं भी शामिल हैं। जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं इतने समझदार निकले कि उन्होंने चीन का पिछलग्गू बनना भी स्वीकार किया और अमरीका का भी। एक कुशल दलाल की भांति वह विक्रेता से भी दलाली खा गए और ग्राहक से भी। उन्होंने चीन को जो आश्वासन दिया उसके बिल्कुल प्रतिकूल अमेरिका को आश्वासन दिया। १९६७ में सी०आई०ए० की सहायता से चलने वाले एक संस्थान ने जुल्फकार अली भुट्टो को काफी धन राशि दी ताकि वह विदेश यात्रा कर सकें।

लाल फीता शाही की सहायता तो सी० आई० ए० करता ही है परन्तु कई प्रमुख अधिकारियों को भी वेतन देकर अपने गुट में शामिल कर लेता है और यही अधिकारी समय पड़ने पर अमरीकी नीति के समर्थन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की समाप्ती के पश्चात, पाकिस्तान पर लाल फीताशाही का ही राज्य रहा है।

पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों पर अपना प्रभाव डालने के लिए अमरीका ने पी० एल० ४८० के अन्तर्गत पाकिस्तान में जमा हुए ५ करोड़ रुपये की धन राशि निकाल ली थी। पाकिस्तान में पी० एल० ४८० के अन्तर्गत लगभग १०० करोड़ रुपये जमा है। अमरीका ने बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रुपये डालरों के बदले में खरीद किए हैं। पाकिस्तान के डालर रिजर्व में पिछले दिनों काफी वृद्धि हुई है यद्यपि पाकिस्तान के निर्यात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही डालर वाले इलाकों में इसका निर्यात बढ़ा है और न ही आयात में वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी नोटों का इतनी बड़ी संख्या में खरीदा जाना मामूली बात नहीं है बल्कि उस योजना का विस्तार है जिसके द्वारा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के चुनाव पर असर डाला जा सकेगा।

पश्चिमी जर्मनी और जापान में भी ऐसी ही स्थिति है। इन दोनों देशों में अमरीकी प्रभाव बहुत हद तक पाया जाता है। वहां लोगों को इस बात की शंका है कि यह सब मिली भगत दोनों सरकारों की मर्जी से ही हुई है। अन्यथा ये देश कैसे अमरीका को अपने देश की घरेलू पर अड़्डे बनाने की अनुमति दे सकते थे। जब तक पश्चिम जर्मनी इस प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता यूरोप में शान्ति स्थापित करना असम्भव है। कुछ समय हुआ भारतीय दूतावास को हिदायत दी गई थी कि वह पाकिस्तान को टैंक बेचने के प्रश्न पर अमरीका से ऊंचे स्तर पर वार्तालाप करे।

ऊचे स्तर का अर्थ है—निर्णय लेने वाला स्तर। सब से ऊंचा स्तर निश्चय ही राष्ट्रपति का हो सकता है। डिप्लोमेटिक स्तर पर इसका अर्थ है—सेक्रेट्री आफ़ स्टेट। परन्तु वास्तव में न तो राष्ट्रपति को अधिकार है निर्णय लेने का और न ही सेक्रेट्री आफ़ स्टेट को, असल शक्ति तो सी० आई० ए० और पेंटागन के हाथ में है जहाँ अन्य किसी व्यक्ति को कोई नहीं पृथक्ता।

अमेरिका चिल्ला-चिल्ला कर एलान कर चुका है कि वह न तो पाकिस्तान को हथियार देगा न भारत को, परन्तु इसके बावजूद पाकिस्तान को काफ़ी मात्रा में पुर्ज सप्लाई किए जा चुके हैं और पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में जो क्षति हुई थी उसको पूरा किया गया है। १९६७ से पहले पाकिस्तान के पास हथियार बन्द गाड़िया भारत से अधिक थी और यदि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को मिलने वाले पुर्जों को पाकिस्तानी कारीगर प्रयोग में ला सकें तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि अमरीका द्वारा हथियार न देने का एलान केवल धोका है और इसकी तह में वास्तविकता कुछ और है।

पाकिस्तान को किसी भी देश से सैनिक आक्रमण का कोई खतरा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में भारत की नीति तो शान्तिप्रिय है, चीन के साथ पाकिस्तान की गहरी मित्रता है। तो फिर पाकिस्तान को हथियार देने का अभिप्राय क्या हो सकता है। पिछले २३ वर्षों में एक बार भी भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। इसके विपरीत पाकिस्तान ने शुरू से ही भारतीय सीमाओं पर छेड़छाड़ जारी रखी है और काश्मीर की घरती पर अनाधिकृत अधिकार कर रखा है। काश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान ने हथिया रखा है और उसका कुछ भाग तो इसने चीन को रेंट रूप में दे दिया है। चोर चोरी के माल को गजों से माप कर नहीं लाठियों से माप कर देता है क्योंकि उसकी कोई हानि नहीं होती। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान ने किया।

१९६५ की मुठभेड़ से पूर्व पाकिस्तान को अमरीका से जो टैंक मिले उनकी कीमत किताबों में कई लाख डालर कम दिखाई गई है। पाकिस्तान का घाटा सैनिक बजट अरिका पूरा कमरीका रहा है। पाकिस्तानी सेना के साढ़े चार डिविज़नों को अमरीका से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और इन लोगों के शिक्षण का सारा खर्च अमरीकी सरकार ने दिया। अमरीका की सहायता से पाकिस्तान में हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, हथियारों के लिए स्टोर बनाए गए हैं और सैनिक सामान भी दिया गया है।

सम्भवतः इसलिए कि पाकिस्तान सीटो, सेंटों और नाटो जैसे सैनिक गुटों में शामिल है।

अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार बन्द गाड़ियां भी दी हैं और अम्पीवीयन गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए भी दी हैं इसके अतिरिक्त सावर, सुपर सावर और हवा से भी तेज चलने वाले हवाई जहाज सप्लाई किए हैं। यह अमरीका की नीति रही है कि एशिया में युद्ध का वातावरण बना रहे ताकि छोटे-छोटे देशों को सैनिक गुटबन्दी में शामिल होने के लिये बाध्य किया जा सके। पाकिस्तान पश्चिमी गुट बन्दी में शामिल है और अमरीका का पिछलग्गु बना हुआ है। इस नीति की झाड़ में पाकिस्तान की यह कोशिश रही है कि कैसे भारत को निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान उस देश से सहायता लेने को तैयार है जो भारत को नीचा दिखाना चाहता हो। चीन और अमरीका का पाकिस्तान के साथ गठ बन्धन कितना विचित्र लगता है? अमरीका सम्भवतः यह समझता है कि वह अपनी नीति से भारत को डरा घमका कर अपने वश में कर सकता है ताकि इतना बड़ा देश साम्राज्यवाद का विरोधी बन कर कहीं साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को इकट्ठा न कर ले और जिससे अमरीका की दुकानदारी बन्द न हो जाए।

ऐसी ही दुकानदारी को चमकाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अमरीका और उसकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्था 'रवात' में मौजूद थी। रवात काण्ड के बारे में विदेशी एजेंटों ने डटकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने का काम किया। भारत में वे राजनैतिक दल, जिन्होंने 'रवात कांड' की चर्चा करते हुए भारत सरकार की विदेश नीति की भर्त्सना की, सरकार विरोधी प्रदर्शन करते रहे। इन प्रदर्शनों के पीछे भी विदेशी हाथ था। क्या ही अच्छा होता यदि ये लोग रवात के प्रदन पर गम्भीरता से विचार करके यह जानने का प्रयत्न करते कि अरब राष्ट्रीयता और मुस्लिम धर्मान्यता जो पैन-इस्लामिज़म का प्रचार करती है उसमें कितना अन्तर है। एक ओर जहां पैन-इस्लामिज़म अरब लोगों में और मुसलमानों में कोई अन्तर नहीं समझता, अरब राष्ट्रीयता इन दोनों को अलग-अलग समझती है। कभी-कभी राष्ट्रीय भावनाओं का जोर हो जाता है और कभी-कभी धर्मान्यता का, चाहे यह थोड़े समय के लिए रहे। धर्मान्यता की सह में उपनिवेशवादी शक्तियां काम करती हैं क्योंकि धर्म के नाम पर ही ये शक्तियां लोगों में बंटवारा करने का दुःसाहस कर सकती हैं। यही कारण है कि धर्म के नकली ठेकेदार सदा 'धर्म खतरे में है' का नारा देते हैं।

इसलिए इन दो विचार धाराओं के बीच संघर्ष में राष्ट्रवादी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए केवल एक ही रास्ता था कि वे राष्ट्रवादी शक्तियों का साथ दें चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। श्री जवाहर लाल नेहरू ने, जो राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रोत्-प्रोत् होकर लोगों को प्रगति के पथ पर चलने का आह्वान देते रहे, अपने जीवन काल में धर्मान्धता का विरोध किया।

पाकिस्तान की नीव धार्मिक रुढ़िवादिता के आधार पर रखी गई और इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने हमेशा भारत-विरोधी रुढ़ भी अपनाया ताकि किसी न किसी बहाने प्रतिक्रियावादी शक्तियां पाकिस्तान की गलत नीतियों पर पर्दा डालती रहे। १९४६ में पाकिस्तान ने पहली अल-मोतमर कांफ्रेंस बुलाई और इसे भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहा। पाकिस्तान ने रुढ़िवादी देशों को इस्लाम के नाम पर प्रगतिशील शक्तियों का विरोध करने के लिए उकसाया। परन्तु जब १९५४ में अरब राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी बौखला उठे और बदलती हुई परिस्थितियों से मुंह मोड़कर अरब देशों में हुई अपनी पराजय का बदला लेने का भरसक प्रयत्न करते रहे। पश्चिमी देशों ने धर्म के नाम पर बलवे कराए, और भाई-भाई के दिलों में घृणा के बीज बो दिए। हमने देखा कि टर्की, ईरान, ईराक, पाकिस्तान और ब्रिटेन ने 'बगदाद संधि' की नींव रखी और इसके माध्यम से भारत और मिस्र का विरोध करना शुरू किया क्योंकि यह दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला कर स्वतन्त्र हुए थे। इस संधि के आधार पर साम्राज्यवादियों ने धर्म का नाम डटकर इस्तेमाल किया। यह अलग बात है कि 'बगदाद पैक्ट' बगदाद में ही दफना दिया गया और १९६४ में अरब राष्ट्रीयता ने मुसलमानों को पैन्-इस्लामिज्म से विमुक्त कर दिया।

१९६७ में जब अरब के लोग पराजित हो गए तो इस्राईल ने यह प्रचार शुरू कर दिया कि अरब वालों की पराजय इस कारण हुई है कि अरब देशों ने 'इस्लाम से विमुक्त' होकर विदेशी विचार धारा अर्थात् समाजवाद को अपनाया है। इस प्रचार का उद्देश्य यह था कि आने वाले दिनों में इस्लाम के नाम पर शिखर सम्मेलन की भूमिका तैयार की जा सके।

इस्लाम धर्म के नाम पर इस्लामिक शिखर सम्मेलन की योजना विफल हो जाती यदि रोहन अल-अक्सा मस्जिद को आग न लगाता। मस्जिद के जलाए जाने खिलाफ लोगों में रोष आना स्वाभाविक था परन्तु इस रोष को नई दिशा देने के

लिए धर्म के ठेकेदारों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहा और इस बात का प्रयास शुरू किया कि धर्म की भाड़ में कोई स्थायी संस्था बनादी जाए या फिर किसी प्रकार का गठ-बन्धन किया जाए। रबात सम्मेलन और अल-अक्सा मस्जिद में भाग लगाने की घटना के पीछे एक सोचा समझा षडयन्त्र था कि किस प्रकार समाजवाद की ओर बढ़ते हुए अरब लोगों के चरण रुक जाएं और पश्चिम एशिया गोपनीय गतिविधियों का केन्द्र बन जाए।

भारत में इसी धर्मान्धता के शिवार भारतीय जन संघ, प्रतिक्रियावादी स्वतंत्र पार्टी और राजनीति में पिछड़ा साए हुए मिण्टीकेट ने वही काम शुरू किया जिसकी रूप रेखा रबात सम्मेलन में रखी जाने वाली थी। एक ही पैली के चट्टे-बट्टे इकट्ठे हो गए और एक ही स्वर में राग अलापते हुए विश्व में राष्ट्रवादी शक्तियों को धीरे धमाने की भावना से मैदान में उतर आए। इन सब पार्टियों को सहायता मिली साम्राज्यवादी टुकड़ों पर चलने वाले समाचार पत्रों से और झूठा प्रचार करने वाले रेडियो से जिसमें बी० बी० सी० भी शामिल था।

रबात सम्मेलन की ओट में ये पार्टियां चाहती थी कि भारत सरकार की शान्ति प्रिय और साम्राज्यवाद-विरोधी नीति का विरोध किया जाए। पाकिस्तान के इशारे पर धर्म के ठेकेदार धर्म-निष्पेक्ष भारत के खिलाफ तो थे ही भारत में भी धर्म के ठेकेदार और उनके पूंजीपति दलाल भारत सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो गए। पूंजीपति इस देश का हो या उस देश का उसकी मनोवृत्ति और काम करने का ढंग एक जैसा है। दोनों शोषक हैं और उनके साये में गरीबी और भूख पलती है, सुख और समृद्धि नहीं। भारतीय हिन्दुओं में जन संघ ने यह प्रचार शुरू किया कि भारत ने रबात सम्मेलन में शामिल होकर इस देश का अपमान किया है परन्तु वे भूल गए कि किसी सम्मेलन में जाने या न जाने से कोई भी राष्ट्र अपमानित नहीं होता। यदि किसी सम्मेलन में कुछ देशों की चाल चलने न दी जाए तो यह स्वयं एक बहुत बड़ी सफलता है। यदि रबात में भारत के प्रतिनिधित्व का प्रश्न न उठता तो पाकिस्तान निश्चय ही इस सम्मेलन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता। जब दो देशों के बीच विचारों का संघर्ष जारी हो तो संघर्ष से घबराकर भाग जाना कायरता है। इसलिए भारत का रबात में भाग लेना आवश्यक था।

किसी भी देश के शान्त वातावरण को दूषित करने के लिए सी० आई० ए० व उसके पिछलगू सदा इस ताक में रहते हैं कि लोगों का ध्यान आर्थिक समस्याओं से हट जाए और वे साम्प्रदायिकता के संकीर्ण दायरे में फंस कर दगे इत्यादि कराते

रहें। विशेषतया उन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे कराए जाते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ताकि सर्वहारा वर्ग की एकता भंग की जा सके। यह सर्व विदित है कि जब सर्वहारा वर्ग के लोग शक्तिशाली होंगे पूँजीवाद अपनी मनमानी न कर सकेगा। यही कारण है कि पूँजीपति व उनके दलाल सर्वहारा वर्ग की शक्ति को क्षीण बनाने के लिए कई ढंग अपनाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि कभी-कभी साम्प्रदायिक व प्रतिक्रियावादी तत्वों की उकसाहट पर इन औद्योगिक क्षेत्रों में दंगे व बलबे होते हैं। जब गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में विश्व के सब लोग शांति के प्रप्रदूत महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भेंट कर रहे थे तो गांधी जी के जन्म स्थान गुजरात में खून की होली खेली जा रही थी। नन्हें मुन्ने बच्चे, बयो वृद्ध पुरुष और स्त्रियाँ और जवान लोम मौत की गोद में सुला दिए गए। यह गांधी जी की 'दोबारा हत्या' करने का प्रयास था। यह कहना अनुचित न होगा कि साम्प्रदायिक दंगों के पीछे विदेशी पूँजी और भारत की साम्प्रदायिक सत्थाएं काम कर रहीं थी। सी० आई० ए० को ऐसे तत्वों की आवश्यकता रहती है जो समय पड़ने पर शांत वातावरण में साम्प्रदायिकता की बिगारी लगा सकें।

गत वर्ष भारत में साम्प्रदायिक दंगे भयानक रूप प्रस्तित्पार कर लेते यदि भारत की जनता सजग और जागरूक न होती। स्थान २ पर राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए 'शांति दल' स्थापित किए गए जिसके परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक तत्वों को मुंह की खानी पड़ी। साम्प्रदायिकता अभिशाप है, वरदान नहीं—यह भावाज हर जगह गुंजने लगी। वातावरण पुनः शांत हुआ और लोगों ने ठण्डे दिल से यह सोचना शुरू किया कि आखिर इन दंगों से उन्हें क्या मिला? कौन रात भर पेट पर पत्थर बांध कर सोया रहा, किस के घर अनाज न होने से चूल्हा न जला, किस की रोखी छीन ली गई, किसका सुहाग लुट गया, किस घर में हाहाकार मच गया, कौन जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया गया? लोग समझ गये कि भारत की इस घरती पर गिरने वाला खून भारतीय था और इसे व्यर्थ बहाया गया। यही रक्त कही भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए बहता तो हमारी पवित्र पावन घरती सहलहा उठती, करोड़ों लोग उस घरती को धूम लेते, इस पवित्र रक्त के कण कण से उस्मान भी पैदा होते और कर्म सिंह भी। मैं भी अपना नत मस्तक करता, पाप भी भाव पूर्ण श्रद्धाञ्जली देते। लेकिन भला यह बताइये कि अहमदाबाद की सड़कों पर साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गिरने वाले खून का क्या बना? जिन लोगों का कारोबार कई दिनों तक ठप्प रहा, उन्हें दंगों से क्या मिला और जो बच्चा अनाथ हो गया वह किस की मां को मा कहेगा।

फासिस्ट प्रवृत्तियाँ

जब साम्प्रदायिकता के दात गढ़ने लगते हैं, फासिस्ट विचार धारा उभरने लगती है। वैसे तो मूल रूप से फासिज्म को एक विचार धारा से संज्ञा दी गई है परन्तु वास्तव में फासिज्म का अर्थ है मानवीय मूल्यों का घटाकर मनुष्य के नैतिक ढाँचे का सर्वनाश करना। जाति व रंग-भेद नीति अपनाने वाले तथा फासिस्ट और तानाशाही शासक 'जीवन के लिए संघर्ष' करने के बहाने राजनैतिक विचार धारा पर आधारित जाति-भेद की नीति को ही बढ़ावा देते हैं। इन लोगों की नज़रों में केवल उन्हीं की जाति के लोग सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च हैं, तथा अन्य जातियों के लोग न तो श्रेष्ठ हैं न सर्वोच्च। इसी नीति को क्रियान्वित करके फासिस्ट संस्थाएं राज सत्ता को हथियाने का प्रयास करती हैं। सत्ता प्राप्त करना बुरी बात नहीं लेकिन यदि गलत तरीके से सत्ता को हथिमाया जाता है यह निश्चय ही निन्दनीय है। जहाँ फासिज्म होगा, वहाँ इन्सान मानवीय मूल्यों का श्राव नहीं कर सकेगा। तानाशाह की आवाज कानून होगी, उसके एक आंख के इशारे से हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे जा सकते हैं और लाखों घर बर्बाद किए जा सकते हैं। तानाशाह की शक्ति असीमित होती है और उस पर जनता का कोई अकुश नहीं होता। तानाशाही में विश्वास रखने वाली किसी भी संस्था ने आज तक खुले रूप से अपना कार्य नहीं किया। गोपनीयता ही उनका मुख्य आधार होता है और 'धर्म व संस्कृति की रक्षा' का नारा ही उनका शक्तिशाली हथियार। वास्तव में न तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा होती है और न ही संस्कृति के प्रति आस्था। केवल धर्म के नाम पर शोषण करना ही इनका परम ध्येय होता है। जहाँ कहीं भी समाजवाद की रचना का प्रश्न उठेगा, प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट संस्थाएं जनता को जन आन्दोलन से अलग

करने का यत्न करेंगी और उन्हें रुढ़िवादी विचारधारा के जाल में फंसाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगी।

जर्मनी में फासिज्म की इंगलिए विजय हुई थी क्योंकि उस देश के पूंजी-पतियो को पहले विश्वयुद्ध में काफी हानि उठानी पड़ी थी। फासिस्टों ने उखड़ते हुए पूंजीवाद को पुनः स्थापित करने के लिए फासिस्ट विचारधारा को जन्म दिया। फासिस्ट सस्था ने पूंजीवाद की डट कर सहायता की और उसके निजी हितों की रक्षा की थी। कारणवश जर्मनी रुढ़िवाद की धारण में चला गया। हिटलर ने सत्ता अपने हाथ में ली और जर्मनी को फिर दूसरे विश्व महायुद्ध में धकेल दिया। कान्ति का विरोध करने वाले लोगों को हिटलर ने आह्वान दिया और देखते ही देखते फासिज्म अपने असली रूप में सामने आने लगा। यहूदियों का कत्ले आम किया गया, उन्हें गैस चैम्बरों में मौत के घाट उतारा गया और बन्दी गृहों में तिल-तिल कर जान देने पर विवश कर दिया गया। यह थी हिटलर की 'सांस्कृतिक विजय' जिमके लिए हजारों लाखों लोगों को यहूदी होने के अपराध में मौत का निशाना बनाया गया। हिटलर की यह इच्छा थी कि यहूदी कौम हमेशा के लिए खरम कर दी जाए। हमने देखा कि किस प्रकार एक के बाद दूसरा देश हिटलर के हाथों पिटा गया। इन देशों पर कोई न कोई बहाना करके चढ़ाई की गई। यह सारी घटना दुःखदायी है और इसके लिए हिटलर और उसके फासिस्ट अनुयायी जिम्मेदार हैं।

पोलैण्ड स्थित आस्विज कैम्प में और उन देशों में जहाँ हिटलर ने दूसरे विश्व महायुद्ध में अधिकार कर लिया था, आदमी, औरतें और बच्चे मौत के घाट उतारे गए। सड़कों पर यहूदियों को कतारों में खड़ा करके जर्मन सिपाहियों द्वारा गोली से उड़ाया गया। यदि हम हिटलर के राज्य हथियाने के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें विदित होगा कि किस प्रकार हिटलर ने नवयुवकों के मन में यहूदियों के प्रति घृणा पैदा की। उसका मन्तव्य था 'छोटी आयु में ही युवकों के मन पर काबू किया जाए' क्योंकि युवकों के अग्रदर साहस भी होता है और खतरे से लड़ने की शक्ति भी। उनकी इस प्रवृत्ति पर काबू पाकर उसे राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। हिटलर ने इसी विचार धारा को लेकर नवयुवकों की अदम्य शक्ति का सहारा लिया और उसी के आधार पर अपने राज्य की नींव रखी। हिटलर को विश्वास था कि जहाँ गड़बड़ हो उसका लाभ उठाया जाए और जहाँ गड़बड़ी न हो वहाँ ऐसे साधन अनाए जाए जिससे गड़बड़ी मच सके। कारणवश लोगो में भकेलेपन और असहाय होने की भावना भर दी गई। लोगो के विचारों में

उनकी इच्छा के प्रतिकूल विचारों को ठूँसा गया। फासिज्म मूलरूप से 'एकाधिकार' का समर्थक है और निराश लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाने का अभ्यस्त भी। फासिज्म लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना जानता है और विशेषतया उस समय जब कि पूँजीवाद पर आधारित एकाधिपत्य देश में सामाजिक प्रशान्ति पैदा करने में सफल हो जाता है। जब इसे विश्वास हो जाता है कि अब अधिक देर तक साम्राज्यवाद की मुर्दा लाश को घसीटा नहीं जा सकता, तो यह लोगों में रुढ़िवादी विचारों का समर्थक बनकर अपना कार्य जारी रखता है।

ऐसी स्थिति बराबर उन देशों में पाई जाती है जहाँ पर तानाशाहों का राज्य है। सी० ब्राई० ए० इन तानाशाहों की हर प्रकार से सहायता करता है। विश्व के सभी फासिस्ट इस बात में विश्वास रखते हैं कि उनकी कौम अभ्य कौमों से श्रेष्ठ है और इसी कारण वे दो कौमों के मिद्धान्त को मान कर उन कौमों के बीच लड़ाई भगडा कराते हैं। सी० ब्राई० ए० का भी यही अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त है कि लोगों में फूट डाली जाए और उन्हें संकीर्णता के दायरे में बन्द कर दिया जाय। सी० ब्राई० ए० फासिस्ट संस्थाओं से तालमेल बनाए रखती है और तानाशाहों की सहायता भी करती है जैसा कि पश्चिम जर्मनी, पुर्तगाल और ग्रीस में हो रहा है। जनता के नेताओं का विरोध करना ही उनका मुख्य काम है ताकि देश प्रगतिशील नीतियों को अपना न सके। अधिकतर फासिस्ट संस्थाएँ केवल इसलिए बनी हैं कि साम्राज्यवाद का विरोध न किया जा सके। अब जब कि एशिया और अफ्रीका में समाजवाद की लहर उठ खड़ी हुई है सी० ब्राई० ए० और उनके दलाल विशेष तौर पर इन प्रगतिशील देशों में सतर्क हो गए हैं और वे उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की खोज में हैं जो उनकी सहायता कर सकें। प्रतिक्रियावादी किसी भी सस्था में हों और किसी भी रूप में हों उनकी मनोवृत्ति एक जैसी है। वे सदैव प्रगतिशील नीतियों का विरोध करेंगे जैसा कि भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के समय हुआ। उनका वर्ग रूप एक जैसा है और उनके कार्य करने की शैली भी एक जैसी है। वे इस बात की ताक में रहते हैं कि कब ऐसा अवसर आए कि वे उन जैसे विचार रखने वाली शक्तियों के साथ सम्भोजता कर सकें।

उनकी दृष्टि में अमरीका में जन अधिकारों की मांग करने वाले लोग प्रजातंत्र विरोधी हैं और जो लोग वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन करते वे 'प्रजातन्त्र के समर्थक'। वे आक्रांताओं की सहायता करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और लोगों की गुलामी को मजबूत बनाना अपना 'राष्ट्रीय कर्तव्य'।

कुर्बान जाएं हम उनकी बुद्धिमत्ता पर ! जनता की भावनाओं की अवहेलना भी करते हैं और जनता की सेवा का दम भी भरते हैं । वे कभी-कभी भावनाओं के वेग में बह भी जाते हैं परन्तु दरयासिन काण्ड पर दो आंसू भी बहा नहीं सकते । यह तो कौम के गम में डूबे रहते हैं परन्तु भाड़ में जाए कौम परस्ती—इनको इस बात की परवाह नहीं । हीरोशीमा और नागा साकी में लाखों लोग अकारण ही बम का शिकार बना दिए जाएं तो इनके कान पर झूँ भी नहीं रेंगती क्योंकि ऐसा करने से उनके मालिक नाराज हो जाएंगे । भारत में भी फासिस्ट टोले ने 'भारतीय करण' का नारा देकर यह सिद्ध कर दिया है कि हिटलर के मरने के बाद भी छोटे-छोटे हिटलर मौजूद हैं जो अपने देश की प्रगति में बाधक हो सकते हैं । उनके नारों के पीछे वास्तविकता कुछ और है । भुंह में राम है तो बगल में छुरी । इन विश्वास घातक लोगों पर कौन अपने देश की बागडोर छोड़ सकता है । कहीं ये सत्ता पर अधिकार कर लें, जो असम्भव है, तो समूचा देश खाई में गिर जाएगा ।

सी० आई० ए० के एजेन्ट नागालैंड, सिक्किम और काश्मीर इत्यादि सीमा प्रदेशों में बहुत सक्रिय हैं क्योंकि ये प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इस बात का प्रमाण मौजूद है कि नागालैंड में देशद्रोहियों की सहायता के लिए पाकिस्तान ने उन्हें हथियार इत्यादि भी दिए ताकि उस स्थान पर अशान्ति बनी रहे । सी० आई० ए० ने ऐसे जासूस भर्ती कर रहे हैं जो इन प्रदेशों से सम्बन्ध रखते हैं । काश्मीर में तो इन्होंने 'आजाद काश्मीर' योजना की भूमिका भरा करने में महत्वपूर्ण कार्य भी किया ।

विश्वविद्यालयों में भी सी० आई० ए० वाले घुस पैंठ करते रहते हैं । जहाँ कहीं उन्हें साम्प्रदायिक तत्व मिलजाए तो बम क्या है मानों कुत्ते को हड्डी मिल गई हो । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में पुलिस ने छापा मार कर बहुत से हथियार अपने कब्जे में लिए । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय जांच समिति के अध्यक्ष श्री बी० पी० गजेन्द्र गड़कर ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला है । इस जांच समिति ने विश्वविद्यालय के प्रबन्धक वर्ग पर आरोप लगाया है कि वे भूतपूर्व प्रबन्धकों में सन्तुलन बनाने के लिए प्रगतिशील और साम पंथी अध्यापकों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकर्ता को खड़ा करते रहे । वह कमरा जहाँ पर संघ का कार्यालय स्थित है, जांच समिति ने उसके सम्बन्ध में लिखा है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यालय साम्प्रदायिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है और इससे दैनिक वातावरण

दूषित होता रहा है। जांच समिति ने पूरे सौच-विचार के बाद यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में बने हुए इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को इमारत को गिरा दिया जाए। जब संघ वालों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने 'खून खराबे' की घमकी दी और इमारत गिराए जाने का विरोध भी किया। यही साम्प्रदायिक तत्व इस बात की ताक में थे कि यदि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संघ के कार्यालय को गिरा दिया तो वे 'विश्वविद्यालय की ईंट से ईंट बजा देंगे'।

यह प्रायः देखने में भी आया है कि जब कभी किसी विश्वविद्यालय में कोई घटना हो तो अमरीकी समाचार पत्र व रेडियो उस समाचार को बुरी तरह उछालते हैं और उनकी यह कोशिश होती है कि अमरीकी रेडियो सुनने वालों को विश्वास हो जाए कि 'भारत सरकार लड़खड़ा रही है' और "भारत के युवक और विद्यार्थी सरकार का तख्ता उलटने के लिए उतारू हैं।" इस प्रकार मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जाती है और सी० आई० ए० को विश्वास होने लगता है कि वह इस लड़ाई में अकेले नहीं बल्कि ऐसे गुट और संस्थाएं भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य सी० आई० ए० के उद्देश्यों से भिन्न नहीं है। दो वर्ष पूर्व जब भारत में कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन, हड़तालें इत्यादि हो रहे थे तो सी० आई० ए० के एजेंट इन्हीं विश्व विद्यालयों में सम्पर्क बढ़ाने का काम कर रहे थे। उस समय की स्थिति का इन्होंने पूरा लाभ उठाया। ऐसा लगता है कि सी० आई० ए० दोनों ओर से सुरक्षित है उग्र धाम पंथी भी सी० आई० ए० के साथ हैं और उग्र दक्षिण पंथी भी। भारत के एक विश्वविद्यालय में जब गर्विले विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा में प्रतिदिन एक अमरीकन को जो कि विद्यार्थी न होकर केवल डिप्लोमेटिक सबिस करता था, देखा तो उन्होंने इस पर भारी रोष प्रकट किया। यद्यपि इस चेतावनी के बाद वह अमरीकन पुनः कक्षा में नहीं आया परन्तु पता लगा है कि अमरीका के एक संस्थान ने उस कालेज को वातानुकूलित बनाने का वायदा किया है इसलिए वह अमरीकी कूटनीतिज्ञ हर प्रकार का लाभ उठाने लगा था। वह कालेज को अपनी पत्रिक सम्पत्ति समझने लग गया था और विद्यार्थियों से ताल-मेल बढ़ाना अपना कानूनी अधिकार परन्तु वह भूल गया कि विश्वविद्यालय की दीवारों पर अमरीकी नारे अंकित करना शायद सम्भव हो ये नारे विद्यार्थियों के दिलों पर अंकित नहीं किए जा सकते।

विद्यार्थी तो स्वभाव से ही विद्रोही हैं वह न तो पैसे से समझौता कर सचता है न अपने विचारों से। उसको डालर की झलक खरीद नहीं सकती, वह स्वाभिमानगी

है और उसकी नसों में बहने वाला रक्त भारतीय है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध है वह उसको सहन नहीं कर सकता। उमे इस बात का दुःख है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सी० आई० ए० घुस पैठ कर रहा है लेकिन शिक्षा का ठेकेदार सो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और न ही किसी विश्वविद्यालय को या कालेज को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वे किसी विदेशी संस्थान से सम्पर्क बढ़ाकर विश्वविद्यालय को या कालेज को पट्टे पर लिख दे।

आज़ादी के शत्रु

अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कैनेडी और जानसन के शासन काल में अन्तर-विभागीय समितियों का गठन इस ढंग से किया गया था कि वे सरकार की बुक्रिया एजसियों पर नज़र रख सकें। सरकार को कई समितियों का गठन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इन सरकारी विभागों के पास वैसे ही काम था जैसा कि सी० आई० ए० के पास। प्रश्न केवल प्रापसी सम्पर्क का था। १९६१ में क्यूबा में वे प्राकृ पिंगज पर हुई अमरीकन पराजय पर सी० आई० ए० की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। कारण यह कि सी० आई० ए० द्वारा दी गई सूचना गलत निकली। इसलिए बोबी कैनेडी के नेतृत्व में एक समिति का निर्माण किया गया जिसका काम सी० आई० ए० के काम की देखभाल करना था। इसी प्रकार जार्जिया के सेनेटर रिचर्ड रसल की नियुक्ति कांग्रेस की ओर से सी० आई० ए० के काम की देखभाल के लिए हुई। राष्ट्रपति के निजि मित्र क्लार्क क्लिफोर्ड के जिम्मे यह काम सगाया गया था कि वह सरकारी तौर पर इन समितियों की जांच करे।

लेकिन, परिणाम क्या निकला? भंसाचुसेट्स इन्स्टीट्यूट प्राकृ टेक्नोलोजी इन कैम्बरिज, जहां पहले रोस्टोव काम करता था ने १९६६ में निश्चय किया कि वह अधिक देर तक सी० आई० ए० के अनुसन्धान केन्द्र में कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्टान फोर्ड के विचारियों ने भी सी० आई० ए० के विद्वविद्यालय स्थित पिट्ट्सबर्ग के विरुद्ध प्रदर्शन किए। कोलम्बिया विद्वविद्यालय और प्रिन्सल कालेज प्राइमोवा के विचारियों ने भी सी० आई० ए० की तीव्र निन्दा करते हुए प्रदर्शन घाटि किए। अमरीका के समाचार पत्रों में भी विपतनाम सम्बन्धी अमरीकन नीति की भर्त्सना की गई। सन्दन के समाचार पत्रों और बाल्कन स्थित रेडियो स्टेशनों

और मजदूरों की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर भी सी० आई० ए० की कड़ी आलोचना की गई ।

आश्चर्य की बात है कि सी० आई० ए० का एक रूप नहीं कई रूप हैं । यह एक और व्यापारिक संस्थाओं के रूप में सामने आती है तो दूसरी ओर हवाई कम्पनियों के माध्यम से । हर काम में इसकी रुचि है और हर स्थान पर इसके पिटुठे बैठे हैं । अमरीका के कूटनीति-विभाग और सी० आई० ए० विभाग में कोई अन्तर नहीं है । एक ही व्यक्ति दोनों विभागों में साथ काम करता है । फ्रांस गणराज्य की स्थापना के लिए सी० आई० ए० ने तृतीय शक्ति "थर्ड फोर्स" की सहायता की । १९४८ के आम चुनावों में ईटली के क्रिश्चन डेमोक्रेट्स की सहायता की । ईरान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री डाक्टर मुसद्दिक और गोटे माला के राष्ट्रपति आर बेन्ज के विरुद्ध पड़पन्त्र रचा । इण्डोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो को सत्ता से अलग करने के लिए विद्रोही लोगों की सहायता की । वर्मा में इसने साम्यवाद-विरोधी चीनी गुरिल्लों को भेजा । १९५० के मध्य में सी० आई० ए० के दलालों ने कोस्टारिका में घुसने का प्रयास किया क्योंकि कोस्टारिका लतीनी अमरीका में सब से स्थायी और प्रजातान्त्रिक देश है । यह सी० आई० ए० के मस्तिष्क की ही उपज थी कि उसने गोटे माला की सरकार से माग की थी कि वह अपने देश में क्यूबा के शरणार्थियों को सैनिक शिक्षण की सुविधा प्रदान करे ताकि ये शरणार्थी पुनः क्यूबा में भेजे जा सकें और अपने देश के विरुद्ध काम कर सकें । सी० आई० ए० ने इन शरणार्थियों को सैनिक शिक्षा दी, धन भी दिया और उन्हें अपने खर्च पर पिगज लाडी में भिजवाया जहां से उन्हें फिडल कैस्ट्रो की राज सत्ता को बदलना था । सी० आई० ए० प्रमुख ने और अमरीकी सेना के प्रमुख अधिकारी ने राष्ट्रपति केनेडी और राष्ट्रपति जान्सन को यह बूढ़ा विश्वास दिलाया था कि सशस्त्र शरणार्थियों के जोरदार आक्रमण से धक्काकर क्यूबा के क्रान्तिकारी शासक हवियार छोड़ देंगे । सी० आई० ए० की जब बुरी तरह असफलता का मुंह देसना पड़ा तो छटी का दूध पाद पा गया । छोटों से देश क्यूबा ने अपनी बहादुरी की धाक दुनिया पर बिटा दी ।

इन सब घटनाओं को देखकर यही लगता है कि सी० आई० ए० अमरीकी सरकार का ही घग है जिसे कई कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है । यह खुफिया विभाग से बढ़कर काम करने वाली मंस्था है । इसी के माध्यम से अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है । यही जिम्मेवार है 'बिना घोषित किए हुए युद्ध' की प्रस्तावना तैयार करने के लिए । यह भ्रूताओं का हवियार है ।

यह ऐसा धिनोना अस्त्र है कि इसे अपने पास रखा नहीं जा सकता। यह न केवल राजनैतिक नियमों और सिद्धान्तों का ही विरोध करती है बल्कि यह नवोदित देशों की आजादी का हनन करने के लिए गुप्त रूप से काम भी करती है। सी० आई० ए० का बजट अमरीकी सैनिक विभाग तैयार करता है। जब 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस' ने ११ मार्च १९६७ को राष्ट्रपति जानसन से मांग की कि वह विद्याविधियों को 'भेद गुप्त रखने' की सौमन्ध से मुक्त करें ताकि वे लोग सी० आई० ए० से अपना नासा तोड़ सकें, यह मांग कोई कम महत्वपूर्ण नहीं थी।

अमरीकी गृह विभाग और सी० आई० ए० निष्कासित व्यक्तियों के सगठनों की सहायता भी करते हैं ताकि इन निष्कासित लोगों की सहायता से उनसे उनके ही देश में शान्ति भग की जा सके। यह ढग अपना कर अमरीकन सरकार अन्य देशों में अपने हितों की रक्षा करना चाहती है। तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष करने के अपराध में यदि कोई व्यक्ति अपने देश से निष्कासित किया गया हो तो उसकी सहायता की बात तो समझ में आती है लेकिन वह व्यक्ति जो अपने देश की स्वतन्त्रता के विरुद्ध काम करने के अपराध में निकाला गया हो उसे अमरीकी अपनी पलकों पर बिठा लें तो उसे कोई भी न्याय समत नहीं कहेगा। सी० आई० ए० का काम वह भी है कि उपनिवेशवाद की जड़ों को मजबूत किया जाए और तानाशाही की सहायता की जाए। अमरीका को शायद विश्वास है कि किसी न किसी दिन इन राज्यों में उल्ट फेर होगा और निष्कासित लोगों की सहायता से वह इन देशों पर अपना प्रभुत्व जमा सकेगा। इसे इस बात की भी आशा है कि इन देशों में सैनिक भर्तु बनाना सरल होगा। वामपंथी किसी भी ढल से सम्बन्ध रखता हो उस की छान बीन का काम भी सी० आई० ए० के जिम्मे है। साम्यवाद का विरोध करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क मामग्री भेजी जाती है उनमें प्रमुल हैं 'प्राग्लेमज माक्र कम्यूनिज्म' अर्थात् 'साम्यवाद की समस्याएं'। यह संस्था उप्रवादी लोगों से भी सम्पर्क रखती है जाहे वे उप्रवादी दाएं बाजू वाले हो या बाएं बाजू वाले। यह जानते हुए कि विषय में सी० आई० ए० की गतिविधियों का भाण्डा घोराने में फूट चुका है, सेनेट की वाचडाग कमेटी के अध्यक्ष मेनेटर बी० रिचर्ड ने सुझाव दिया था कि उन सस्थाओं की आर्थिक सहायता बन्द कर दी जाए जिन पर सी० आई० ए० से घन लेने का आरोप लगा है। सेनेटर फुलब्राईट और अन्य सदस्यों ने भी राष्ट्रपति द्वारा सी० आई० ए० की गतिविधियों पर अंकुश न रखने के प्रति गहरी क्तिता प्रकट की थी।

सी० आई० ए० दोधारी समझार की तरह मार करने की कोशिश करती है। जहाँ प्रजातन्त्र को उखाड़ फेंकना असम्भव हो और सशस्त्र कान्ति आसान हो वहाँ सी० आई० ए० वाले अपनी पिछ्छु सरकार बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। अब यह प्रकट हो चुका है कि विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान केन्द्रों तथा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में सी० आई० ए० घुस पँठ करती है, घन से भी और मन से भी ताकि विश्व में अमरीकी नीतियों का विरोध कम किया जा सके। सी० आई० ए० ने क्यूबा के प्रगति-विरोधी तत्वों जो फलोरीदा में इकट्ठा हुए थे, की सहायता की ताकि वे अमरीकी वायु सेना में बतौर पायलेट भर्ती होकर कागो में राष्ट्रवादियों को पराजित करने के लिए भेजे जा सकें। इस से अधिक रोमाचकारी घटनाएँ भी हैं जैसा कि सी०आई०ए० की सहायता से गायना के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर छेदी जगन का तख्ता उलटना। सी० आई० ए० ने १९६२-६३ में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे कर भारतीयों और नीग्रो के बीच दंगे फसाद कराये थे। जब छेदी जगन का दल जनता के हितों की बात कर रहा था केनेडी सरकार को इस बात का डर था कि कहीं मार्क्सवादी छेदी जगन गायना को 'क्यूबा' न बना दे। इसलिए अमरीका ने यही उचित समझा कि प्रगतिशील विचारों का गला घोट दिया जाए।

सी० आई० ए० विदेशों में अपनी कार्यवाहियों के लिए सरकारी सहायता भी प्राप्त करती है। व्हाइट हाउस के एक प्रतिनिधि का कहना है :—

“कि राष्ट्रपति जानमन को अमरीका के अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट, निकोलास कायजुन बाथ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि सी० आई० ए० ने लाखों डालर विभिन्न सरथाओं को दिए हैं और यह तब कुछ अमरीका की सबसे बड़ी राजनीतिक योजना समिति की नेशनल सक्कुरिटी कौंसिल के आदेशानुसार किया गया है।”

अंगोला, मुजाम्बिक, गिनी बिसाऊ और दक्षिणी रोडेसिया के स्वतन्त्रता सेनानी प्रतिक्रियाधी शक्तियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। स्वतन्त्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए वे लोग कटिबद्ध हैं। वे इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि गुलामी के कीटों को अपनी मातृभूमि पर कदाचित् रेंगने नहीं देंगे। जेलखाने, गोली, लाठी या फाँसी का फंदा उनके अदम्य उत्साह को कम नहीं कर सकता। वे यह भी निश्चय कर चुके हैं कि अन्याय के आगे उनका मिर मुक्त नहीं

सकता, भले ही कट जाए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को तरह-तरह की घातनाएं दी जाती हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाता है, न कोई बदलाती कार्यवाही होती है और न कोई सुनवाई। जंगली कानून राज्य करता है। जिन भां बहिनों का मुहारा लुट गया उन्हें यह भी जानने की अनुमति नहीं है कि उनका एक मात्र सहारा बन्दी गृह में किन हालतों में मौत की गोद में सुला दिया गया? शमशान भूमि को राख भी उनकी इस दुविधा का वसर नहीं दे सकती। आसुओं की अविरल धारा उनके मन को शान्त नहीं कर सकती। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उचित उत्तर नहीं मिल सकता।

जिन देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है वहाँ सी० आई० ए० का यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार इन देशों की आजादी पर कुठाराघात किया जा सके।

न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार विश्व युवक केन्द्र, नेशनल स्टुडेंट प्रेस कांसिल आफ इण्डिया और फोण्डेशन आफ इण्डिया ट्रस्ट को फाऊंडेशन आफ यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज और कैयर बुड फाऊंडेशन की ओर से आर्थिक सहायता मिलती रही है। नेशनल स्टुडेंट्स प्रेस कांसिल आफ इण्डिया के भूतपूर्व अतिरंग सचिव ने अपने एक वक्तव्य में जो हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक २१ फरवरी १९६७ में छपा था, कहा था :

“एक योजना के लिए हमें अवश्य फाऊंडेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज न्यूयार्क से आर्थिक सहायता मिली थी परन्तु हमें किंचित भी फाऊंडेशन-के बारे में कोई सन्देह न था। हमें इस बात का पता न था कि फाऊंडेशन को सी० आई० ए० से सहायता मिलती रही है।”

अज्ञानता के पर्दे में इतनी बड़ी हिमाशय जैसी भूल ! गलती करने के पश्चात् यदि अनुप्य यह निश्चय कर ले कि वह इस गलती को दुहरायेगा नहीं, तो इस भूल को माफ़ किया जा सकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि इस संस्था ने भूलकर भी फाऊंडेशन की विनीती गतिविधियों की निन्दा नहीं की है। इसके बावजूद यदि सहायता प्राप्त करने वाले ‘अज्ञानता’ का द्विदोरा पीट कर अपने असली रूप को छिपाना चाहें तो यह असम्भव है। इण्टर नेशनल स्टुडेंट्स काफ़ेस जो इसलिए भंग कर दी गई है कि इसका सम्बन्ध सी०आई०ए० से था के सचिव भी एक भारतीय रहे हैं।

केनेडा के विद्यार्थियों के प्रमुख नेता डेविड यंग ने खुले तौर पर सी० आई० ए० के विरुद्ध आरोप लगाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों का केनेडा के

विद्यार्थियों द्वारा बुलाने के उद्देश्य के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। जब कभी केनेडा में विचार गोष्ठियाँ बुलाई गईं तो फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज़ ने उनकी धन से डटकर सहायता की, कारण यह कि इन विचार गोष्ठियों में भाग लेने वाले लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को प्रयोग में लाया जाना सम्भव था। केनेडा जैसे देश पर न तो साम्राज्यवादी होने का सन्देह किया जा सकता है न साम्यवादी होने का। उसकी इस नीति का लाभ उठा कर अमरीकी साम्राज्यवादियों की यह कोशिश रही है कि सम्मेलन या विचार गोष्ठी ऐसे स्थान पर बुलाई जाए जहाँ किसी प्रकार की रोक टोक न हो।

अमरीका के 'समाजवादी' नेता नार्मन थामस के विरुद्ध भी यह आरोप लगाया गया था कि उसे सी० आई० ए० द्वारा आर्थिक सहायता मिलती रही है। सी० आई० ए० ने नार्मन थामस की इन्स्टीट्यूट फ़ार इण्टरनेशनल लेबर रिसर्च को १९६१-१९६३ में जे० एम० केप्लन के माध्यम से १० लाख डालर की आर्थिक सहायता दी थी। वास्तव में इस इन्स्टीट्यूट की सभी गतिविधियों का संचालन सी० आई० ए० द्वारा किया जाता रहा है। इसी अनुसन्धान केन्द्र द्वारा कोस्टारिका में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था और मेक्सिको में एक प्रकाशन हाऊस भी। स्पष्ट है कि इस अनुसन्धान केन्द्र द्वारा समाजवाद का प्रचार नहीं बल्कि समाजवाद का विरोध किया जाता था। अतः अमरीका की समाजवाद में किस प्रकार रुचि हो सकती है?

२६ फरवरी १९७० को अमरीका के एक प्रमुख अधिकारी ने वाशिंगटन में ध्वनि करते हुए कहा था कि भारतीय बुद्धिजीवियों को अमरीका का भ्रमण कराने के लिये सी० आई० ए० धन का प्रयोग किया जाना नितांत आवश्यक समझती है। इसी प्रमुख अधिकारी ने 'वाशिंगटन पोस्ट' के सम्वाददाता को बताया था कि यह असम्भव है कि भारतीय बुद्धिजीवी अमरीकी सरकार से सफ़र खर्च लेना मान लें, इसलिए यह आवश्यक है कि यह सहायता ग्रन्थ सूत्रों से दी जाए ताकि इन बुद्धिजीवियों को सहायता प्राप्त करने में कोई बाध न हो। इस अधिकारी ने इस प्रकार दी जाने वाली सहायता का समर्थन करते हुए कहा था कि "भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग विदेशी सरकार से सहायता इस लिए भी प्राप्त नहीं करना चाहते क्यों कि ऐसा करने से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है और उनकी अपने देश में कई प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। उससे बचने का एक सरल तरीका यह है कि उन लोगों को अमरीकी गैर-सरकारी संस्थाओं से सहायता दी जाए ताकि वे अपने आपको स्वतन्त्र व्यक्ति समझ सकें।"

इस जटिल समस्या को मुलभाने के लिए ही सी० आई० ए० ने गैर-सरकारी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना मजूर किया है। एक अन्य संस्था जिसमें सी० आई० ए० की विशेष रुचि रही है वह है—कमेटी फ़ार सेल्फ़-डिटरमिनेशन अर्थात् स्वशासन अधिकार समिति। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं में कांग्रेस फ़ार कल्चरल फ़्रीडम और रेडियो पीस यूरोप प्रमुख हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से भारत और अन्य देशों के प्रतिक्रियावादी तत्वों की सहायता की जाती है। इसी संस्था के माध्यम से कई प्रतिनिधि मण्डल फार्मूमा और सैगोन भेजे जा चुके हैं।

अमरीकी सरकार अमरीकी केन्द्रीय श्रमिक संस्था की धन से इसलिए सहायता करती रही है कि इस संस्था के माध्यम से विश्व के अन्य देशों में श्रमिक संगठनों के साथ सम्पर्क बढ़ाया जा सके। खास तौर पर उन देशों में श्रमिक संगठनों पर अधिक बल दिया जाता रहा है जो देश अर्ध-विकसित हैं। इस से पूर्व अमरीकी श्रमिक संस्था को सी० आई० ए० से सहायता मिलती थी और वह भी तथा कथित संस्थानों के माध्यम से। जब सी० आई० ए० का भेद खुल गया तो कुछ संस्थानों का आश्रय लिया गया। उनका नाम भले ही भ्रम हो लेकिन काम में कोई अन्तर नहीं। वही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वह अब भी है। पैसे के लालच में किस किस का ईमान खरीदने का प्रयास नहीं किया जाता? कोई इस कुकर्म के लिए इन्हें धिक्कारे भी तो क्या? बेशर्मी की हद होती है लेकिन जब कोई इस दाघरे में सीमित न रहना चाहे तो उसके सामने कोई तर्क काम नहीं करता। कौन समझाए इन लोगों को कि जो श्रमिक अपनी मुठ्ठी में अपनी तकदीर समझते हों उन्हें डालर की माया से पथ भ्रष्ट नहीं किया जा सकता?

किसी एक संस्था के बदनाम होने पर तुरन्त नई संस्था बनाने के काम में अमरीका निपुण है। अब धन से सहायता देने का काम एक अन्य संस्था के जिम्मे है जिसका नाम है युनाईटेड स्टेट्स एजेंसी फ़ार इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट। इस संस्था से जिन अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया है उनमें प्रमुख हैं—अमेरिकन रिटेल क्लर्कस इण्टरनेशनल और इण्टरनेशनल फ़ेडरेशन आफ़ पेट्रोलियम एण्ड केमिकल वर्कर्स। इसके अतिरिक्त इस अमरीकी एजेंसी के माध्यम से विभागीय श्रमिक संस्थाओं को अफ्रीका, एशिया और लतीनी अमरीका में कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए धन की सहायता दी जाती है। जब किसी संस्था को आर्थिक सहायता दी जाती है तो उस संस्था से यह आशा की जाती है कि वह गैर-साम्यवादी राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का सहयोग देगी। अब तो आर्थिक सहायता व्यापक रूप में दी जाने लगी

है और छोटी-मोटी कई संस्थाएँ इसका पूर्ण रूपेण लाभ उठा रही हैं। कारण यह है कि इस प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और न ही अन्य देश की सरकार का इसमें कोई दखल है। सोपा सम्पक सहायता देने और लेने वाले के बीच रहता है। जहा-जहा भी सी० आई० ए० को बदनाम होने के कारण हटना पड़ा है, वहा तुरन्त किसी अन्य संस्थाओं के जिम्मे वही काम सौंपा जा चुका है।

बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में सबसे ऊँची और शानदार इमारत उस देश की समाजवादी पार्टी की है परन्तु यही समाजवादी पार्टी अफ्रीका और एशिया में चल रहे आजादी के आन्दोलनों का समर्थन नहीं करती बल्कि प्रतिक्रियावादियों और आजादी के शत्रुओं की सहायता करती है। इस संस्था के अधिकांश सदस्यों को सी० आई० ए० से आर्थिक सहायता मिलती है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नाम पर यह पेशेवर क्रांति-विरोधी लोगों का टोला हो। ब्रसल्स में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रमुख कार्यालय है। इसी नगर में विद्यार्थियों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का भी कार्यालय था जिसे इसलिए भग कर दिया गया क्योंकि इस संस्था के विरुद्ध सी० आई० ए० से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भीषण आरोप था। यह संस्था भग तो कर दी गई परन्तु इसके स्थान पर एक नई संस्था कायम कर दी गई है जिसका नाम है—इन्स्टीट्यूट दि-इण्टरनेशनल इत्युदियां सुर सा-एजुकेशन। संस्था बनते देर नहीं लगती क्योंकि नाम ही तो बदलना है काम में तो कोई अन्तर नहीं होता। ब्रसल्स में तो सी० आई० ए० की गतिविधियां बहुत बढ़ चुकी हैं क्योंकि इस स्थान पर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हैं, विद्यार्थियों, श्रमिकों और युवकों के।

आज के अन्तरिक्ष-युग में सीटो, नाटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठनों का महत्व कम हो गया है परन्तु इन संगठनों के पीछे सी० आई० ए० का हाथ रहने से इन संगठनों की गोपनीय गतिविधियों पर दृष्टिपात करना जरूरी है। सैनिक आक्रमण तो आज के युग में इतना सरल नहीं है जितना कि गोपनीय ढंग से किसी अन्य देश की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्था में घुस पैंठ करना। यही काम सी० आई० ए० का है। सी० आई० ए० का काम है इन्टेलीजेन्स अलायन्स द्वारा सैनिक संगठनों में एकता बनाए रखना, उनकी कार्यवाहियों को बढ़ावा देना और समय पड़ने पर हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना ताकि जो राष्ट्र एक बार इस चंगुल में फँस जाए तो वह बचकर निकल न सके।

ऊंट रे ऊंट ! तेरी कौनसी कल सीधी ? सी० आई० ए० का कौनसा काम धिनीता नहीं ? इसके किस कार्य पर गर्व किया जाए ? सी० आई० ए० राजनीति में ही दखल नहीं देती बल्कि सट्टे बाजों का भी टोला है । इन्ही सट्टे बाजों के माध्यम से हथियारों का सौदा किया जाता है । सट्टे बाजों के कारण ही युद्ध का भीषण वातावरण पैदा किया जाता है और इसका लाभ उठा कर हथियारों का सौदा किया जाता है । जाहिर है जिसका काम हथियार बेचना हो वह चाहेगा कि हथियारों की मांग बढ़ती रहे अर्थात् युद्ध के बादल मँडराते रहें । हथियारों में तेजी और मन्दे की सूचना भी सी० आई० ए० के माध्यम से दी जाती है । यदि कोई देश किसी समाजवादी देश से हथियार खरीदना चाहे या विमान लेने का सौदा करना चाहे तो सी० आई० ए० वाले समाचार पत्रों के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अमुक समाजवादी देश के जहाज काम में नहीं लाए जा सकते । सैनिक समान खरीदने के धारे में, जिसे प्रायः गोपनीय रखा जाना चाहिये, देश के समाचार पत्र टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं ।

हथियार बेचने की होड़ में विचारों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में उन लोगों की सहायता भी जाती है जो रिटायर होने से पहले सरकारी क्षेत्र में अच्छे पद पर रहे हों । फोर्ड फाऊंडेशन ने काम करने वाले व्यक्तियों में अधिकांश लोग वे हैं जो सरकारी अफसर रह चुके हों । काम करने वालों में लायक अधिकारियों की लड़किया आसानी से नौकरी हासिल करती हैं । अधिकारी स्वयं न सही उसकी लड़की उतना ही योगदान दे सकती है । इस आधार पर फोर्ड फाऊंडेशन का काम चलता है । इसके अतिरिक्त सी० आई० ए० ने टेपरिकार्ड और फोटो द्वारा ब्लैकमेल करने का तरीका भी अपनाया शुरू किया है । पश्चिम जर्मनी में लोक सभा के एक बहुत बड़े अधिकारी की वार्ता को टेप रिकार्ड करने के बाद उसे अपने राष्ट्र के विरुद्ध काम करने के लिए कहा गया । पाश्चात्य देशों के दूतावासों में सी०आई०ए० से सम्बन्ध रखने वाले लोगों का जाल बिछा रहता है । शायद ही कोई पाश्चात्य देश ऐसा होगा जिसके दूतावास में सी० आई० ए० के एजेंट न हों । यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि अमरीकी कम्पनियों ने अन्य देशों में बड़े २ समाचार पत्रों में हिस्से खरीद रखे हैं । टेलीवीजन कम्पनियों पर भी इसी प्रकार नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है । फ्रांस जैसे देश में जहाँ फ्रांसीसी भाषा का जोर है दूर देहातो में अंग्रेजी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों की भरमार है । इन समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों में इतनी ताजगी होती है कि यह समाचार

पत्र लन्दन टाइम्स और वी० वी० सी० से भी पहले समाचार प्रसारित करते हैं। फ्रांस में जनरल दी गाल के बाद सी० आई० ए० का इस प्रकार विस्तार फ्रांस के देशभक्तों के लिए एक चुनौती है।

ब्रिटेन में गिरजाघरों के अन्दर जितनी सजीदगी पाई जाती है अमरीकी ढंग पर बने हुए गिरजाघरों में नहीं। अमरीकी ढंग के बने गिरजाघरों में फ्राई-रूम भी है, बाल-रूम भी और प्रार्थना कक्ष भी। यही कारण है कि धर्म के इन ठेकेदारों की कोई बात समझ में नहीं आती। फलस्तीन में यदि यहूदी, मस्जिदों और पवित्र स्थानों को फोड़ा स्थलों में बदल कर प्रेमी और प्रेमिकाओं के केन्द्र में परिवर्तित कर दें तो यह दुःख की बात तो अवश्य है आश्चर्य का विषय नहीं। क्योंकि ईसाई सरकार भी अमरीकी साम्राज्यवादियों के इशारों पर इन्हीं पूजा स्थलों को गलत कामों के लिए प्रयोग में ला रही है। अमरीका में नए पोढी के लोगों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार वे Humour with God and Fun in the Church अर्थात् भगवान के साथ दिल्लगी और गिरजाघरों में हसी मजाक का चरितार्थ कर सकें। नौजवान लड़के और लड़कियां इन केन्द्रों में जाती हैं जहाँ धन का प्रयोग पानी की भाँति किया जाता है। जरा सोचिए, इन गिरजाघरों के पास इतना धन कहाँ से आया? यह भगवान की अनुकम्पा है या फोर्ड फाउंडेशन की, यह भगवान का नियम है या सी० आई० ए० का। किसका अधिकार है इन भगवान के घरों पर, भगवान का या पूँजी के दलाल का? यीशू मसीह की आत्मा इनको आशीर्वाद देती होगी या धिक्कारती होगी। पाश्चात्य सभ्यता के रंग में डूबे हुए कुछ धनवानों ने खुदा को भी अपनी तिजोरी में बन्द कर रखा है और वे नहीं चाहते कि उनके आडम्बरो का भाण्डा फोड़ा जाए। लेकिन कब तक? जब तक इन्सान सोता है, उसके जागते ही यह नकली पहरेदार या धर्म के ठेकेदार दुम दबाकर भाग जाएंगे। हमारी धारणा है कि अमरीकी ढंग के गिरजाघरों से या तो हिप्पी पैदा होंगे या डकेट, धर्म में निष्ठा रखने वाले इन्सान पैदा नहीं हो सकते। सी० आई० ए० की यही कोशिश रहती है कि पहले देश की संस्कृति को निपुंसक बना दिया जाए और फिर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम पर उस देश में धुसपैठ की जाए। जहाँ सी० आई० ए० का बोल बाला हो जाए तो समझ लीजिए कानून को छुट्टी मिल गई। आपको अधिकार है किसी का गला दबोचिए या किसी का गौरव छीनिए। अगर आप शान्ति चाहते हैं तो घर की चार दिवारी में बन्द रहिए, रात को बाहर मत निकलें अन्यथा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकेगा। अगर आप यह नहीं चाहते तो सी० आई० ए० और उस जैसी

अन्य संस्थाओं को चोर दरवाजे से भी अपने देश में मत घुसने दीजिए। श्री लंका में सी० आई० ए० की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। क्यूबा के बहादुर लोगों ने सी० आई० ए० की हालत खराब कर रखी है। जासूसी करने के लिए पकड़े गए अमरीकी सैनिकों ने स्पष्ट रूप में बताया है कि क्यूबा के खिलाफ अमरीका, प्रशिक्षण केन्द्रों से जासूसी की ट्रेनिंग देकर भेजता है। वे लोग जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनमें से अधिकांश लोग सी० आई० ए० के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं।

कांगों में पेट्रिक लुमुम्बा की हत्या के पीछे भी सी० आई० ए० का हाथ था क्योंकि पेट्रिक लुमुम्बा के नेतृत्व में साम्राज्यवाद को मुह की खानी पड़ी थी। लेकिन धर्म की बात है कि लुमुम्बा के हत्यारे शोम्बे को सी० आई० ए० के संरक्षण में एक बार कटंगा से प्रसन्न ले जाया गया और वहां से ही कांगों के प्रगतिशील आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई गई। उठते हुए राष्ट्रों की प्रगति को रोकने के लिए राष्ट्रीय नेताओं की हत्या करने या उन्हें अपमानित करने की योजना सर्वथा निंदनीय है। भारत में भी पाश्चात्य देश के दूतावास के एक सेबर अटेची ने पैसा देकर एक भारतीय मजदूर नेता से प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ घृणास्पद पोस्टर लगवाया था। जब इस बात की खोज हुई तो उस अटेची को भारत छोड़ना पड़ा।

कौन सा धनीना काम ऐसा नहीं जिसे सी० आई० ए० न करता हो? इन कार्यवाहियों के केन्द्र हैं धर्म के नाम पर चलने वाले कहीं-कहीं वाई० एम० सी० ए० या वाई० डब्लू० सी० ए० के होस्टल। यह सही है कि होस्टल के प्रबन्धकों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कौन इस होस्टल में टिकता है और उसकी क्या दिनचर्या है लेकिन यह बात सत्य है कि इन होस्टलों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है क्योंकि संस्कृति या सम्यता का विरोध कौन करेगा? इतनी बड़ी शानदार संस्था को इस्तेमाल करने में भी सी० आई० ए० को कोई धर्म नहीं आती।

नाईजीरिया में 'बांटो और राज्य करो' की नीति के आधार पर नाईजीरिया के एक प्रान्त बायाफ्रा के लोगों को भड़का कर, फुसला कर, स्वतन्त्र रहने का चकमा देने के पीछे भी सी० आई० ए० का हाथ था। नाईजीरिया की आजादी को खतरे में डालने की यह साम्राज्यवादी चाल थी। मोले भाले लोग फस गए। पृथक बायाफ्रा आन्दोलन में नाईजीरिया और बायाफ्रा के कई लोग मारे गए। बायाफ्रा को पृथक रखने की मांग करने वालों का समर्थन सी० आई० ए० और साल चीन के लोग

करते थे। दो साम्राज्यवादियों के बीच समझौता इस लिए हुआ कि दोनों आजादी के दावु हैं। सी० आई० ए० और तान चीन के इरादों में कोई भ्रंतर नहीं। एक पश्चिम से उठा है पाश्चात्य सभ्यता का लिबास पहन कर, दूसरा पूर्व से उठा है शांति का रूप धारण कर के। दोनों आजादी के सूर्य को उदीयमान होता नहीं देख सकते। एक माधो-वाद का गुलाम है तो दूसरा साम्राज्यवाद का। प्रकट रूप में दोनों एक दूसरे के प्रति विरोधाभास दिखाते हैं लेकिन हैं मिनी भक्त। एक तेल फेंकता है तो दूसरा भाग लगाता है। एक विस्तारवादी है तो दूसरा पूर्ण रूपेण साम्राज्यवादी। नाईजीरिया में ऋग्ड़े का कारण उस देश के खनिज पदार्थ थे। चीन, अमरीका और ब्रिटेन की नजर खनिज पदार्थों पर थी और यही कारण है कि वे बायाफ्रा के पृथक रहने की मांग को लेकर खनिज पदार्थों की बांट के लिए समझौता कर रहे थे। नाईजीरिया की राष्ट्रवादी सरकार ने पूरी शक्ति के साथ बायाफ्रा को अलग करने की मांग का विरोध किया। विजय राष्ट्रवादियों की हुई, चीन हार गया, अमरीका को मुंह की खानी पड़ी, सी० आई० ए० की चाल बेकार हो गई।

स्वतन्त्र देश में अन्दर ही अन्दर पृथकतावादी आंदोलन की मांग को सुलगाने का काम करते हैं सी० आई० ए० के एजेंट, क्योंकि वे जानते हैं कि पृथक्तावादी आंदोलन से ही आजाद देश की शक्ति को क्षीण किया जा सकता है। जब साम्राज्यवादी शक्तियां परास्त हो जाती हैं तो वे 'बांट-बंटवारे' की नीति के बीज बोकर तमाशा देखती हैं। इसी प्रकार जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो नागालैंड में ऐसी पृथक्तावादी शक्तियों की सहायता करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने कई हत्यकण्डे अपनाए। फिजो भारत से फरार हुआ तो ब्रिटेन में एक पादरी की शरण में पहुँचा। नागालैंड में काफी समय तक विद्रोही नागाओं ने हुलडबाजी की। सी० आई० ए० के एक एजेंट जानस्मिथ के कथनानुसार १९५६ में सी० आई० ए० ने अपने एक एजेंट को टेक्नीकल कोओपरेशन मिशन के नाम पर अमरीकी मिलिट्री भटेची के साथ इम्फाल भेजा था और उन्होंने वहाँ कई विद्रोही नागाओं से भेंट भी की थी। जानस्मिथ का कहना है कि अमरीकी भटेची ने नागाओं को दस लाख रुपये की कीमत के हथियार दिए और उन्हें कहा कि जब तक अमरीकी सहायता नहीं पहुँचती वे विद्रोह जारी रखें। इसके अतिरिक्त ढाका स्थित अमरीकी कॉन्सिल जनरल और सी० आई० ए० एजेंट की पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही नागाओं के साथ खुफिया बातचीत भी हुई और इसी मीटिंग में विद्रोही नागाओं को अधिक सहायता और

हिदायतें भी दी गई। नागा विद्रोहियों को हथियार देने का काम एक अन्य सी० आई० ए० एजेंट जोसफ म्कालर के जिम्मे था जो पूर्वी पाकिस्तान से हथियार भेजता था। इस काम में जोन ग्रीवर सहयोगी था और देहली में उनका सम्बन्ध बलारा पापास से था।

जिन लोगों ने नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण एवं हथियार दिए उनमें डेविड हेनरीग्लो का नाम उल्लेखनीय है जो १९५० में पाकिस्तान में अमरीकी प्रतापास में घटेची बन कर आया और भारत व पाकिस्तान में सी० आई० ए० की गतिविधियों में ताल मेल बढ़ाने का काम करता रहा। यह व्यक्ति १९६२ में दिल्ली भी आया था। स्मिथ ने यह भी बताया कि सी० आई० ए०, नागा विद्रोहियों की सहायता करने के अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भारत विरोधी कार्यवाहियों को भी प्रोत्साहन देती थी। इस काम की देख रेख डेविड बरगस करता था जो १९५६ को भारत आया और जिसने कई बार नागालैंड के उन इलाकों का दौरा किया जहां प्रयुक्तवादी आंदोलन चल रहा था इस कार्य में चैपमेन उसका सहयोगी था।

स्मिथ ने जैक कुरान का भी जिक्र किया है जो सारे भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों का ईंचार्ज था। १६ नवम्बर १९६७ की इण्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचार के अनुसार जैक कुरान वही व्यक्ति है जिसने इन्स्टीट्यूट ऑफ़ पैसेफ़िक रिलेशनज न्यूयार्क की ओर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में पुस्तक छपी है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि यह पुस्तक १९५१ में छपी जब जैक कुरान भारत आया हुआ था। जैक का जन्म चीन में हुआ, बर्मा में उसकी परवरिश हुई और भारत में सामाजिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सी० आई० ए० से ग्रांट लेकर आया।

आखिर सी० आई० ए० ने नागा विद्रोहियों की सहायता क्यों की? इस पर विचार करना आवश्यक है।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया उठ जाने के बाद भारत को जो कुछ विरासत में मिला उसमें लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी शामिल थे जो अनपढ़ थे और छद्मवादिता का शिकार थे और जो किसी भी समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न देख सकते थे। अंग्रेजों ने उन्हें जान बूझकर अज्ञानता के दायरे में बन्द रखा

और जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इन्ही अज्ञानता के पिजरे में बन्द लोगों को साम्राज्यवादियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साम्राज्यवादी हत्कण्डों में प्रमुख स्थान मिलता है सीमाओं पर छेड़खानी करने की। सीमाओं पर गोला बारूद चलता रहे इस काम के लिए सीमा पर विद्रोह करने वाले लोगों की धन, प्रशिक्षण और हथियारों से सहायता की जाती है।

नागालैंड में नागाओं को उकसाने के लिए भी सी० आई० ए० ने यही काम किया। साम्राज्यवादियों को ख्याल था कि घघकता हुआ नागालैंड भारत की आजादी को कमजोर कर देगा लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। नागालैंड के देशभक्तों ने न केवल विद्रोहियों के दात खट्टे कर दिए बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि साम्राज्यवादियों की कमीनी हरकतों का नागालैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

इसी प्रकार सी० आई० ए० की यह कोशिश रही है कि भारत की उत्तरी सीमा पर उथल पुथल होता रहे और अपने इस प्रयास से सफल बनाने के लिए सीमा पार क्षेत्रों में सी० आई० ए० के एजेंट तखरीबी कार्यवाहिया करने में संलग्न रहते हैं। 'आज़ाद काश्मीर' सरकार तो पिट्टु सरकार है ही, इसका सब काम पिछलग्गुओं का है। काश्मीर के बारे में भारत की नीति बहुत स्पष्ट रही है और इस नीति की हर जगह सराहना हुई है। भारत कह चुका है कि वू कि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वे भारतीय क्षेत्र से तुरन्त हट जाए।

कभी २ 'आज़ाद काश्मीर' का नारा भी सुनने में आता है। यह नारा उन लोगों की ओर से लगाया जाता है जो आजादी के दावु हैं और चाहते हैं कि काश्मीर विदेशी शक्तियों के हाथ में बटपुतली बन जाए और भारत की आजादी के लिए हमेशा खतरा बना रहे। चाहे रायशुमारी मोर्चा हो या कोई और सस्या, काश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करने वाले विदेशी शक्तियों के हाथ खेल रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकार अपने देश में इन तत्वों को सहन नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र में जब भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने तर्कों के साथ पाकिस्तान की धोधी दलीलों का मुंह तोड़ उत्तर दिया तो पाकिस्तान के अतिरिक्त साम्राज्यवादी अमरीका और बर्तानिया भी बीससा उठे थे। परिसाम स्वरूप जब कृष्णा मेनन ने १९६२ और १९६७ का चुनाव लड़ा तो सी० आई० ए० वालों ने कृष्णा मेनन का विरोध करने के लिए अपनी शक्तियों के मुंह खोल दिए। अमरीकी

पसा पानी की तरह बहाया गया ताकि कृष्णा मेनन चुनाव जीत न सकें। कृष्णा मेनन की जीत साम्राज्यवादियों की हार होती। चुनावों की सी० आई० ए० ने अपने भारतीय एजेंटों की सहायता से चुनाव को जिंदगी और मौत का प्रश्न बना लिया।

२३ नवम्बर १९६७ को लोक सभा में स्मिथ के ब्यान पर विस्तृत चर्चा हुई। लोक सभा के कई सदस्यों ने मांग की कि 'काश्मीर प्रिसेस' नामी भारतीय हवाई जहाज में विस्फोट के बारे में जिन भ्रमरीकी अधिकारियों का नाम स्मिथ ने अपने ब्यान में लिया है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है? सदस्यों ने यह भी जानना चाहा कि वह भ्रमरीकी कौन है जिस पर विस्फोटक कार्यवाही का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्री यशवन्तराव चव्हाण ने संसद में बताया कि वह व्यक्ति भ्रमरीकी दूतावास का अधिकारी है और अब भी वहीं काम करता है। 'काश्मीर प्रिसेस' नामी भारतीय हवाई जहाज के साथ १९५५ में दक्षिण-चीनी समुद्र में दुर्घटना हुई थी जिसकी जिम्मेदारी सी० आई० ए० पर है। स्मिथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसने स्वयं, बिना जाने हुए, दो टाईम बम, कोमिटिंग चीन के एक व्यक्ति को जो हांगकांग में काम करता था को देने के लिए भेजे। यह सब क्यों किया गया? इसके बारे में जानकारी देते हुए स्मिथ ने कहा कि १९५५ में घटना से कुछ दिन पूर्व दिल्ली स्थित भ्रमरीकी अटैची ने कहा था: 'स्मिथ! मुझे आपकी सेवाओं की आवश्यकता है क्योंकि मैं अपने एक मित्र को तुरन्त ही कुछ भेजना चाहता हूँ।' उस अटैची ने दिल्ली के होटल का जिक्र करते हुए कहा कि उस होटल में कोई व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे कहना कि 'मैंने यह पैसा आपके पास भेजा है।' वह पैसा भारी था और जब स्मिथ ने उस अटैची से पूछा कि इस पैसे में क्या है तो उसने उत्तर दिया कि वह स्वयं भी नहीं जानता और यह पैसा बन्द किया हुआ मिला है और उसे यह हिदायत दी गई है कि वह इस पैसे को खोले बिना ही भ्रमुक व्यक्ति के पास भेज दे। स्मिथ ने हिदायत अनुसार वह पैसा निश्चित व्यक्ति को जाकर दिया। स्मिथ ने आगे चलकर यह भी बताया है कि उसके विवाह के उपरान्त उसकी धर्म पत्नी, जो सी० आई० ए० की एजेंट थी, ने उसे बताया कि उस पैसे में दो टाईम बम भेजे गए थे, वे बम हांगकांग से 'काश्मीर प्रिसेस' नामक हवाई जहाज में रखे गए। यह हवाई जहाज विस्फोट होने के कारण, उड़ान के आधा घंटे बाद ही समुद्र में गिर कर तबाह हो गया। यह जहाज हांगकांग से इण्डोनेशिया जा रहा था और रास्ते में ही उसके साथ यह दुर्घटना हुई।

स्मिथ ने यह भी बताया कि भारत के भूतपूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को

चुनाव में हारने के लिए सी० आई० ए० ने लाखों डालर खर्च किए। सी० आई० ए० कृष्णा मेनन का इसलिए विरोध करती रही है क्योंकि कृष्णा मेनन ने काश्मीर की समस्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र में साम्राज्यवादी चालों का भाण्डा फोड़ा था। परिणाम स्वरूप १९६२ के आम चुनाव में कृष्णा मेनन का डटकर विरोध किया गया परन्तु सी० आई० ए० के हत्यकण्डे असफल रहे। १९६७ में बम्बई चुनाव क्षेत्र में वही बात दुहराई गई जिसके कारण दो बार बम्बई से कृष्णा मेनन की हार हुई।

सी० आई० ए० की गतिविधियों को लेकर २३ नवम्बर १९६७ को भारतीय संसद में काफी चर्चा हुई थी। इस दौरान सदस्यों ने यह भी माग की थी कि जिस व्यक्ति के बारे में स्मिथ ने चर्चा करते हुए उसे 'काश्मीर प्रिसेस' की दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है क्या वह व्यक्ति अमरीकी दूतावास का अधिकारी है? केन्द्रीय गृह मन्त्री ने उत्तर देते हुए बताया था कि वह व्यक्ति अमरीकी दूतावास में काम करता था। गृह मन्त्री ने यह भी बताया था कि तीन अमरीकी सस्थानों—फोर्ड फ्राऊडेशन, राक फ़ीलर फ्राऊडेशन और एशिया फ्राऊडेशन—को गैर-नारकारी सस्थानों और ट्रस्टों से आर्थिक सहायता मिलती रही है और मजे की बात यह है कि इन सस्थानों की आर्थिक सहायता सी०आई०ए० करती है। यह तिकड़मबाजी नहीं तो और क्या है? गृह मन्त्री ने जोरदार शब्दों में कहा था कि इन सस्थानों को मनमाने करने की छूट नहीं दी जा सकती और आर्थिक सहायता के इस कुकर्मि जाल को फँसने से रोका जाएगा।

अमरीकी खुफ़िया विभाग ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दिल्ली में केन्द्र स्थापित करके अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना शुरू किया था। इस बात की चर्चा करते हुए स्मिथ ने यह भी कहा है कि भारतीय सरकार को विवश होकर एक अमरीकी अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश देना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति की गतिविधियाँ भारत-विरोधी थीं। इस अमरीकी अधिकारी का नाम रोज़ीकी बताया जाता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सी० आई० ए० का काम अन्य देशों में ऐसी कार्यवाहियों को बढ़ावा देना है जिससे वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर न हो सके। यह उन लोगों की सहायता करता रहा है जो जवाहर लाल नेहरू की प्रगतिशील नीतियों के विरोधी थे और जो अब भी इन्दिरा सरकार का विरोध इसलिए करते हैं कि देश से गरीबी को हटाने की योजनाएँ सफल न हो सकें।

राजनैतिक दबाव की नीति

किसी भी देश की राजनैतिक परिस्थिति में कब और कैसा मोड़ आ जाए इसके बारे में भविष्य वाणी नहीं की जा सकती भले ही थोड़ा बहुत भ्रन्दाजा लगाया जा सकता हो। भारत में जब दल बदलने वालों की हरकतों से ऐसा भ्रन्दाजा लगाया जाने लगा कि शायद राजनीति में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है तो सी० आई० ए० ने अपनी गतिविधियाँ राजनैतिक क्षेत्र पर प्रभाव डालने के लिए अधिक तेज कर दी। सबसे पहले यह मान कर कि मन्त्री तो बदल सकते हैं, मन्त्रालय में काम करने वाले प्रमुख अधिकारी नहीं, सी० आई० ए० ने यह उचित समझा कि वह प्रमुख अधिकारियों के माध्यम से उपयुक्त सूचना भी हासिल करे और साथ-साथ उन्हें अपना पिछलग्नु भी बना ले।

सी० आई० ए० की नीति में यह तीसरा मोड़ था। पहले राजनैतिक दलों को गाँठा गया, फिर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों को और इसके पश्चात् लाल फीताशाही के जन्मदाताओं को।

भारत में अधिकारी वर्ग आरम्भ से ही प्रभावशाली रहा है और उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। अब भी अधिकारी वर्ग यही समझता है कि सरकार उनके ही बल बूते पर चल रही है। सरकार गुल्त काम करे तो स्वाभाविक है कि लोग सरकार-विरोधी होंगे, उनको क्या मालूम कि सरकार की मशीनरी के पुर्जों को जग लगा हुआ है और लाल फीताशाही अपनी मनमानी करती है। हम सब अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराते परन्तु उन लोगों की आलोचना किए बिना नहीं रह सकते जो भ्रन्त तो भारत का खाएं और गुणमान अमरीका का करें। पेंशन सरकार से हासिल करें और रिटायर होने के बाद नौकरी टाटा या बिरला की या किसी

विदेशी फर्म की करें। जब तक सरकारी नौकरी में रहें सेवा पूर्जापतियों की करें और नौकरी से मुक्त होने के बाद चाकरी उन लोगों की करें जो इनके पूर्व-सरकारी सम्बन्धों का लाभ उठा कर कोटा और परमिट हासिल कर सकें।

हाथी जिन्दा लाख का और मरा हुआ सवा लाख का ! यह अधिकारी रिटायर होने के बाद भी उतना ही वेतन पा लेते हैं जितना उन्हें पढ़ने मिलता था। दुःख तो इस बात का है कि जब एक अधिकारी सरकारी नौकरी के दौरान विदेशी फर्मों से सम्बन्ध जोड़ता है और रिटायर होकर उस विदेशी फर्म में काम करने को राजी हो जाता है। कुछ समय से विदेशी एजेंसियों ने यह धन्धा शुरू कर रखा है कि बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों, उनकी धर्म पत्नियों और बच्चों को किसी न किसी बहाने विदेश भिजवाते हैं तथा इस प्रकार सम्पत्ति बढ़ा कर उनसे लाभ उठाया जा सके।

भारत में लाला फीताशाही को दो सरकारों के आधीन कार्य करने का तजुरबा हासिल है, एक सरकार विदेशी थी और दूसरी देशी। इसलिए हम यह नहीं मानते कि इन लोगों को विदेशी कुचक्रों का ज्ञान नहीं है। विदेशी एजेंसियाँ लोगों को राष्ट्र विरोधी जाल में फसाकर इन लोगों से अपने ही देश के विरुद्ध जासूमी करने के लिए तैयार करती हैं।

आश्चर्य का विषय है कि लगभग ५०० से ६०० अधिकारी इस समय तक विदेश यात्रा के लिए विदेशी एजेंसियों के कृपा पात्र बन चुके हैं। मजे की बात यह है कि वे अधिकारी जो अधिक तजुरबा हासिल करने के लिए विदेश जाते हैं, उनके इस तजुरबे का लाभ हमारे देश को नहीं होता। अधिकांश लोग तो सेवा से निवृत्त होने के कुछ मास पहले ही विदेश यात्रा की योजना बनानी आरम्भ कर देते हैं। वे लोग जो आधुनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गए हैं निश्चित ही भारत लौटने पर उनकी यह धारणा बन गई होगी कि उससे कम जानकारी देने वाले हमारे देश में नहीं हैं। प्रश्न उठता है कि विदेशों में शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकारी वर्ग को क्यों प्रेरणा दी जाती है ? कारण यह है कि इन अधिकारियों के माध्यम से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है। वरना कौनसा ऐसा काम है जिसकी विशेष शिक्षा विदेश में ही दी जा सकती हो, देश में नहीं ? क्या हमारे विश्वविद्यालय किसी देश के अन्य विश्वविद्यालयों से कम ख्याति प्राप्त हैं ? फिर भी अधिकारी वर्ग पर विदेशी शिक्षण का भूत सवार क्यों ? हम मानते हैं कि

उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हुमा करती है लेकिन उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख देना अमानुषिक है। विदेशी छात्राणिकों पर अधिक निर्भर रहने से राष्ट्रीय गौरव को ठेस लग सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जब इण्डो-यू० एस० एजुकेशनल फ्राऊडेशन की योजना पेश की गई थी तो उस समय इस सुझाव का डटकर विरोध हुआ था क्योंकि यह योजना शिक्षा प्रणाली में सुधार या शिक्षा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से लोगों के दिल और दिमाग पर काबू पाने के लिए बनाई गई थी।

लेद का विषय है कि जिन देशों की खुफिया कार्यवाहियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए उन्ही देशों में हमारे खुफिया विभाग के अधिकारी शिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। चाहिए कि भारत की कभी भी यह नीति नहीं रही है कि वह अन्य देशों में खुफिया कार्यवाहियां करे परन्तु इस प्रकार की नीति पर अन्य देशों की नीति निर्धारित नहीं है इसलिए अन्य देश के खुफिया विभाग के कर्मचारी हमारे देश के खुफिया विभाग के 'गुरु' हों तो 'शिष्य' अपने 'गुरु' के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। हमारे खुफिया विभाग के कर्मचारियों को सजग और जागरूक रहना चाहिए।

आश्चर्य की बात है कि जन-गणना का शिक्षण प्राप्त करने के लिए भी हमारे भारतीय कर्मचारियों को विदेश भेजा जा रहा है। भारत आबादी के आधार पर विश्व में दूसरे दर्जे पर है और इतनी बड़ी आबादी वाले देश के कर्मचारी उन देशों में शिक्षण के लिए भेजे जाएं जहां की आबादी हमारे एक प्रदेश से भी कम हो, यह समझ में नहीं आता। भारत में गणित-शास्त्रियों की कमी नहीं है परन्तु फिर भी 'गणित विद्या' प्राप्त करने के लिए हम विदेशी शरण में जाएं यह विचित्र बात है।

हम सी० आई० ए० पर आरोप लगाते हैं :—

- कि सी० आई० ए० ने तहसील से लेकर लोक सभा स्तर तक पूरा रिकार्ड बना रखा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो राजनैतिक क्षेत्र में भाग लेता है, के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार लगभग नौ लाख व्यक्तियों की सूची तैयार है। यह काम कई वर्षों से जारी है। आखिर किसलिए ?

इस योजना के अन्तर्गत कई लोग दिन रात काम करते हैं। सी० आई० ए० इन लोगों की सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाती है। 'अमेरिकन रिपोटर', जैसी पत्रिकाओं के नाम पर प्रति वर्ष 'पते की जानकारी' के बहाने जो फार्म भेजा जाता है उसके द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस सूची के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्रमुख व्यक्ति का सम्बन्ध किस राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक संस्था से है, उन्हें अमरीकी जीवन के किस भाग में दिलचस्पी है, वे कितनी बार अमरीकी रेडियो सुनते हैं और वे 'अमेरिकन रिपोटर' से क्या चाहते हैं। जाहिरा तौर पर यह प्रश्न मामूली ढंग के हैं परन्तु इन प्रश्नों के पीछे सी० आई० ए० का दिमाग काम करता है और वह इस सूचना के आधार पर अपना जाल फैलाते हैं।

- सी० आई० ए० भावी नेताओं के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करती है। अधिक ध्यान उन लोगों की ओर दिया जाता है जो विद्यार्थी या युवक आन्दोलन में काम करते हैं। वे सोचते हैं कि विद्यार्थी समुदाय की सुगमता से खरीदा जा सकता है। पिछले दिनों उन लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने व उनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश की गई जो १९६० में देश की बागडोर हाथ में ले सकते हैं। आखिर न तो यह ज्योतिष विद्या का कयाल है न किसी दैवी शक्ति का कि एक संस्था यह जान सके कि २० वर्ष बाद कौन स्थानीय स्तर पर और कौन राष्ट्रीय स्तर पर नेता होगा? लेकिन रिसर्च विभाग में यह काम जारी है। सी० आई० ए० वर्तमान के प्रति ही चिन्तित नहीं बल्कि भविष्य के बारे में भी चिन्तित है। उसको डर है कि साम्राज्यवाद का भविष्य खतरे से खाली नहीं। साम्राज्यवाद जिस नींव पर खड़ा है वह अधिक देर तक टिकने वाली नहीं। सड़सड़ाते हुए साम्राज्यवाद को सी० आई० ए० कितनी देर तक सड़ा रख सकता है?

सूचना इकत्रित करने के बहाने किसी भी व्यक्ति को या उसकी संस्था को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह यह्यमन्त्रकारी गतिविधियों को जारी रख सके। यह्यमन्त्र यह्यमन्त्र है उसे देशी करें या विदेशी, किसी भी यह्यमन्त्रकारी को माफ नहीं किया जा सकता। यह्यमन्त्रकारियों के दाव-पेच से सावधान रहने की आवश्यकता है, उनके चेहरे का नफाब उत्तारना ही चाहिए।

- सी० आई० ए० पर यह भी गम्भीर आरोप है कि इसने विद्यार्थियों और युवकों को और उनकी संस्थाओं को पिछलभू बनाने का भी प्रयास शुरू कर रखा है। इसकी गतिविधियां यहां तक ही सीमित नहीं बल्कि मजदूरों, साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्थाओं में भी बढ़ रही हैं। यह ठीक है कि 'काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ सकती' परन्तु फिर भी सावधान रहना आवश्यक है ताकि इस कुकर्मों और कुमार्गी सी० आई० ए० को पनपने न दिया जाए।

गत कुछ वर्षों से एक नई योजना के अन्तर्गत युवकों को फसाने के लिए 'युवक शिक्षण योजना' तैयार की गई है जिसके माध्यम से युवकों को फुसलाकर विदेश भेजा जाता है ताकि वे पश्चिमी सभ्यता के प्रशंसक बनकर पश्चिमी राग-रंग में उलझ कर क्रान्तिकारी भावनाओं से विमुख हो जाएं। यह भी कोशिश की जाती है कि इन युवकों के दिमाग में यह बिठा दिया जाए कि 'पश्चिमी ढंग का प्रजातन्त्रवाद' ही उचित है।

इस योजना के बारे में भारतीय संसद में भी यदाकदा चर्चा की जा चुकी है। दिल्ली में भी इस योजना के प्रसार के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है।

- सी० आई० ए० ने सदैव फासिस्ट और साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वाली संस्थाओं की आर्थिक सहायता की है, उनको प्रोत्साहन दिया है। इसके प्रतिरिक्त सरकार विरोधी कार्यवाहियों को भी बढ़ावा दिया जाता है। धर्म के नाम पर होने वाले दंगों के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। यह संस्था विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में क्रियाशील है जो औद्योगिक क्षेत्र हों। औद्योगिक क्षेत्रों में हड़तालें कराना या दंगे कराना ही इनका काम है। कारण यह है कि यदि भारत आर्थिक तौर पर शक्तिशाली हो जाए तो पूँजीवादियों की दाल नहीं गल सकती। मजदूर वर्ग के लोगों में फूट डालने की तह में साम्राज्यवादी भावना काम करती है।

- सी० आई० ए० समाचार पत्रों और स्थानीय पत्रिकाओं को भी आर्थिक सहायता देती है ताकि इस प्रकार के प्रचार को बढ़ावा दिया जा सके जिससे समाजवाद के बढ़ते हुए चरण रुक जाएं। सी० आई० ए० जनता की शत्रु है और इसी कारण समाजवाद का भी विरोध करती है। सी० आई० ए०

की यह कोशिश रही है कि समाचार पत्रों की नीति पर डाक्टर का प्रभाव कायम रहे। लोग समाचार पत्र पढ़ें और अपने विचारों पर इसका प्रभुत्व कायम होने दें भले ही सम्पादक की लेखनी न बिक सकती हो परन्तु समाचार पत्र का मालिक, जो नीति निर्धारित करता है वह तो खरीदा जा सकता है।

हमारे देश के समाचार पत्रों ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। नई चेतना लाने में योगदान भी दिया है लेकिन कुछ वर्षों से कुछ समाचार पत्रों की नीति में परिवर्तन हुआ है। दुःख की बात है कि हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जिनकी लेखनी राष्ट्र हित के बारे में तो कम लिखती है, अमरीकी विचारों का अधिक प्रतिपादन करती है। यह हर्ष का विषय है कि काफी हद तक लेखकों और सम्पादकों ने राष्ट्रीय मान मर्यादा को ठेस नहीं लगने दी है।

यह भी देखा गया है कि व्यापार सम्बन्धी बड़े-बड़े कारखानों और मिलों में लोगों के विचारों को नया मोड़ देने के लिए पत्र-पत्रिकाओं द्वारा कोशिश जारी है। यह पत्र-पत्रिकाएं कार्यकर्ताओं में निःशुल्क बांटी जाती हैं।

सवाल रबात का हो या प्रिवीपर्स का, चुनाव केरल का हो या उत्तर प्रदेश का—इन लोगों का एक ही काम है कि लोगों में यह भावना भर दी जाए कि देश उत्पात की ओर बढ़ रहा है, निराशा चर्म सीमा पर पहुँच चुकी है, प्रजातन्त्र प्रणाली खत्म होने वाली है।

- सी० आई० ए० ने कई ऐसी संस्थाओं को भी जन्म दिया है जिनका उद्देश्य साम्राज्यवादी शक्तियों का पिछलभू बनकर यह जाहिर करना है कि जन-साधारण की तथा कथित सहानुभूति साम्राज्यवादियों के साथ है ऐसी ही एक संस्था भारत में काम कर रही है जिसका नाम 'फ्रैंड्स आफ़ ईसाईल' है इसके अतिरिक्त एक अन्य संस्था 'सोसायटी फ़ार कलचरल फ्रीडम' है जिसका सम्बन्ध न तो भाजादी से है और न ही कलचर से। इनका मुख्य उद्देश्य है कि इने-गिने व्यक्तियों को या तो फार्मूसा भेजना या इस्राईल भेजना ताकि ये व्यक्ति वापिस भारत आकर फार्मूसा और इस्राईल सरकारों की नीतियों के प्रति उचित वातावरण पैदा कर सकें। अभी कुछ दिनों से तो दिल्ली नगर की दीवारों पर दो बड़े-बड़े चित्रों वाला इस्तहार भी देखने

को मिलेगा। जिममें महात्मा गांधी के साथ-साथ च्यांग-काई शेक के चित्र हैं। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को च्यांग-काई-शेक के स्तर पर लाना देश-द्रोह है। दक्षिण कोरिया दिवस के उपलक्ष में भी इस प्रकार की प्रचार सामग्री जारी की गई थी। इस्राईल के पक्ष में भी इस प्रकार के इस्तहार लगाए गए थे। इस प्रचार द्वारा विदेश में यह प्रकट करने का प्रयास किया जाता है कि दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम और फार्मोसा की सरकार को भारतीय जनता का 'समर्थन' प्राप्त है परन्तु वास्तविकता कुछ और है। लोग जानते हैं कि विदेशी धन के आधार पर भारत की क्रांति-कारी परम्पराओं को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। भारत के लोग लाल चीन की विस्तारवादी नीति के उसने ही विरोधी हैं जितने वे साम्राज्यवादी कैम्प में पलने वाले च्यांग-काई-शेक सरकार के।

- सी० आई० ए० ने अपने कंधों पर कुछ तथा कथित संस्थाओं के कार्यालयों को चलाने का भार भी सम्भाल रखा है। शानदार भवनों में इन संस्थाओं के कार्यालय स्थित हैं, उनको देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह किसी भारतीय संस्था का कार्यालय होगा। उनकी प्रचार सामग्री को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि ये सामग्री और उस पर किए जाने वाला व्यय किसी गैर-सरकारी संस्था का हो सकता है।
- सी० आई० ए० ने भारत में तथा अन्य स्थानों पर भी प्रेस कौंसिल बना रखी है या फिर उनकी सहायता की जिम्मेदारी ले रखी है जो निरन्तर प्रचार सामग्री भेज कर यह कोशिश करती है कि भारतीय जनता को साम्राज्यवादी शक्तियों के वास्तविक रूप से अनभिज्ञ रखा जा सके। इनकी प्रचार सामग्री से जनता-विरोधी भावनाओं की झलक आती है।
- सी० आई० ए० भारत सरकार की प्रगतिशील नीतियों का विरोध करने के लिए इने-गिने व्यक्तियों को इस्तेमाल करती है। चाहे वैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न हो या प्रिवीपर्स को समाप्त करने का, सी० आई० ए० के इशारे पर इनका विरोध किया जाता है।
- सी० आई० ए० ने रबात के प्रश्न पर जो हड़दंग मचाया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बी० बी० सी० ने जिस ढंग से भारत को बदनाम करने की कोशिश की वह सोची समझी साजिश का छोटा सा रूप था। लेकिन

भाष्य की बात है कि रवात के प्रश्न को लेकर बी० बी० सी० ने जो भर कर टोका टिप्पणी की—पक्षपाती के रूप में। यहां तक ही बस नहीं, भारत की प्रतिक्रियावादी संस्थाओं ने भी उसी राग में गाना शुरू कर दिया। इन सब का उद्देश्य एक था कि भारत सरकार को बदनाम किया जाए और हिन्दुओं को उत्तेजित किया जाए। यह अलग बात है कि उन्हें सफलता न मिली और लोग जान गए कि साम्राज्यवादी एक ओर तो पान-दस्तामिजम को बढ़ावा देते हैं तो दूसरी ओर हिन्दुओं को भी भड़काते हैं ताकि दोनों लड़ पड़ें और साम्राज्यवाद सुरक्षित रह सके।

सी० आई० ए० का आर्थिक दृष्टिकोण :

सी० आई० ए० एक विशेष आर्थिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है ताकि स्वतन्त्र देशों को पुनः आर्थिक बन्धनों में जकड़ उनकी आजादी को छीना जा सके। साम्राज्यशाही पिछले के बाद एक बार फिर वापिस लौटने का प्रयत्न करती है, सीधे दरवाजे से नहीं बल्कि चोर दरवाजे से। यह ढंग सम्भवतः अब पुराना हो गया है और अब यही साम्राज्यशाही आर्थिक दरवाजे से घुसने का प्रयास करती है और आर्थिक सहायता के बहाने घुस बैठ करके इस बात की आशा करती है कि इस सहायता के उपलक्ष में उसे कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाएँ। आर्थिक घुसपैठ अधिक भयंकर और विकराल रूप धारण कर सकती है विशेषतया उस समय जब किसी देश में आर्थिक समस्या भीषण रूप धारण कर चुकी हो क्योंकि आर्थिक सहायता के साथ-साथ ऐसी जंजीरें बन्धी रहती हैं कि इन बन्धनों से छुटकारा पाना ठिन हो जाता है।

‘वैसा सब कुछ कर सकता है’ इस सिद्धान्त के आधार पर व्यक्तियों की तथा उनकी संस्थाओं की भी सहायता की जाती है। पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध रहता है और चूंकि खुफिया काम करने के लिए स्थानीय मुद्रा का ही प्रयोग हो सकता है इसलिए यह जानना कठिन होता है कि कितना धन, किसको, कब दिया गया। किन्तु कुछ संस्थाओं की ओर से इस नीति का समर्थन निःसन्देह अपेक्षणीय है। जो संस्था इस बात की चर्चा नहीं करती कि इस संस्था को मिलने वाला धन कहां से आया, निश्चय ही इस गोलमाल में हिस्सेदार है। जिस प्रकार अमरीका की नेशनल स्टुडेंट्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने यह राज खोल दिया कि उनकी संस्था को सी० आई० ए० से आर्थिक सहायता मिलती रही, इन संस्थाओं के बारे में, जिनके धन

के स्रोत का पता नहीं, जब भेद खुलेगा तो इन संस्थाओं को घाटे-दाल का भाव विदित हो जाएगा ।

१९५१ में वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की इयाका में हुई बैठक में इस संस्था से सम्बन्ध रखने वाली राष्ट्रीय समितियों से चन्दा लेने की दृष्टि से छः भागों में विभक्त किया गया । निम्नलिखित सूची से पता लग सकेगा कि किस उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी :

ए	१,००० फ्रांक	
बी	५,००० फ्रांक	भारत, पाकिस्तान और आस्ट्रिया
सी	१०,००० फ्रांक	वियतनाम, डेन्मार्क और टोगो
डी	२०,००० फ्रांक	केनेडा, नीदरलैंड
इ	५०,००० फ्रांक	ईटली, स्वीडन, टर्की
एफ	१००,००० फ्रांक	ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम

यह सूची उन देशों की है जिन्हें ऊपरलिखित राशि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ को नियमित रूप से देनी पड़ती है । परन्तु इस सूची को ऊपर से नहीं नीचे से पढ़िए । आपको कुछ आश्चर्यजनक बातें दिखाई देंगी । जहाँ ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस धनराशि प्रदान करने वालों में चोटी पर हैं, छोटा सा देश बेल्जियम भी इन देशों के साथ भारी धनराशि देने वालों की सूची में आता है । क्या इस छोटे से देश का युवक आन्दोलन इतना शक्तिशाली है कि इस धनराशि को देने की क्षमता रखता है ? इसके अतिरिक्त टर्की का दर्जा दूसरे नम्बर पर आता है जिसे ५०,००० फ्रांक देने पड़ते हैं जबकि केनेडा और नीदरलैंड जो गरीब देश नहीं हैं छोटे दर्जे में शामिल किए गए हैं । सगंड़ा वियतनाम, अज्ञात टोगो डेन्मार्क के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं और गौरवशाली आस्ट्रिया को भारत और पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया है ।

इस सूची में जिन देशों का नाम लिखा गया है वास्तव में उनसे कोई चन्दा वसूल नहीं किया जाता । धनराशि तो अन्य स्रोतों से मिलती है । सूची तो केवल दिखावा मात्र है वरना कहां टोगो और कहां अमरीका ? कागजों में नाम दक्षिण वियतनाम का लिखा जाता है, पैसा अमरीका देता है और बड़ी शान के साथ कोषाध्यक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहता है कि इन राष्ट्रों से पर्याप्त सहायता मिलती रही है और दूसरे ही क्षण में इस बात को स्वीकार कर लेता है कि राष्ट्रीय

समितिया अपना चन्दा भ्रष्टा नहीं करतीं। एक ही जुबान से दो प्रतिकूल बातें।
वाह रे अन्तर्राष्ट्रीय संस्था केरा, कमाल !

यह तो स्पष्ट है कि सच्चकोटि के दान वीरो में चार ही देशों का नाम लिखा गया है और उन्हीं से पंसा वसूल किया जाता है, वही संस्था के व्यय को पूरा करते हैं और इन्हीं चार देशों को अत्यति अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अधिक धन देने के उपलक्ष में वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की नीति भी निर्धारित करें। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऊपरलिखित सूची राजनैतिक दृष्टिकोण से तैयार की गई है क्योंकि 'जैसा होगा धन, वैसा होगा मन'।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के यात्रा कोष की ६० प्रतिशत धनराशि फ्रांज़ेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज भ्रष्टा करती है जिसको मिलने वाली धनराशि के स्रोतों के बारे में पीछे चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थाओं को अधिकांश धनराशि एशिया फ्रांज़ेशन से प्राप्त होती है। यही संस्था विशालकाय भवनो का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि भी देती है। इस प्रकार मिली हुई धन राशि से बने हुए विशालकाय भवन पड़्यन्त्रकारी गतिविधियों का केन्द्र बन जाते हैं।

अधिकांश संस्थान घेनामी हैं और सी० आई० ए० इन संस्थानों को अपनी कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में लाती है। इन संस्थानों के माध्यम से अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने का कार्य किया जाता है सी० आई० ए० के कार्यालय का काम विभिन्न विभागों में विभक्त है प्रत्येक विभाग का मुखिया अपने विभाग की देख रेख करता है। एशियाई विभाग और अफ्रीकी विभाग विशेष ध्यान के पात्र हैं क्योंकि अफ्रीकी एशियाई देशों में साम्राज्यवाद की जड़ें खोलनी हो चुकी हैं और इन देशों के लोग अपने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर हैं।

१९५६ तक दक्षिण-पूर्व-एशियाई कार्यालय नई दिल्ली में स्थित था और एक बंगाली सज्जन इस कार्यालय के प्रमुख थे। इन्होंने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह तो केवल एक व्यापारी है परन्तु वास्तव में यही व्यक्ति 'साम्यवाद का विरोध' करने के लिए 'बड़े व्यापार' को कई वर्षों तक चलाता रहा। उसकी देख रेख में बुद्धिमान काम करने वालों का जाल बिछाया गया। उनके रहन-सहन, खान-

पान और शान व शौकत को देखकर कोई भी व्यक्ति भूले से भी यह शक नहीं कर सकता था कि यही महोदय व्यापारी नहीं बल्कि 'बड़े व्यापारी' के दलाल के रूप में लोगों के स्वाभिमान का सौदा किया करते थे। यह अलग बात है कि उन्हें सफलता न मिली परन्तु उसकी कार्यवाहिया निन्दनीय थीं।

भाज सी० आई० ए० की गतिविधियों में कोई आमूल परिवर्तन नहीं है। वही है चाल बेढगी, जो पहले थी वह अब भी है। अन्तर केवल यह है कि अब लोग सी० आई० ए० की गतिविधियों से परिचित हो चुके हैं। सी० आई० ए० पहले की भांति अब भी उन देशों की खोज में रहती है जहाँ गड़बड़ मचाई जा सके और जहाँ सी० आई० ए० को थोड़ी सी भी सहायता प्राप्त हो सकती हो। जहाँ-जहाँ विद्यलभू सरकारें कायम हैं वहाँ सी० आई० ए० को अपनी कमीनी चालों में थोड़ी सी सफलता अवश्य प्राप्त होती है परन्तु अधिकांश देशों में लोगों के बढ़ते साहसिक कदमों के भागे सी० आई० ए० की चालें नाकाम रही हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विरुद्ध रेडियो एवं समाचार पत्रों द्वारा झूठा प्रचार किया जाता है, विभिन्न राजनैतिक दलों के माध्यम से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की सरकारों पर दबाव डाला जाता है कि वे एंग्लो-अमरीकन गुट में शामिल हो जाएं। वह यह भी झूठा प्रचार करते हैं कि यदि भारत एंग्लो-अमरीकन गुट में शामिल हो गया होता तो चीन भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता था। सदा इस बात का प्रयास किया जाता है कि प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखने वाले देशों की शक्ति को क्षीण किया जा सके। हर प्रकार की हरकतें की जाती हैं ताकि पड़ोसकारि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सी० आई० ए० सरकार के अन्तर्गत एक अन्य सरकार है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में निर्णय करती है कि किस देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किसके साथ कैसे हों? इस प्रकार आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाता है और उल्ट फेर की भूमिका भदा की जाती है।

१३ मई १९६६ को केन्द्रीय गृह मन्त्री ने भारतीय लोक सभा में कहा था कि भारत सरकार कानून द्वारा इस बात पर रोक लगाना चाहती है कि भारत में किसी भी सस्या को विदेशी संस्थाओं से आर्थिक सहायता न मिल सके। गृह मन्त्री विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय संस्थाओं को मिल रही आर्थिक सहायता के बारे में चर्चा कर रहे थे। सभा में इस बात की मांग की गई थी कि खुफिया विभाग की १९६७ और १९६८ की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। गृह मन्त्री ने बताया कि किन कारणों से खुफिया विभाग द्वारा की गई जांच पड़ताल को आम जनता के

सन्मुख नहीं रखा जा रहा । आपने बताया कि खुफिया विभाग किन्हीं कारणों से खुली जांच न कर सका है और न ही गवाहियां इत्यादि ली गई हैं परन्तु इस विभाग की जांच का आधार वे सूचनाएं हैं जो उन्हें प्राप्त हुई थी ।

केन्द्रीय गृह मन्त्री ने कहा कि व्यक्तियों या उनकी संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता का विषय चिन्ताजनक है । ये संस्थाएं चाहे राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करती हों या साहित्यिक क्षेत्र में । यद्यपि निश्चित रूप में यह जानकारी प्राप्त न हो सकी है कि इस प्रकार किस संस्था को कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई परन्तु ऐसा लगता है कि इस प्रकार दी जाने वाली सहायता न तो अधिक मात्रा में थी और न ही इतनी कम कि इसकी ओर ध्यान न दिया जाए । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि गत आम चुनाव में विदेशी धन का प्रयोग किया गया था । चुनाव के समय विदेशी धन पानी की तरह बहाया जाता रहा है और इस बात की कोशिश की जाती रही है कि प्रगतिशील विचार रखने वाले लोगों को हराने के लिए विपक्षी दलों की पूरे तौर पर सहायता की जाए । पिछले आम चुनाव में तो सी० आई० ए० ने ही निर्णय लिया था कि किस प्रगतिशील व्यक्ति का विरोध कीन करेगा और इस प्रकार उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इने-गिने नेताओं के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मोर्चा लगाया जाए । अमरीकी साम्राज्यवादियों ने हमेशा कृष्णा मेनन का विरोध किया है । हारे हुए जुमारी की भांति साम्राज्यवादी हमेशा इस ताक में रहे हैं कि कोई न कोई मौका हाथ में जरूर लगे जिससे प्रगतिशील नीतियों को उखाड़ फेंका जा सके ।

केन्द्रीय गृह मन्त्री ने यह भी बताया कि विदेशी समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा भारतीय खुफिया विभाग की सूचना के अनुसार ऐसा विदित होता है कि सी० आई० ए० की हिदायत पर कुछ संस्थाओं को 'शोध' के लिए तथा 'शिक्षा के विस्तार' के लिए आर्थिक सहायता मिलती रही है । हो सकता है कि इन संस्थाओं को इस बात का ज्ञान न हो कि इस प्रकार मिलने वाली आर्थिक सहायता या छात्र वृत्ति या यात्रा व्यय के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता न तो शोध कार्य के लिए है और न ही शिक्षा के विस्तार के लिए अपितु इस देश में इन कार्यवाहियों के माध्यम से अमरीकी गुप्तचर संस्था की गतिविधियों को बढ़ावा देना है ।

इसी कारण भारत सरकार ने एशिया फ्राऊडेशन को आदेश दिया है कि वह भारत से अपना ताम-तोबड़ा उठा कर से जाए । सरकार ने यह आश्वासन भी

संसद में दिया है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न कोई अन्य संस्था भारत में दिखाई दी तो उसे भी अपना काम-धाम बन्द करना पड़ेगा। गृह मन्त्री ने संसद में चर्चा करते हुए कहा कि संसद सदस्यों को इस समस्या पर विचार करना चाहिए ताकि भारत की धरती पर पड़यन्त्रकारी गतिविधियां पनप ॥ सकें। आपने कहा कि अपरोक्ष रूप में मिलने वाली राशि, पुस्तकों पर कमीशन के रूप में, या व्यापारिक सौदों से आर्थिक दलाली के रूप में, या विज्ञापन दरो की बढ़ाकर या अनुवाद कार्य के लिए भारी रकम द्वारा दी जाती है। इस प्रकार मिलने वाले धन पर न तो किसी को डाक हो सकता है और न ही एतराज परन्तु इस प्रकार इन संस्थाओं को या व्यक्तियों को काफ़ी धनराशि सहज में ही पदान की जाती है।

यह भी देखने में आया है कि इन व्यक्तियों के नाम पर विदेशों में अवैध तरीकों से धन भी भेजा जाता है और इस काम में विदेशी बैंकों, विदेशी कम्पनियों और विदेशी लोगों की सहायता भी जाती है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं कि जिनका काम सिवाए सौदे बाज़ी के और कुछ नहीं है। उनका काम तो दलाली करना है, कभी वे राजाओं के दनाल बन जाएंगे तो कभी राजबादा दाही के। कभी बैंको के राष्ट्रीयकरण का विरोध करके बैंकरो की चापसूसी करेंगे तो कभी काला धन कमाने वालों के एजेंट बन जाएंगे। इन लोगों का दीन-ईमान पैसा है। वह तो ऐसे लोग हैं जिन्हें 'चाम भी प्यारा है और दाम भी'। अगर किसी मनुष्य का चाम बेच सकते हों तो सहर्ष बेच देंगे। देश की मान मर्यादा का सौदा करना ही तो वह भी करने को तैयार रहेंगे। ऐसे लोग समाज के लिए हानिकार होते हैं, वे कभी भी देश-द्रोह कर सकते हैं। मानवता उन्हें छू भी नहीं सकती, उनके लिए सब मर्यादाएं कुण्ठित हो चुकी हैं।

इस प्रकार की स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे समाज-विरोधी तत्वों से सावधान रहा जाए ताकि वे लोग हमारे देश को घुन की तरह खा न जाए। कुछ लोग भले ही गोरी जमड़ी देखकर उन लोगों के विरुद्ध आवाज न उठाएं परन्तु जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है वह अवश्य ही इन देश-द्रोहियों का विरोध करेगा। सेद का विषय है कि जब हमारे देश में हमारे भाई ही विदेशी सत्ता या धन्ना सैठों के हाथ में बिक जाएं, तो चायद कुछ लोग निराशा अनुभव करने लगते हैं। परन्तु उन्हें विदित होना चाहिए कि कुछ इने-गिने लोग अपनी गलत कार्यवाहियों से थोड़े समय के लिए हानि तो पहुँचा सकते हैं। परन्तु ऐसे लोग अधिक देर टिक नहीं सकते। यही कारण है कि जिन-जिन स्थानों पर सी० भाई०

ए० ने लोगों को या उनकी संस्थाओं को खरीदना चाहा वहां प्रारम्भ -में तो उन्हें अवश्य सफलता मिली परन्तु जनता ने जब करवट ली तो इन संस्थाओं का अस्तित्व मिट गया । लोगों ने जन-भावनाओं का विरोध करने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार अलग कर दिया मानो दूध और पानी अलग-अलग कर दिया गया है । जनता से अलग-अलग रहने वाले चेहरे भी ज़रा देखें कि वे किस रंग में और कहा रहते हैं ?

नया रूप, पुरानी चालें

दुनिया के लोग बड़ी तेजी के साथ छलागे मारते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को नई दिशा प्रदान की जा चुकी है। संसार का मानचित्र जो दस वर्ष पहले था वह अब वैसा नहीं है। नए राष्ट्रों का जन्म हुआ है, उन्होंने आजादी की सांस ली है। सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद कई राष्ट्रों ने फिर भंगड़ाई ली है। साम्राज्यवादियों ने दमन की नीति अपनाई, राष्ट्रवादियों ने उसे भी सहन किया। अपने जीवन की आहुति देने वालों ने फांसी के फन्दे की धूमा परन्तु उफ न की, गोलियों से शरीर छलनी हो गया लेकिन आह न निकली, और जेल की काल कोठरियों में तिल-तिल कर बलिदान देने वालों ने अदम्य उत्साह का परिचय दिया। बार-बार उनके मुख से यह आवाज निकली 'तुम तीर आज़माओ हम ज़िगर आज़माएँ'। परिणाम यह निकला कि जनता की अपार शक्ति के आगे साम्राज्यवादी टिक न सके। एक-एक करके राष्ट्र आजाद होते गए। विश्व के इतिहास की रूप रेखा बदल दी गई। नया इतिहास लिखा जाने लगा। प्रजातान्त्रिक देशों में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ।

साम्राज्यवादी तिलमिलाने लगे। उनकी नींवें शिथिल हो गईं। परिवर्तन अवश्य भावी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, न धन में इतनी शक्ति है न हथियारों में कि बढ़ते हुए कदमों को रोक सकें। इस समय दुनिया में ४४ देश ऐसे हैं जो अभी तक साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्ति प्राप्त न कर सकें हैं। कुल मिला कर लगभग २८ करोड़ लोग दुनिया में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें से काफी देश ऐसे हैं जो गोराम्राहों के शिकार हैं जहां पर काली चमड़ी वाले लोगों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन देशों में न जनता के साथ समान व्यव-

हार किया जाता है न उन्हें किसी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इन देशों में प्रमुख हैं दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी रोडेशिया, जाम्बिया (दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका) पुर्तगाली तानाशाही के अधीन अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी इत्यादि। इन देशों में काली नस्ल वालों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। इन देशों के अतिरिक्त ३६ देश ऐसे भी हैं जहां उन लोगों को अभी तक गुलामी का दौर देखना पड़ रहा है। यद्यपि समुक्त राष्ट्र सघ ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने की बराबर मांग की है परन्तु उन वर्तमान शासकों के काम पर जूँ तक नहीं रेंगी है। साम्राज्यवादी शासकों में न केवल पुर्तगाल बल्कि आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और अमरीका भी शामिल हैं।

इस प्रकार अभ्य देशों को गुलाम रखने की नीति के पीछे साम्राज्यवादियों की एक गहरी चाल है। वे चाहते हैं कि इन देशों के खनिज पदार्थों का शोषण किया जाए और वह धरती जो सोना उगलती है उसे खीरान कर दिया जाए या फिर इस प्रकार उत्पन्न होने वाली कीमती धातुओं को कोडी के मूल्य खरीद कर उस देश को भिखारी बना दिया जाए। आर्थिक गुलामी के बन्धनों में इन देशों को जकड़ने के पश्चात् उन्हें राजनैतिक व सामाजिक तौर पर अपाहिज बनाने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।

कांगो में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की गई थी। कांगो पश्चिमी तट से पूर्व तक और भूमध्य रेखा से रोडेशिया तक फैला हुआ एक ऐसा देश है जिसकी अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण इसे अफ्रीका में एक महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है। इस देश से अफ्रीका की राजनैतिक स्थिति पर भी प्रभाव डालना सम्भव है। इस देश के प्राकृतिक साधन किसी देश से कम नहीं हैं। तेल-खजूर और रबड़ के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस देश में हीरे भी मिलते हैं और सोना भी। १९५६ में दुनिया में हीरे की पैदावार का ६६% भाग कांगो में हुआ था। केवल खनिज पदार्थों के निर्यात से १०० लाख पौंड की आमदन हुई थी। १९५८ तक कांगो के लोगों को बेल्जियम सरकार ने अपने अंकुश के नीचे दबाए रखा। कारणवश जनता राजनैतिक विचार-प्रवाह से अलग रही परन्तु जब राष्ट्रवादी नेता पेट्रिक लुमुम्बा ने आल-अफ्रीकन पीपुल्स काफ्रेस जो घाकरा में हुई के अन्दर अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए जब साम्राज्यवादियों को चेतावनी दी कि कांगो को अधिक देर गुलाम नहीं रखा जा सकता तो साम्राज्यवादी कैम्प में खलबली मच गई। परन्तु विजय राष्ट्रवादियों की हुई। ३० जून '६० को राष्ट्रीय सरकार बनी पेट्रिक लुमुम्बा

उसके प्रधान मन्त्री बने और कामावूवू राष्ट्रपति । ११ जुलाई १९६० को काटंगा ने कांगो से अलग होने का एलान कर दिया । इस एलान के पीछे बेल्जियम सरकार का हाथ था क्योंकि वह लुमुम्बा से नाराज थी और उसे कांगो की आजादी एक भ्रांख भी न भाती थी । जब देश में अलगाव पसन्दी शक्तियां उठ खड़ी हुईं तो उस समय लुमुम्बा ने सोवियत रूस से सहायता ली । बस क्या था साम्राज्यवादियों ने बौखला कर कामावूवू को इस बात पर राजी कर लिया कि वह लुमुम्बा को प्रधान मन्त्री पद से हटा दे । लुमुम्बा ने इसका विरोध किया और जब वह लियोपोल्डविला से स्टानलेविला जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । आजादी का अमर सेनानी जेल की बान कोठड़ी में बन्द रखा गया और कुछ दिनों पश्चात लुमुम्बा की निर्मम हत्या कर दी गई । यह हत्या मानवता के माथे पर सदा के लिए कलुषित दाग बन गई । लुमुम्बा की हत्या के पीछे सी० आई० ए० का पड्यन्त्र था । इसकी तह में डलेस भी नीति काम कर रही थी । लुमुम्बा चले गए, उनकी आत्मा अब भी कांगो में निवास करती है । वह आज भी राष्ट्रवादियों को प्रेरणा देती है कि साम्राज्यवादी हथकण्डों से सावधान रहो । साम्राज्यवादी पिशाच हैं, मानवता के शत्रु हैं और उपनिवेशवाद के समर्थक ।

सी० आई० ए० की गतिविधियों पर प्रकाश डालते समय हमारे सामने यह प्रश्न था कि 'अन्धे को अन्धा कहना' चाहिये या नहीं । क्योंकि निश्चय ही उन लोगों की आंखों में 'सी० आई० ए० का पर्दाफाश करना' अखरेगा जिनको डर है कि सजग और जागरूक जनता कहीं उनके पड्यन्त्रकारी अन्धे पर सात न मार दे । यह भी ठीक है कि सैकड़ों साम्राज्यवादी दलालों का काम ठप्प हो जाएगा, साम्राज्यवादी की जड़ें खोखली हो जाएंगी परन्तु यह भी सही है कि लाखों इन्सानों को शोषण से मुक्ति मिलेगी क्योंकि सी० आई० ए० शोषक टोले का साथ देता है ।

अभी कुछ दिन हुए जार्डन में फलस्तीनी कमाण्डो और शाह हुसैन की सेनाओं के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई । एक ओर साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियां खड़ी थी तो दूसरी ओर लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद को सहारा देने वाली शक्तियां । एक को जनता का समर्थन प्राप्त था तो दूसरे को शाही दरबार का, लेकिन यह भी प्रमाणित हो गया कि अरब देशों में जन-जन की भावनाओं की अवहेलना करके साम्राज्यशाही संगीन की नोकों से अपना राज्य कायम नहीं रख सकती । अरब देशों में देशभक्ति की भावनाओं के सामने एक या दो राष्ट्र दीवार बनकर खड़े नहीं हो सकते । यदि जार्डन के शाह हुसैन यह समझते हों कि विदेशी गोला-बारूद और

हवाई जहाजों से अरब देशों में अरब-राष्ट्रीयता-विरोधी नीति अपना कर वह अपना दमन-चक्र जारी रख सकते हैं तो यह उनकी भूल है। अमरीकी साम्राज्यवाद का ताना-बाना अफ्रीका के कुछ देशों में भी मिलेगा और एशिया के कुछ भागों में भी। जहाँ जहाँ शोषण की गुंजायश हो सकती है—साम्राज्यवाद के लिए पाय जमाना सरल हो जाता है। अरब देशों पर साम्राज्यवादियों की कोप दृष्टि इसलिए भी रही है कि नए आर्थिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत मरुस्थल उर्वरा धरती में बदला जा चुका है। जिस रेगिस्तान में लोग पानी की तरसते थे वहाँ नई-नई योजनाओं से पानी की कमी को दूर किया जा चुका है। रेतीली धरती का कण-कण सुनहला रूप धारण कर चुका है। अरब देश मिलाकर यदि अमरीका जैसे साम्राज्यवादी देशों को तेल देना बन्द कर दें तो वाशिंगटन की मिलें बन्द हो सकती हैं, कारखानों में बिजनीयों की रोक खत्म हो सकती है, विमान उड़ नहीं सकते, लगभग आधा कारोबार ठप्प हो सकता है। यही कारण है कि अरब देशों में साम्राज्यवादी हठकण्डे अपनाए जाते हैं ताकि तेल का शोषण होता रहे और अरब देशों की आर्थिक व्यवस्था आत्म-निर्भर न हो सके।

साम्राज्यवादियों को न यहूदियों से सहानुभूति है न ईसाइयों से, न इसे हिन्दू से प्यार है न मुसलमान से। मुसलमान की मस्जिद ध्वस्त हो जाए या हिन्दू का मन्दिर गिर जाए तो साम्राज्यवादियों की आंख से आसू नहीं टपकेंगे परन्तु उनकी बाहे खुल जाएगी कि जब हिन्दू को मुसलमान से लड़ाना आसान हो जाएगा। यदि अमरीका, ब्रिटेन या फ्रांस को हिटलर के जुल्म से तंग आने वाले यहूदियों के साथ हमदर्दी थी तो उन्होंने अमरीका, ब्रिटेन या फ्रांस में ही यहूदियों के लिए अलग 'होमलैंड' क्यों न बना दिया। किसी भी शरणार्थी को दूसरे के घर में बसाने का उपदेश तो हर कोई दे सकता है परन्तु मजा तो तब है जब उसे अपने घर में स्थान दे। यदि यहूदियों का पुनर्निवास अमरीका में हो गया होता और फिर इन्हीं यहूदियों ने अमरीकियों को निकालकर स्वयं उस भाग पर अधिकार कर लिया होता तो अमरीका को आटे-दात का भाव मालूम हो जाता। अगर निक्सन के परिवार के किसी भी व्यक्ति को उसके घर से उखाड़ा गया होता तो उन्हें विदित होता कि निष्कासित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब क्या है? परन्तु खेद तो इस बात का है कि चतुराई के साथ 'वल्फोर डेक्लेरेशन' के आधीन साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अरब की धरती पर यहूदियों को इसलिए आबाद कर दिया कि ये लोग साम्राज्यवादियों के पिछलग्गू बने रहेंगे। यहूदी विद्वानों के किस कोने में नहीं रहते

और यदि हर देश में यहूदी यह माग करनी शुरू कर दें कि उन्हें प्रलग 'होमलैंड' दिया जाए तो देशभक्तों की क्या प्रतिक्रिया होगी। खेद का विषय है कि फलस्तीन के स्वाल पर साम्राज्यवादी इसे विकृत रूप देते रहे हैं। भारत में यह प्रचार किया जाता रहा है कि 'अरब' देश तो 'मुस्लिम देश' हैं हमें इनका समर्थन नहीं करना चाहिये। इस ढंग का प्रचार भ्रमात्मक है क्योंकि हमारी नज़रों में साम्राज्यवादी तो साम्राज्यवादी है—न वह हिन्दु है न मुसलमान, न वह यहूदी है न ईसाई—उसका काम तो केवल लोगों को आपस में लड़ना है। दो गडोसी राष्ट्र भिड़ने लगे तो साम्राज्यवादियों के चेहरे खिल उठते हैं क्योंकि जग का मामान बिकेगा, मानवता का सौदा होगा, सम्यता का दिवाला निकलेगा, बच्चे यतीम होंगे, बहिनों का सिन्दूर गोंदा जाएगा, माताओं की गोद खाली होगी, शोषण बढ़ेगा, गरीबी का दौर-दौरा होगा, लोग भूख से विह्वल होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक ढांचा अस्त-व्यस्त होगा और फिर चालाक दुकानदार की भांति अमरीका दल-बल के साथ, डालर के खौर पर उस देश में घुम जाएगा और उसे कंगाल बना कर भिख मर्गों की कतार में हमेशा के लिए बिठा देगा।

प्रत्येक देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका काम प्रगतिशील नीतियों का विरोध करना है। भारत में भी ऐसे लोगों की यही मनोवृत्ति है कि सरकार की प्रगतिशील नीतियों का विरोध किया जाए। जब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने सरकार की खिल्ली उड़ाई और जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो इन लोगों ने अदामत का दरवाजा भी खटखटाया। यह वही लोग हैं जो इन्दिरा गांधी को कम्युनिस्ट और कृष्णा मेनन को साम्यवादियों का समर्थक कहते हैं और जितने भी प्रगतिशील निदर्शी व्यक्ति हैं उन्हें साम्यवाद का प्रशंसक और युवा तुकों को साम्यवादी धुसपंठिया कहते हैं। जब जनता जायदाद पर सीमा लगाने की माग करती है तो ये लोग इस प्रकार झूठा प्रचार करते हैं कि जन साधारण के मन में यह बात बिठा दी जाए कि जायदाद पर सीमा निर्धारित होने का मतलब होगा कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति को भी अपनी मामूली जायदाद ॥ हाथ धोना पड़ेगा।

इस प्रचार शैली के पीछे एकाधिपतियों, पूँजीपतियों और निज कारोबार के लिए विदेशी पूँजी का सहयोग प्राप्त करने वालों का हाथ है और इन सब के पीछे विद्यमान है—सी० आई० ए०। सी० आई० ए० एक फासिस्ट संस्था है और यह वंक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों में मानसिक गुलामी के बीज आरोपन करने

का काम भी करती है। सी० आई० ए० की किसी भी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। धरव देशों में यह यहूदी का रूप धारण करती है और भारत-पाक महाद्वीप में मुसलमान का, दक्षिण अफ्रीका में यह गोरे का साथ देती है तो परतन्त्र अफ्रीकी देशों में काले का। यह मस्जिद भी गिरा सकती है और मन्दिर भी। इसका काम है लोगों में फूट डालना, लोगों के घर जलवाना, निरीह वच्चों को कत्ल करना, मानवता की हत्या करना।

सी० आई० ए० सर्व प्रथम किसी देश में फूट डालने का काम करती है और फिर 'एकता' लाने का और जब एकता के लिए वार्ता शुरू हो जाए तो उस वार्ता को विफल बनाने का काम भी करती है। जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस गम्भीर स्थिति से गुजर रही थी तो सी० आई० ए० के दलाल संसदीय कार्यालय के बाहर चक्कर काट रहे थे। उनके लिए 'राजनैतिक कमाई' का सब से सुन्दर मौका था। सी० आई० ए० ने एक नया धन्धा भी शुरू कर रखा है। यह विदेशी सरकारों की दलाली का काम भी करती है चाहे 'कोयले की दलाली में मुंह काला क्यों न हो जाए'। यह बहाना बनाने में निपुण भी है और क्रियात्मक कार्यों की भाड़ में धोके बाजी में चतुर भी।

जब जनता वर्तमान के प्रति चिन्तित होगी तो सी० आई० ए० वाले भूतकाल की बात करेंगे। लोग रोट्टी के लिए संघर्ष कर रहे हों तो ये उनका मन बहलाने के लिए 'सोता और मैना की' कहानी सुनाएंगे। जनता की विद्रोही भावनाओं को कुपिष्ट करने के लिए उन्हें नाच गाने के लिए आमन्त्रित करेंगे। इनकी यही इच्छा होगी कि लोग समाजवादी विचार धारा के समर्थक न बन कर 'उग्र राष्ट्रवादिता' के पुजारी बन जाएं ताकि धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करके उन्हें साम्प्रदायिकता की भट्टी में भोंका जा सके।

इनकी मित्रता किनसे है ? जनता से—नहीं ! परन्तु इनकी मित्रता है :—

- क) भारतीय और विदेशी एकाधिपत्य वालों से।
- ख) शोषकों से।
- ग) फासिस्टों और उनकी संस्थाओं से।

ताकि लोग गरीबी से छुटकारा न पा सकें। उन्हें डर है कि जब देश आत्म-निर्भर हो जाएगा तो एकाधिकार की रक्षा नहीं की जा सकेगी। जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग और जागरूक हो जाएगी।

यही कारण है कि एक ही पैली के चट्टे—बट्टे साम्राज्यवाद के साये में पलते रहते हैं। सी० आई० ए० के पास हर बिमारी का इलाज मौजूद है या यूँ कह लीजिए कि टोटे हैं, सब के सब एक दम पेटेंट :

क) यदि कोई व्यक्ति प्रगतिशील हो तो उसे साम्यवादी कहो या साम्यवाद का समर्थक या वाम पथी ।

ख) यदि लोग समाजवाद की बात करें तो उन्हें उग्र राष्ट्रवादिता के चक्र में डाल दो ।

ग) यदि मेहनतकश जनता अपने अधिकारों के लिए लड़े तो पूँजीपतियों की मदद करो ।

घ) यदि बेरोजगार रोजगार की माग करें तो अपने कारखानों को ताले लगा दो ।

ङ) यदि बोनस का प्रश्न उठे तो कारखाने में ताता बन्दी करके स्वयं वहाँ से चले जाओ ।

सी० आई० ए० को विश्वास है कि उसे निम्नलिखित लोगों से सहायता मिल सकती है :

क) लाल फीताशाही से ।

ख) नौजवानों से ।

ग) राजनैतिक गुटों से ।

घ) विद्यार्थियों से ।

ङ) वैज्ञानिकों से ।

सरकारी भेद को प्राप्त करने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए, प्रजातांत्रिक सरकारों का सत्ता उलटने के लिए, पड्यन्त्र की भूमिका तैयार करने के लिए सी० आई० ए० उपयोगी सुचना प्राप्त करने का भी काम करती है ताकि उसे प्रयोग में लाया जा सके :—

क) व्यवसायिक राज वेचने के लिए ।

ख) सैनिक क्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए ।

ग) तस्करी के लिए ।

और अपने इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित ढंग अपनाए जाते हैं :—

क) आर्थिक हस्तक्षेप द्वारा ।

ख) राजनैतिक घुस पंथ द्वारा ।

ग) धार्मिक भावनाओं को उद्धेलित करके ।

जिस प्रकार मृत्यु का निवास-स्थान युद्ध, विष और विमारी है उसी प्रकार सी० आई० ए० विध्वंसक कार्यवाहियों की गोद में पलता है इसलिए इस घुस पंथ को रोकने के लिए सब राजनैतिक और सामाजिक दरवाजे बन्द होने चाहिए ।

अमरीकी लोग, आम तौर पर, सी० आई० ए० की गतिविधियों के कट्टर विरोधी हैं । सी० आई० ए० तो अपने देश अमरीका की भी बफादार नहीं है इसे अपने देश में भ्रष्ट समझा जाता है । भला कौन सजग व्यक्ति चोरो और लुटेरो का साथ देगा । ये लोग साम्राज्यवाद-विरोधी देशों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं ।

अधिकांश अमरीकी लोग समुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति के कट्टर विरोधी हैं । इन लोगों को विश्वास है कि सी० आई० ए० ने ही दुनिया में अमरीका का हलिया बिगाड़ रखा है और आजका अमरीका जनता का हितैषी नहीं बल्कि उनका शत्रु है । साम्राज्यवादी अमरीका अब्राहम लिंकन और जेफरसन को भूल चुका है । जो कुछ इन महान विभूतियों ने अमरीका के लिए किया, उन्हीं की सन्तान ने उस पर कालिल पोत दी । जेफरसन आजादी के लिए लड़े, लिंकन रंग-भेद के खिलाफ लड़े परन्तु अमरीका रंग-भेद नीति का समर्थन करने वाले दक्षिण रोडेशिया का भी मित्र है और दक्षिण अफ्रीका का भी, इसकी मित्रता पुर्तगाल और ग्रीस की तानाशाही सरकारों से भी है जिन्होंने अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी बिसाऊ में आजादी का दमन कर रखा है । यह गरीबी से सताए हुए छोटे-छोटे राष्ट्रों पर आक्रमण भी कराता है और अर्ध-विकसित देशों में आर्थिक शोषण के बीज भी बोता है ताकि साम्राज्यवादी हत्यारणों को सफल बनाया जा सके ।

यह असम्भव है कि कोई भी व्यक्ति जो खुफिया विभाग में काम करता हो वह अपना सम्पर्क इस विभाग के साथ दिखाने का एलान करता रहे। खुफिया काम तो खुफिया ढंग से किए जाते हैं और वे लोग जो यह कार्य करते हैं उनका रग-ढग बदल नहीं जाता, केवल वे लोम पैसे के लालच में अपना ईमान बेच देते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो काम वह कर रहे हैं वह उनके अपने देश के लिए महत्त्वपूर्ण है। खुफिया विभाग तो देश की रक्षा के लिए बनाया जाता है और जो खुफिया विभाग विदेशी सत्ता के इशारे पर काम करता हो वह निश्चय ही निन्दनीय है। अतः यह जनता का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों से और उनकी संस्थाओं से सतर्क रहें तथा उनकी षडयन्त्रकारी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। यह प्रजातन्त्र के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा यदि हम विध्वंसकारी, आतंकवादी और हिंसात्मक कार्य-वाहियों को बढ़ावा देने वाली राष्ट्र-विरोधी संस्थाओं को पनपने दें। किसी भी देश को अपनी आजादी की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है इसलिए कोई भी देश अपने आस्तीन में साप नहीं पाल सकता। साम्राज्यवाद का पिछलमू सी० आई० ए० भी एक विषैला साप है जो नृशंसात्मक कार्यवाहियों के लिए बदमाश है।

आजादी का यह मतलब नहीं कि कुछ लोगों को अधिकार है कि वे इसका गलत इस्तेमाल करते हुए आजादी का हनन करना शुरू कर दें। इस प्रकार की आजादी पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए और यदि सरकार इतना कड़ा कदम उठाने में असमर्थ हो तो जनता को चाहिए कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों के मुंह में लगाम दे। इससे पहले कि षडयन्त्रकारी गतिविधियां विकराल रूप धारण कर लें, प्रत्येक देश वासी को इस बात का निश्चय करना चाहिए कि वे लोग जो आजादी का दमन करने का प्रयास करते हैं उनके साथ लोहा लिया जाएगा।

यदि प्रजातन्त्र की धक्का लगता है तो आजादी को ठेस लगती है। इसलिए हम प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रशंसक ही नहीं उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि स्वावलम्बी राष्ट्र आर्थिक गुलामी की जजीरों में जकड़ दिए जाएं नहीं तो हमारी अवस्था उस चिकित्सक के समान होगी जो कहेगा "आपरेशन तो कामयाब रहा परन्तु रोगी की मृत्यु हो गई।"

अन्त में हम उन लोगों से अनुरोध करते हैं, उनकी कार्य करने की शक्ति को आह्वान देते हैं, उनकी आजादी, प्रजातन्त्र और शान्ति के प्रति भावनाओं को चुनौती

देते हैं, कि वे सजग और जागरूक रहें क्योंकि सी० आई० ए० का अस्तित्व में आजादी के लिए खतरा है।

सी० आई० ए० की कुख्यात गतिविधियों की चर्चा करते हुए पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति अय्यूब खा ने आरोप लगाया है कि उसकी सरकार का तख्ता उलटने में सी० आई० ए० का हाथ था। 'सुबह का भूला शाम को घर लौट प्राए' तो उसे भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। अच्छा है कि अय्यूब खा जल्दी समझ गए। पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की हत्या के पीछे भी पडयन्त्रकारी भावना काम कर रही थी परन्तु उस समय शासक वर्ग 'मिट्टी के माघो' बनकर सारा तमाशा अपनी आँखों से देखते रहे। पाकिस्तान में अब भी फौजी शासन है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान को अमरीकी साम्राज्यवादी भी इस्तेमाल करेंगे और चीनी विस्तारवादी भी। सी० आई० ए० के पर्दे के पीछे कौन किसके साथ गठ बन्धन करता है इसके प्रति सजग रहना आवश्यक है। एशिया और अफ्रीका की धरती उपद्रवों और उत्पातों से मुक्त रहे इसके लिए आवश्यक है कि सी० आई० ए० के चेहरे पर पड़ा हुआ नकली नकाब उतरता रहे। उसमें आप सब का सहयोग अनिवार्य है।

सी० आई० ए० आजादी की शत्रु है। इसका जनाजा उस स्थान पर जाकर दफना दो जहाँ इसकी मौत पर आसू बहाने वाला कोई न हो।

